अगस्त - 2024 वर्ष -7 अंक 8

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

आमंत्रण मूल्य
50/-

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। मीडिया जगत, विशेषकर समाचार जगत के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ मुद्दों तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । उद्देश्य समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से उपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

मीडिया मैप

संपादकीय सलाहकार मंडल
डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेव राज गुप्ता
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक
प्रदीप माथुर

संयुक्त संपादक
सतीश मिश्रा

ब्यूरो प्रमुख
राजीव माथुर

मुख्य सह-संपादक
प्रशांत गौतम

सह-संपादक
अंकुर कुमार

विशेष प्रतिनिधि
जगदीश गौतम

विधि परामर्शदाता
संजय माथुर

पंजीकृत कार्यलय
2325, सेक्टर - डी , पॉकेट - 2 ,
वसंतकुंज , नई दिल्ली

कार्यालय
69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम
गाजियाबाद-201014

दूरभाष - 9810385757 /
9910069262

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-
editor@mediamap.co.in

संपादकीय
विचार प्रवाह
राजनीतिक परिदृश्य

चुनाव के बाद नए अवतार के रूप में उभरे राहुल गाँधी	डॉ॰ सलीम ख़ान	8
चुनाव परिणाम: नफरत की राजनीति और सांप्रदायिकता के अन्त का संदेश	प्रो प्रदीप माथुर	11

आर्थिक जगत

बजट: क्या विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा?	प्रो. लल्लन प्रसाद	12
10 विकास स्तंभों पर आधारित सरकार बचाओ बजट"	प्रो शिवाजी सरकार	13
कमज़ोर सरकार का मजबूर बजट	डॉ॰ सलीम ख़ान	14

विदेश नीति

भारत और रूस की मित्रता का विरोधी अमेरिका	डॉ जॉन दयाल	16
मोदी की मॉस्को यात्रा से अमेरिकी आयुध लॉबी नाराज	गोपाल मिश्रा	18
क्या बांग्लादेश से हमें कुछ सबक सीखने की जरूरत है?	डॉ. सतीश मिश्रा	19

राज्यों से

यह कुर्सी है बदलने में जरा सी देर लगती है	मीडिया मैप लखनऊ ब्यूरो	20
महाराष्ट्र चुनाव और मोदी सरकार का भविष्य	मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क	21
जगन्नाथपुरी का भव्य मेला जहाँ लाखो श्रद्धालु आते है	जगदीश गौतम	22

समसमयकी

महात्मा गांधी जी की यादों को सहेजने के लिए बन रहा एक स्मारक	हेमलता म्हस्के	23

विविधा

राजीव गाँधी जो भितरघात के शिकार हुए	प्रो प्रदीप माथुर	24
हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास	राजीव माथुर	26

महिला संसार

क्या महिला आरक्षण काफ़ी है?	अमिताभ श्रीवास्तव	28

धर्म दर्शन

मुहर्रम पर ताज़िया क्यों निकाला जाता है ।	डा. मुजफ्फर हुसैन गजाली	29

फिल्मी दुनिया

मोहब्बत और मौसिकी की जुगलबंदी को खय्याम कहते हैं	ज़ेबा हसन	30
चमकते सितारे जो हमें हँसा और रुला कर न जाने कहाँ चले गये।	प्रशांत गौतम	32

खेल कूद

पेरिस ओलंपिक्स में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन	प्रभजोत सिंह	34
वरिष्ठ पत्रकार प्रभजोत पॉल सिंह को मिला पेरिस ओलंपिक में सम्मान	प्रशांत गौतम	35

हास्य व्यंग

धूमधाम से मनाया गया इस वर्ष का अट्टहास सम्मान समारोह	रामकिशोर उपाध्याय	36

संपादकीय

बजट और समाज के कमज़ोर वर्ग

केंद्रीय बजट 2024 पर करीब से नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिन-रात सबका साथ-सबका विकास कहने वाली मोदी सरकार ने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कम किया है। बजट में वंचितों के लिए पर्याप्त राहत नहीं दी गई है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए दो सबसे आवश्यक क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा, को बहुत कम दिया गया है। जबकि स्वास्थ्य आवंटन में वृद्धि हुई है, यह सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.88% है, और शिक्षा आवंटन, हालांकि बढ़ा है, सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.07% है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट आवंटन क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 4% और 6% होना चाहिए। फिर अल्पसंख्यकों के उद्देश्य से कई योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में भारी कटौती की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) को कुल बजट का सिर्फ 0.06% प्राप्त हुआ।

"बजट से समाज के सिर्फ़ एक वर्ग को फ़ायदा होता दिख रहा है। बजट में अमीरों और बड़ी कंपनियों के प्रति पक्षपात इस बात से स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट कर राजस्व (17%) आयकर राजस्व (19%) से कम है, जबकि अप्रत्यक्ष करों का बोझ ग़रीब और मध्यम वर्ग पर बना हुआ है। नई रोज़गार प्रोत्साहन योजना के तहत निगमों को भारी सब्सिडी देना भी ठीक नहीं है।

इसके अलावा, राजस्व में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में व्यय में नगण्य वृद्धि हुई है। यहां तक कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना में भी उच्च बेरोजगारी दरों के बावजूद वृद्धि नहीं देखी गई है। फिर खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती को समझना मुश्किल है।

सरकार को भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए, अमीरों पर अधिक प्रत्यक्ष कर लगाना चाहिए और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अप्रत्यक्ष करों को कम करना चाहिए। दलितों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए और नीतियां बनानी चाहिए। आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रतीकात्मक इशारों के बजाय ठोस योजनाएं और पर्याप्त बजट आवंटन समय की मांग है।

कर्ज पर निर्भरता कम करने और ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की भी जरूरत है। बजट का करीब 19% हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए आवंटित किया गया है। उधार और अन्य देनदारियों के साथ यह बजट का करीब 27% है। सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और सामाजिक अशांति को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर ब्याज मुक्त माइक्रोफाइनेंस और बैंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए।

बजट में निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक बिंदु हैं, जैसे कि राजकोषीय विवेक का पालन, अनुमानित कर उछाल, पूंजीगत लाभ में वृद्धि, और प्रतिभूति लेनदेन कर। ये उपाय परिसंपत्ति की कीमतों को स्थिर करेंगे और कई क्षेत्रों में सीमा शुल्क को कम करके हमारे निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। लेकिन अपने आप में ये उपाय वर्तमान आर्थिक संकट को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

प्रो प्रदीप माथुर

स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका

जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच), दिल्ली इकाई द्वारा एक साल तक चलने वाले अभियान के तहत रविवार को "आधुनिक भारत का निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की भूमिका" शीर्षक से एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए गए योगदान पर प्रकाश डालना था। इस कार्यक्रम में सटीक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसके बारे में कई वक्ताओं ने तर्क दिया कि इसे तेजी से विकृत किया जा रहा है।

अपने आरंभिक भाषण में, जेआईएच दिल्ली के अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान ने ऐतिहासिक तथ्यों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया और मुस्लिम योगदान को कम करने के लिए इतिहास को फिर से लिखने की हालिया प्रवृत्ति के खिलाफ आग्रह किया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस तरह की विकृतियाँ गलतफहमी पैदा करती हैं और देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती हैं। खान ने खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक अयाश खान के काम का हवाला दिया, जिन्होंने निहित स्वार्थ वाले इतिहासकारों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों और उनके चित्रण के बीच विसंगतियों की ओर इशारा किया।

खान ने इस्लामी विद्वान मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही का भी जिक्र किया, जिन्होंने प्रामाणिक इतिहास लेखन के महत्व को रेखांकित किया। इस्लाही ने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐतिहासिक आख्यानों में हेरफेर की आलोचना की, और तर्क दिया कि वास्तविक इतिहास प्रस्तुत करना मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है।

जेआईएच के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने सेमिनार के विषय की प्रशंसा की, खास तौर पर बढ़ते इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के संदर्भ में। उन्होंने इन पक्षपातपूर्ण आख्यानों का मुकाबला करने और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में मुसलमानों द्वारा निभाई गई अभिन्न भूमिका पर जोर देने के लिए अधिक विद्वतापूर्ण शोध और सार्वजनिक शिक्षा का आह्वान किया। प्रोफेसर सलीम ने जोर देकर कहा कि इतिहास को फिर से लिखने के लिए सत्तारूढ़ सरकार के प्रयास केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक विभाजन को गहरा करना है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की भागीदारी इस्लामी शिक्षाओं से प्रेरित थी जो अन्याय और उत्पीड़न का विरोध करती हैं। प्रो. सलीम ने गलत सूचना और घृणा के बढ़ते ज्वार को संबोधित करने के लिए देश भर में अधिक सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आह्वान किया, सभी समुदायों में सामूहिक प्रयास की वकालत की, जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के दौरान प्रदर्शित एकता के समान है।

प्रसिद्ध लेखक सैयद उबैदुर रहमान ने स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम योगदान का विस्तृत विवरण दिया, जिसकी शुरुआत 1819 के फरैजी आंदोलन से हुई, जिसे उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित प्रतिरोध बताया। रहमान ने 1857 के विद्रोह में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की और कई अन्य मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रकाश डाला जिनके बलिदान को काफी हद तक भुला दिया गया है।

रहमान ने शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन के नेतृत्व में रेशमी रूमाल आंदोलन के महत्व पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के समर्थन से ब्रिटिश शासन को अस्थिर करना था। उन्होंने तुरंगजई के हाजी साहब और मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जैसे प्रमुख व्यक्तियों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रहमान ने इन गुमनाम नायकों के बारे में दस्तावेजीकरण और जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने का आह्वान किया।

स्वतंत्र पत्रकार श्रीमती सैयदा स्वालेहा जबीन ने स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं की महत्वपूर्ण लेकिन कम सराहना की गई भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बेगम हजरत महल जैसी प्रमुख हस्तियों का उल्लेख किया, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया था, और अबदी बानो बेगम, जिन्हें बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जबीन ने महात्मा गांधी द्वारा मुस्लिम महिलाओं के योगदान की स्वीकृति का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से समझने के लिए उनकी भागीदारी आवश्यक है।

जामिया मिलिया इस्लामिया के सहायक प्रोफेसर डॉ. अब्दुल्ला चिश्ती ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में मुसलमानों के राजनीतिक नेतृत्व पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में सांप्रदायिक रूप से विभाजित करने की आलोचना की और तर्क दिया कि ब्रिटिश द्वारा थोपे गए इस ढांचे ने दो-राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी। चिश्ती ने सभी समुदायों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया और इतिहासकारों से इतिहास को सही ढंग से संरक्षित और संप्रेषित करने का आग्रह किया।

जेएनयू के पूर्व इतिहास विद्वान डॉ. अभय कुमार ने औपनिवेशिक लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास के विकृतीकरण पर और विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जेम्स मिल और मैक्स मुलर जैसे यूरोपीय विद्वानों की भारतीय इतिहास के पक्षपातपूर्ण चित्रण के लिए आलोचना की, उन्होंने कहा कि उनमें से कई ने भारत का दौरा किए बिना ही भारत के बारे में लिखा। कुमार ने इतिहास को विकृत करने के चल रहे प्रयासों का मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे 'क्यों' और 'कैसे' को समझने के महत्व पर जोर दिया।

जेआईएच दिल्ली राज्य सचिव आसिफ इकबाल ने सेमिनार के उद्देश्यों को रेखांकित किया और अगले साल फरवरी में एक भव्य इतिहास सम्मेलन की योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रमुख भारतीय शहरों में अतिरिक्त इतिहास सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें वास्तुकला, संस्कृति और सामाजिक सुधारों में मुसलमानों के योगदान सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया जाएगा। इन आयोजनों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के योगदान को सही ढंग से दर्शाया और याद किया जाए।

(अनवारुल हक बेग)

भाजपा की राजनीति का नया मोहरा - कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा के विषय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आदेश वास्तव में आश्चर्यजनक है। जिले स्तर पर प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में जो कर सकता था उसके लिए लखनऊ से आदेश जारी करने की वैसे ही कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर इस बात को देश व्यापी मुद्दा बनाने का कोई मतलब भी न था। जबकि इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक छोटा सा कदम बताया जा रहा था।

प्रश्न यह है कि क्या योगी जी जैसे राजनीति के चतुर खिलाड़ी को इस आदेश के राजनीतिक असर का अंदाज नहीं था। यदि था तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया?
सबको पता है कि वर्ष 2017 में भाजपा के सर्वशक्तिमान नेता नरेंद्र मोदी की इच्छा के विरुद्ध योगीजी, लखनऊ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए और गृहमंत्री अमित शाह के तमाम विरोध के बावजूद अभी भी अपनी कुर्सी बनाए हुए है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन का ठीकरा उनके सर पर फोड़ने का प्रयास हुआ और उनके मुख्यमंत्री पद से हटने की मुहिम फिर रंग पकड़ने लगी।
प्रश्न यह है कि ऐसे समय जब उनकी स्थित वैसे ही कमजोर हो रही है। कांवड़ यात्रा आदेश जैसे विवादास्पद कदम उठाकर योगी जी अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? इसलिए लगता है कि यह आदेश भाजपा के आंतरिक संघर्ष में अपना वरदहस्त बनाए रखने के लिए उनका सोचा समझा राजनीतिक दांव है। लगता यही उन्होंने एक ऐसा पांसा फेंका है जिसमे चाट और पट दोनों में ही उनकी विजय है।
अब यह मामला और तूल पकड़ता है तो केंद्र में हिंदुत्व और राजनीतिक करने वाली मोदी सरकार की स्थित काफी कमजोर होगी। एन.डी.ए के घटक दलों ने इसका मुखर विरोध करना प्रारंभ कर दिया है और बहुमत के लिए उन पर प्राश्चित मोदी सरकार दबाव में है।
लोक सभा सच में विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट इस दवाब को और भी बढ़ा रहा है। स्वाभाविक है कि इस दबाव को स्थिति में मोदी शाह की जोड़ी मोदी पर उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ने का दबाव नहीं डाल पाएगी।
अगर दिल्ली के अपनी स्तिथि सुधारने के लिए मोदी-शाह की जोड़ी दबाव बनाकर योगी का त्यागपत्र ले लेती है। तो मुख्यमंत्री हिंदुत्व राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगेऔर आर.एस.एस. समर्थित हिंदुत्व राजनीति में उनका स्थान नरेंद्र मोदी से कहीं ऊपर हो जाएगा। आश्चर्य नहीं भाजपा के तमाम नेता जो मोदी से असंतुष्ट हैं। योगी के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने में सफल है।
भाजपा के अंदर भीतरी टकराव की जो भी छोटी और दलगत राजनीति है। इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। समाज का आपसी सौहार्द और अमन चैन खतरे में आ रहा है। ओर आपसी संघर्ष और टकराव बट रहा है। हा अगर भाजपा के अंदर का संघर्ष दोनों पक्षों को कमजोर करके घृणा और सम्प्रदायिक वैमनस्य पर आधारित मोदी सरकार को पतन और हिंदुत्ववादी राजनीति का अंत करता है तो यह अच्छी बात होगी।

कौन ठगवा नगरिया लूटल हो ?

पिछले दिनों टीवी पर एक सीरीयल 'महारानी' देख रहा था जिसमें एक बड़ा मार्मिक गाना सुना "कौन ठग नगरिया लूटल हो"। अचानक यूरेका जैसी ख़ुशी हुई।यही तो मैं और मेरे जैसे कितने परेशान देशवासी कहना चाह रहे थे। पिछले दस सालों में भारत का और सोचने समझने वाले हर भारतीय का सबसे बड़ा नुक़सान यही हुआ की उसकी आस्था को धीरे धीरे अंध विश्वास बना दिया गया है। भारत की प्राचीन सभ्यता की बात करने वाली सरकार ने आम आदमी की पूजा,परम्परा,त्योहार और धार्मिक मान्यताओं का तमाशा बना कर उनकी आस्था का अपमान किया है।
जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा हो उसको बिगाड़ देने में पता नहीं इन दुशासनों को क्या मज़ा आता है।हमारी पत्रिका के इस अंक में काँवर यात्रा पर भी लेख लेने पड़े क्योंकि एक राज्य के एक शहर ने अनोखा तुग़लकी फ़रमान जारी कर दिया कि यात्रा के दिनों में हर खाने के स्टाल पर मालिक को अपना नाम लिखना पड़ेगा।देखा देखी दूसरे राज्यों ने भी ऐसे ही आदेश जारी कर दिए।अंत में इस फ़ैसले को सर्वोच्च न्यायालय को रोकना पड़ा।
इसी तरह इस सरकार ने दस सालों में देश में अपने सारे त्योहारों को चाहे दीवाली हो(पटाखों को लेकर),दशहरा (रावण की लम्बाई),नवरात्र(माँस की दुकान),ईद (अदान की आवाज़) को अंध विश्वास और लाठी वालों के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं है की हिंदुवादी संगठन या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत के लिए नए हैं।इस देश की फुलवारी में हर रंग के फूल खिलते रहे हैं। लेकिन जबसे इन दलों को 2014 में पूर्ण बहुमत मिल गया ये अपने असली रूप में आ गये और अब चारों ओर इनका आतंक है।
पहले तो सिर्फ़ टीवी वाले गेरुए कपड़ों वाले बाबा लोग थे जो रोज़ लोगों का भविष्य बता कर अपना वर्तमान सुधार रहे थे। कोई भी पढ़ा लिखा या थोड़ा सा भी दिमाग़ रखने वाला इंसान ये कैसे मान लेगा की एक राशि वाले सारे जातक विदेश चले जाएँगे या उनकी लॉटरी लग जाएगी।लेकिन फिर भी घर की सारी महिलायें सारे काम छोड़ कर टीवी के सामने आ कर बैठ जाती थीं।
हमने ये बात सूचना मन्त्रालय में भी उठायी कि भारत के संविधान में लोगों में एक वैज्ञानिक सोच बनाने की बात कही गयी है लेकिन सरकारी तंत्र ख़ुद ही लोगों को अंध-विश्वास की ओर ढकेल रहा है।मगर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।वैसे भी हमारे देश में सूचना मंत्रालय की औक़ात ही क्या है। बजाय इन बातों को गंभीरता से लेने के अब इन भाग्य विधाताओं ने तो हमारे सारे त्योहारों का सत्यानाश कर दिया हैं।जो रक्षाबन्धन, दीवाली जैसे त्योहार हम लोग सदियों से अपने घर में अपने हिसाब से मनाते थे उनके बारे में भी अब ये टीवी वाले रंग बिरंगे बाबा और कुछ 'दादियाँ' बताने लगे हैं की कौन सी राशि के लोग इस त्योहार पर क्या करेंगे तो उनपर लक्ष्मी की अपार कृपा कैसे होगी।
फिर पिछले साल से एक नया नाटक शुरू हुआ कि हर त्योहार दो दो दिन पड़ने लगे।विशेषकर रक्षाबन्धन जैसे त्योहार पर बेचारी बहनों को बताया गया की वो राखी देर रात को कुछ घंटों में ही बाँध सकेंगी वरना दूर दूर से इस शुभ त्योहार पर भाइयों से मिलने आने वाली महिलाओं को क्या क्या परेशनियाँ हुईं इसके बाबाओं की सेहत या आमदनी पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। हम ये बिलकुल नहीं कह रहे हैं कि इससे पहले कभी बाबा या संत सत्ता के क़रीब नहीं रहे।धीरेन्द ब्रह्मचारी की या कुछ और मठाधीशों की शासकों से नज़दीकियों के क़िस्से किसी से छिपे नहीं हैं।पर वो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, कुछ ज़मीन,आश्रम और धन के लिए सत्ता के इर्द गिर्द मँडराते थे। और ये शायद सारी दुनिया में होता हैं।
मगर आज सबसे ख़तरनाक बात ये हुई है ऐसे पाखंडियों की फ़ौज बन चुकी है जिन्हें हर प्रकार के प्रचार और पाखंड का शासकों की ओर से खुली छूट है। ये लोग आस्था के नाम पर किसी को भी पीट सकते हैं, जान ले सकते हैं,महिलाओं का शारीरिक शोषण कर सकते हैं और जेल भेजे जाने पर चुनाव के समय परोल पर छोड़ दिए जाते हैं।
इनके बिना सत्ता में आना नामुमकिन है और सत्ता में बने रहना तो असंभव। ऐसे में एक ही रास्ता है। अगर सम्भव हो तो हर त्योहार का दिन,शुभ मुहूर्त,समय और मनाने का तरीक़ा भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई एक कमिटी करे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन?
(अमिताभ श्रीवास्तव)

हम चले संभल के सजन बरसात में!

हम सभी को बरसात की पहली फुहार का इन्तजार रहता है जो कि धूल धक्कड़ भरे दिनों की एकरसता को कम कर देती है। बरसात की शुरुआत मे किसका मन ड्राइविंग करने के लिए नहीं मचलता बदलते मौसम के कारण मन में तरंग तो उठती है साथ ही हम सावधानी को भी नज़रअंदाज़ कर

देते है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर मौसम में एक ही तरह से ड्राइविंग करे, जब मौसम बदलता है तो हमें अपने ड्राइविंग के तरीके भी बदलने चाहिए। ड्राइविंग की हिदायतों में ऐसी कोई रहत्यमयी बात नहीं है। वह तो एक सामान्य सूझ-बूझ की ही बात है।
सर्वप्रथम बरसात शुरू होने के पहले गाड़ी की जांच-परख करनी चाहिए। इंजन से शुरुआत करें, विशेषकर कम्प्रेशान देखिए, ब्रेक्स और ब्रेकशूज की अलीभांति जांच बहुत जरूरी है। टायरों की हालात को बारीकी से देखिये- मोटर गाड़ियों के लिए कम से कम 2 मि. मी. का टायर ट्रेड ही सुरक्षित होता है। वाइपर ब्लेइस को परख लीजिए, वे भली प्रकार काम कर रहे है या नहीं। कार की इलेक्ट्रिकल व्यवस्था भी जांच करवा लीजिए ताकि आपको संभावित खामियों का पता चल सके और हाँ, अपनी कार में जंग-रोधक उपचार अवश्य करवा ले, अब आपकी कार सफर के लिए तैयार है, पर क्या आप तैयार है ?
जब भी बरसात में ड्राइविंग का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि पहली फुहार ही सबसे खतरनाक होती है! बचे खुचे तेल और ग्रीज से मिलकर पानी सड़क पर एक चिकनी परत छोड़ता है। इसलिए अपने वाहन की रफ्तार कम रखिये।
इन दिनों आपको स्वयं देखने, अपनी उपस्थिति का आभास अन्य ड्राइवरों को देने, और अपनी प्रतिक्रिया के लिए अधिक समय चाहिए। गीली सड़कों पर ब्रेक के लिए अधिक अंतर की भी ज़रूरत होती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अगली गाड़ी से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिये।
गाड़ी का फिसलना एक भयावह अनुभव होता है- खासकर जब फिसलने वाली गाड़ी आपकी हो। गीली चिकनी सतह पर आप जब जब तेजी से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते है, लहसा ब्रेक लगाते है या कार एकदम मोड़ते है तो गाड़ी फिसल सकती है। गाड़ी फिशलने के लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ज्यादातर कार खुद व खुद नहीं फिसलती बल्कि उसके पीछे चलाने वाले का हाथ होता है।
बरसात आपकी आंखों के आगे अजीबोगरीब खेल खेलती है। बिंडशील्ड के पार आप ठीक से देख नहीं पाते। कार के शीशे अंदर से, यहां तक कि रियर व्यू मिरर तक धुंधला जाते है। जांच कर ले कि आपके वाइपर ब्लेड ठीक से काम कर रहे है। गाड़ी पीछे करते समय आपको अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। दिन में भी हेडलाइट्स का इस्तेमाल ही श्रेयस्कर होता है। जितनी कम दृष्यता होगी आपको उतनी ही अधिक सावधानी रखनी होगी।
सड़क पर चलते फिरते अन्य लोगों का भी ध्यान रखिए। पैदल चलनेवालों का विशेष ख्याल कीजिए, अक्सर लोग बरसात से बचने के फिकर में आसपास का ध्यान नहीं रखते और सड़क के खतरों को नज़रअंदाज कर देते है। साइकल सवारों और हाथ गाड़ी वालों में संभलकर रहिए क्योंकि बरसात की वजह ते उन्हें कम नजर आता है। जहां तक हो सके रात में ड्राइविंग न कीजिए।
हमारी सड़कों पर एक और भयानक खतरनाक दुश्मन सहसा प्रकट होता है गढड़ा। साहता प्रकट होने वाले ये गढडे न केवल आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते है बल्कि आप उस पर अपना नियंत्रण भी खो सकते है।
बरसात में अपनी गाड़ी का खास ख्याल करे। कार और टायर की नियमित जांच करें। अपने ब्रेकों को भी समय समय पर जांचते रहे। जब मौसम ज्यादा ही खराव हो तो अपनी गाड़ी को थोड़ा आराम दे। बेहतर तो ये होगा कि गाड़ियों को साझे में इस्तेमाल करे। इससे सड़क पर कम भीड़ होगी और आपके शरीर और जेब को भी फायदा होगा।
बदला हुआ मौसम सुखद लगता है, न कि दुर्घटनाएं. दुर्घटनाएं खराब मौसम के कारण नहीं बल्कि खराब ड्राइविंग के कारण होती है।
(भावना राजेश्वरी)

असुरक्षा के बोध से भरे अम्बानी परिवार का समारोह

अंबानी परिवार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका भव्य विवाह समारोह और अत्यधिक दिखावे वाली अमीरी अब उनकी एक अलग छवि बना रही है। बड़े स्तर पर की गई पीआर (पब्लिक रिलेशन) से अब शायद खुद अंबानी परिवार को भी असहजता महसूस हो रही होगी। लेकिन तय कार्यक्रम तो करने ही होते हैं। इस दौरान एक चीज जो प्रमुख रूप से उभरकर सामने आई है, वह है असुरक्षा का बोध। जब इंसान के अंदर असुरक्षा का भाव बढ़ता है, तो वह दिखावे की ओर ज्यादा झुकता है। वैसे भी शिखर पर पहुंचने की जगह सबसे असुरक्षित होती है।
अंबानी परिवार के लिए धीरूभाई अंबानी एक आदर्श हैं। धीरूभाई पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिसमें उन्हें इस रूप में दिखाया गया है कि उन्होंने बेहद गरीबी से उठकर एक विशाल कंपनी खड़ी की। गरीबी और अमीरी के इस अंतर को अंबानी परिवार के सदस्य बचपन से अनुभव करते आए हैं। धीरूभाई अंबानी के संघर्ष और सफलता की कहानी महज 50 साल पुरानी है, जब वह अत्यधिक गरीब थे। लेकिन उसके बाद से जिस तेजी से वह अमीर बने, वह सभी जानते हैं। धीरूभाई की चतुराई और तिकड़म का कोई सानी नहीं था। उनके पैसे खर्च करने का साहस और निर्णय लेने की गति सराहनीय थी। निर्णय नैतिक थे या नहीं, यह हमेशा एक बहस का विषय रहा है, लेकिन सिस्टम में उनके फैसलों की सफलता का कोई मुकाबला नहीं था।
जब अंबानी परिवार का बिजनेस बढ़ रहा था, तब अनिल अंबानी का नाम चर्चा में आया। उन्हें अभिनेत्री टीना मुनीम से शादी करनी थी, जिसका परिवार ने विरोध किया, लेकिन अंततः दोनों का विवाह हो गया। हालांकि, परिवार ने कभी भी टीना मुनीम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया।
धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद, 2006 में अंबानी परिवार के बिजनेस को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे महाभारत में द्रोपदी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था, वैसे ही अंबानी परिवार के विभाजन के लिए टीना को जिम्मेदार माना गया। यह भी संभव है कि जब किसी की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता, तो वह व्यक्ति भी आत्मसम्मान की चाहत रखता है।
टीना अंबानी अब भी मुकेश अंबानी के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, और अनिल भी शामिल होते हैं, लेकिन उनके चित्र मुकेश अंबानी के परिवार के साथ कभी नहीं दिखते। जब भी अनिल अंबानी मुश्किल में फंसे, मुकेश ने उनकी मदद के लिए बिजनेस डील कीं और सारे करार तोड़कर अनिल के क्षेत्रों में अपने कदम बढ़ाए। जबकि विभाजन के समय यह तय हुआ था कि मुकेश अनिल के बिजनेस में दखल नहीं देंगे, लेकिन समय के साथ जैसे-जैसे अनिल कमजोर होते गए, मुकेश ने उनके बिजनेस को संभाल लिया।
अंबानी परिवार ने अपने जीवन को पूरी तरह से बिजनेस के इर्द-गिर्द घुमा दिया। इस कारण जीवन में नीरसता आ गई। पैसे और सुविधाओं के बावजूद, वे जीवन में सजीवता और उत्साह नहीं खोज पाए। महंगी घड़ियां, गाड़ियां, और आभूषण भी उनके जीवन की इस नीरसता को दूर नहीं कर पाए। शायद इस नीरसता को तोड़ने के लिए ही यह भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया।
अनंत अंबानी की सेहत और आत्मविश्वास परिवार के अन्य सदस्यों जैसा नहीं है, जो उनकी बीमारी का परिणाम है। उन्हें समाज और बिजनेस में स्थापित करने के लिए पीआर टीम काम कर रही है, और इस विवाह का उद्देश्य भी उन्हें समाज में स्वीकार्यता और बिजनेस जगत में गंभीरता से लेना हो सकता है।

चुनाव के बाद नए अवतार के रूप में उभरे राहुल गाँधी

डॉ॰ सलीम ख़ान

राहुल गाँधी ने विपक्ष के नेता की हैसियत से अपने पहले सम्बोधन में बीजेपी को धराशायी कर दिया। राहुल गाँधी अगर मणिपुर, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर भाषण देते तो लोग कहते, यह तो बीजेपी का घर ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें नहीं रहते, मगर वह तो हिन्दुत्व के दरबार में घुस गए। बीजेपी यह कहकर वरग़लाती है कि फ़ुलाँ-फ़ुलाँ हिन्दुत्व के दुश्मनों की वजह से हिंदू धर्म ख़तरे में है। हम उनसे सनातन धर्म की हिफ़ाज़त करते हैं। इस सेवा के बदले हमें वोट देकर सत्ता में रखा जाए। राहुल गाँधी ने आगे बढ़कर कह दिया चूँकि हिंदू धर्म हिंसा की शिक्षा नहीं देता इसलिए यह अपने आपको हिंदू कहकर दिन-रात नफ़रत-नफ़रत, हिंसा-हिंसा फैलानेवाले सिरे से हिंदू ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने देखा कि राहुल ने हिन्दुत्व पर ही हाथ मार दिया तो सोचा कि अगर यही छिन जाए तो मैं किस बुनियाद पर हुकूमत करूँगा? बस फिर क्या था। इस नाज़ुक रग पर हाथ रखते ही वह बिलबिला उठे और राहुल के जाल में फँस गए।

प्रधानमंत्री भूल गए कि उन्हें दरमियान में बोलकर अपनी जग-हँसाई नहीं करानी चाहिए, बल्कि आख़िर में जवाब देने के मौक़े का इंतिज़ार करना चाहिए। उनसे यह नहीं हो सका इसलिए उन्होंने बीच में खड़े होकर कह दिया कि हिंदू समाज को हिंसा का समर्थक कहना उसका अपमान है। मोदी के जवाब में राहुल ने कहा कि वह पूरे हिंदू समाज के बारे में नहीं कह रहे हैं। उसके आगे बढ़कर राहुल गाँधी ने यह भी कह दिया कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस हिन्दुओं के प्रतिनिधि नहीं हैं। राहुल ने अयोध्या में बीजेपी में राम भक्तों की नाराज़ी और वाराणसी से किसी तरह मोदी के बच निकलने का ज़िक्र किया तो पानी सिर से ऊँचा हो गया। काश, प्रधानमंत्री सब्र कर जाते तो उन्हें इस तरह धोबी-पछाड़ का सामना नहीं करना पड़ता! इस लम्हे प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि काश, वह चुनाव हार जाते तो उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। प्रधानमंत्री एक बार चित होने के बाद फिर बोले, इनके अलावा तीन बार अमित शाह और राजनाथ सिंह तथा एक-एक बार शिवराज चौहान, किरण रिजिजू और भूपिंदर यादव फट पड़े।

राहुल के सम्बोधन से सत्ता पक्ष को मिर्ची लगी तो उन्होंने तुरन्त कहा कि यह शोर-गुल तीर के सीने में पेवस्त होने की वजह से हो रहा है। राहुल ने हिन्दुत्व पर अपना बयान जारी रखा तो गृहमंत्री ने उठकर कहा कि उन्होंने गर्व से ख़ुद को हिंदू कहनेवालों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, इसलिए वह माफ़ी माँगें। शाह ने 40 साल पुराने 1984 के सिख दंगों को तो याद किया, मगर 22 साल पुराने गुजरात दंगे तीन साल पुराने दिल्ली के दंगे और इसी बरस होनेवाले मणिपुर दंगे को भूल गए। राहुल गाँधी ने कहा कि बीजेपी मणिपुर को भारत का हिस्सा ही नहीं समझती, इसलिए वहाँ न प्रधानमंत्री और न गृहमंत्री। झूठ के इल्ज़ाम पर जब राहुल ने डटकर कहा, "यह सच है!" तो गृहमंत्री की सारी धौंस हवा हो गई, क्योंकि तमांचा झन्नाटे दार था। अग्निवीर को राहुल गाँधी ने 'यूज़ ऐंड थ्रो' स्कीम बताते हुए कहा कि यह नौकरी चार साल के बाद ख़त्म हो जाती है। जवान को सिर्फ़ 6 महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी मुद्दत चीन में 5 साल है। उसको न तो कोई पेंशन मिलती और न मरने के बाद शहीद का दर्जा, और मुआवज़ा भी नहीं मिलता।

इस टिप्पणी पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सब्र का पैमाना छलक गया। उन्होंने राहुल गाँधी पर सदन को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था अमेरिका तथा अन्य देशों में लागू है। इसे बहुत सोच-समझकर लागू किया गया है और दूसरे स्थानों पर आपत्ति नहीं होती तो यहाँ क्यों की जा रही है? राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि अग्निवीर के दौरान जंग में मारे जाने पर उसे एक करोड़ मुआवज़ा दिया जाता है। राहुल के बयान को डिलिट करने की माँग करनेवाले राजनाथ ने मौत के बाद रक़म देने की बात तो की, मगर ज़िंदगी में उसके शोषण पर कुछ नहीं कह सके और न पेंशन पर कुछ बोले। यह गृहमंत्रालय का मामला नहीं था। उसके बावजूद अमित शाह अपनी बेइज़्ज़ती कराने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा रक्षामंत्री ने जब यह बता दिया कि मरनेवाले अग्निवीर को एक करोड़ मुआवज़ा दिया जाता है तो विपक्ष के नेता को अपने शब्द वापस लेकर माफ़ी माँगनी चाहिए। राहुल गाँधी ने एक मारे जानेवाले अग्निवीर के घर जाने की घटना सुनाकर दूसरी बार गृहमंत्री को पटकनी दे दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में रक्षामंत्री और उनके बयानों में अन्तर्विरोध है, लेकिन हक़ीक़त अग्निवीर का परिवार जानता है। यह स्कीम फ़ौजी जवानों के दरमियान भेदभाव का प्रतीक है, इसलिए उनकी सरकार उसे निरस्त कर देगी।

देश की अधिकांश आबादी अग्निवीर स्कीम के ख़िलाफ़ है। राजनाथ सिंह अगर दरमियान में दख़ल-अंदाज़ी न करते और अमित शाह उनके समर्थन में नहीं आते तो राहुल गाँधी को यह साबित करने का मौक़ा नहीं मिलता कि फ़ौज का दोस्त और दुश्मन कौन है? यह मुद्दा छेड़कर राहुल ने अग्निवीरों के परिजनों को बीजेपी से दूर करके अपना समर्थक बना लिया। राजनाथ और अमित शाह की प्रतिक्रिया ने राहुल गाँधी की मदद की। अडानी और अंबानी की ख़ातिर किसान क़ानून को बनाने का इल्ज़ाम लगाने के बाद पूँजीपतियों के लाखों करोड़ क़र्ज़ की माफ़ी और किसानों की ख़ुदकुशी का ज़िक्र किया। उन्होंने किसानों से वार्ता न करने और उन्हें गले नहीं लगाने की शिकायत करते हुए एमएसपी नहीं देने की बात की तो नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ख़ून जोश मार गया। वह बोले सदन में झूठ बोलकर देश को गुमराह किया जा रहा है, एमएसपी दी जा रही है। हालाँकि चौहान ख़ुद झूठ बोल रहे थे।

एमएसपी न सारे मुल्क में दी जाती है और न सारी पैदावार पर अदा की जाती है। कुछ फ़सलों पर भी रंगनाथ आयोग की सिफ़ारिश के मुताबिक़ नहीं दी जाती। ऐसा होता तो किसान अपनी पैदावार नष्ट करके वीडियो न बनाते। राहुल ने पूछा कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा क्यों कम हो गया? तो इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। अपने सम्बोधन में राहुल गाँधी ने जब कहा कि यह हुकूमत किसानों को देश का दुश्मन समझती है तो फिर एक बार गृहमंत्री के सब्र का बाँध टूट गया। उन्होंने खड़े होकर बड़ी लाचारी से कहा कि सदन अध्यक्ष यह मिथ्यारोपण है। आप बे-जा ढील देकर उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृपया हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। इस दिलचस्प मंज़र में एक ख़ूँख़ार शेर अपनी ही बकरी से सुरक्षा की भीख माँग रहा था। गृहमंत्री की इस गुहार ने उनके सारे रोब और दबदबे की मिट्टी पलीद कर दी। एक समीक्षक ने टेलीविज़न परिचर्चा में कहा कि ऐसा लग रहा था मानो गली का गुंडा किसी लाठी-बरदार हवालदार की सुरक्षा की भीख माँग रहा है। इस मौक़े पर सदन के स्पीकर को ऐसा लगा होगा कि वह सरकार के नहीं, बल्कि विपक्ष के समर्थक हैं। राहुल गाँधी के हमले से स्पीकर ओम बिड़ला भी सुरक्षित नहीं रहे। राहुल ने जब कहा कि वह भेदभाव करते हैं, प्रधानमंत्री से झुक कर मिलते और उनसे नहीं, तो स्पीकर ने मौक़ा ग़नीमत जानकर जवाब दिया कि भारतीय संस्कृति में बड़े से झुककर मिलते हैं और छोटा पैर छूता है। ओम बिड़ला को नहीं पता था इस सवाल का भी मुँहतोड़ जवाब राहुल के पास है। उन्होंने कहा सदन में तो सबसे बड़े आप हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे झुककर मिलना चाहिए। इस जवाब को सुनकर ओम बिड़ला को ख़याल आया होगा कि अब झोला उठाकर चल देना ही बेहतर है। यह एक सच्चाई है। पहले स्पीकर मावलंकर को जब पण्डित नेहरू ने अपने दफ़्तर में बुलवाया तो उन्होंने यह कह कर इनकार कर दिया कि सदन के पद की मान-रक्षा के अनुसार वह नहीं आ सकते।

राहुल ने शिव की तस्वीर निकाली तो बिड़ला मना करके फँस गए। इसपर कैमरा हट गया तो राहुल ने कहा, "यह जादू देखो कैमरा हट गया।" उसके बाद राहुल को सारी तसवीरें दिखाने का मौक़ा मिल गया और उन्होंने अन्य धर्मों के साथ निर्भीक होने की क़ुरआनी शिक्षा भी पेश की। राहुल ने दरअस्ल प्रधानमंत्री बने बिना जनता के दिल से बीजेपी का ख़ौफ़ निकाल दिया और ख़ुद उसे डरा दिया। दस सालों तक संसद भवन में विपक्ष का नेता नहीं था। पिछली बार काँग्रेस चार सदस्यों से चूक गई तो बीजेपी ने डर के मारे पद बहाल करने की हिम्मत नहीं की। अब पता चला कि राहुल गाँधी को सुप्रीमकोर्ट में जाने से पहले सदन से निकाल बाहर करके बे-घर क्यों किया गया? राहुल गाँधी ने अपने सम्बोधन से साबित कर दिया बीजेपी के अंदर पाया जानेवाला ख़ौफ़ दुरुस्त था। मोदी ने उपेक्षा से कहा था, "कौन राहुल?" अब उन्हें पता चल गया कि 'कौन है राहुल?' प्रधानमंत्री ने ख़ुद अपने बारे में कहा था, 'एक अकेला सबपर भारी' लेकिन अब दुनिया कह रही है कि अकेला राहुल पूरी बीजेपी पर हावी है। विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री का साया (शैडो पीएम) कहा जाता है, मगर अब तो साया व्यक्ति से बड़ा हो गया लगता है।

आम भारतीय के पास वक़्त गुज़ारी के लिए क्रिकेट, फ़िल्में और राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। ये तीनों चीज़ें उसे मोबाइल पर मिल जाती हैं इसलिए वह अपना ग़म कम करने के लिए उनसे टाइम पास करता रहता है। एक ज़माने में क्रिकेट मैच पाँच दिनों तक चलता था और इसके बावजूद बिना किसी परिणाम के ड्रा हो जाया करता था। फ़िलहाल पाँच घंटों के अंदर सब कुछ निमट जाता है और मैच ड्रा भी नहीं होता। पुराने ज़माने में मैच ड्रा करने की ज़रूरत दो कारणों से पड़ती थी। अव्वल तो विरोधी टीम का लक्ष्य बहुत ज़्यादा होने पर और दूसरे अपने बल्लेबाज़ों के कम रन पर आउट हो जाने की स्थिति में। इस बार संसद भवन में यही हुआ। इंडिया मोर्चे के कई खिलाड़ियों ने मसलन राहुल गाँधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन उवैसी और इमरान प्रताप गढ़ी वग़ैरा ने अपनी भाषण-कला से रनों का ढेर लगा दिया, जबकि बीजेपी का कोई बल्लेबाज़ पिच पर जम ही नहीं पाया। जन साधारण से पूछा जाए कि सदन में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, तो लोग सिर्फ़ उनके राहुल गाँधी पर एतिराज़ का हवाला देंगे। कोई नहीं जानता कि मोदी के अलावा बीजेपी के किसी नेता ने अपने भाषण में क्या कहा? आलम यह कि—

सुकूत छाया है इंसानियत की क़ब्रों पर यही है मौक़ए-इज़हार आओ सच बोलें सुकूत (यानी चुप्पी) के इस घुटन भरे सन्नाटे में टीम को हार से बचाकर मैच ड्रा करने का सारा बोझ प्रधानमंत्री के कमज़ोर कंधों पर आ गया और इस उम्र में वह बेचारे करते भी तो क्या करते? लेकिन क़तील शिफ़ाई के मशवरे पर अमल करते हुए सच तो बोल ही सकते थे, लेकिन उनसे यह नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ट मैच के अंदाज़ में लंबी पारी खेलकर मैच को ड्रा तो कर दिया, मगर इस दौरान न सिर्फ़ संसद भवन में बैठे दर्शक बोर होते रहे, बल्कि मोबाइल और टेलीविज़न पर उन्हें देखनेवाले भक्त भी ऊब गए। एक थके-माँदे खिलाड़ी को धीमे-धीमे पानी पी-पीकर कई गेंदों के बाद एक दो रन लेते हुए देखना और इसपर ताली बजाना कैसा अज़ाबे-जान है, इसका नज़ारा संसद भवन के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान हुआ। वह लगातार बोले जा रहे थे और सुननेवालों को ऐसा लग रहा था कि उनका ब्रेक फ़ेल हो गया है। अब इस बस को रोकने के लिए उसे किसी पेड़ या दीवार से टकराना ज़रूरी है, वर्ना वह अपने बेबस मुसाफ़िरों समेत किसी गहरी खाई में जाकर गिर जाएगी।

प्रधानमंत्री की धीमी आँच पर (स्लो मोशन में) लम्बे-चौड़े भाषण को देखकर सुनील गावसकर की याद आ गई। वह टेस्ट मैच के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का रिकार्ड उनके नाम था, मगर जब वन-डे का ज़माना आया तो उनका पिच पर टिकना भारतीय टीम की शिकस्त का परवाना बन जाता था। इसलिए कि वहाँ धड़ा-धड़ रन बनाने की ज़रूरत होती थी और वह धीमे-धीमे खेलकर अपनी टीम को हरवा देते थे। आगे चलकर एक ऐसा ज़माना भी आया कि जब गावसकर के प्रशंसक तथा अन्य शौक़ीन उनके आउट होने की दुआ करते थे। प्रधानमंत्री के साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने दुनिया-भर में फैले हुए मोदी भक्तों को इतना बोर कर दिया है कि अब वह आउट होने के बजाय सेवानिवृत होने की तमन्ना करने लगे हैं। संघ परिवार चाहता है कि बड़े मियाँ जल्द से जल्द अपना झोला उठाकर 'मार्गदर्शक मंडल' में चले जाएँ वर्ना उनकी टीम का फ़ाइनल जीतना तो दूर टूर्नामेंट में क्वालिफ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा।

प्रधानमंत्री को अपने समापन भाषण में दो काम करने थे। अव्वल तो इस समापन भाषण पर धन्यवाद देना जो उनकी मर्ज़ी पर राष्ट्रपति ने पढ़कर सुनाया था और दूसरे विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देना। राहुल गाँधी के भाषण ने प्रधानमंत्री महोदय को इतना परेशान कर दिया कि वह अपनी दोनों ज़िम्मेदारियाँ भूल गए। उनको यह एहसास भी नहीं रहा कि संसद भवन चुनावी भाषण करने का स्थान नहीं है। उनसे दूसरी ग़लती यह हुई कि उन्होंने राहुल के भाषण से उन बातों को निकलवा दिया जो उनके ख़याल में विवादित थीं। वो चीज़ें अगर संसदीय कार्रवाई में मौजूद होतीं तो उनके जवाब का औचित्य भी मौजूद होता, मगर स्पीकर की मदद से राहुल गाँधी के भाषण में से, हिंदू राष्ट्र, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और अडानी तथा अंबानी की आलोचना की सारी बातें निकलवालने के बाद उसकी आलोचना करना निरर्थक प्रयास था। निकाली गई बातों पर टिप्पणी करके मोदी ने अकारण ही अपना और दूसरों का वक़्त बरबाद किया। इस मामले में प्रधानमंत्री ने जल्दबाज़ी करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यह उम्र का तक़ाज़ा है, क्योंकि एक ख़ास वक़्त के बाद दिमाग़ काम नहीं करता।

संसद भवन में राहुल गाँधी का अनुभव नरेंद्र मोदी से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कई मामलों में प्रधानमंत्री पर वरीयता प्राप्त कर ली है। अव्वल तो वह उत्तर प्रदेश सहित केरल से मोदी की तुलना में दोगुने वोट के फ़र्क़ से सफल होकर संसद भवन में गए हैं। इस बार लोकसभा में उनकी पार्टी के सदस्यों की तादाद लगभग दोगुनी हो गई है जबकि मोदी की बीजेपी के सदस्य बीस प्रतिशत कम हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर मोदी मीडिया तक में राहुल गाँधी की लोकप्रियता में असाधारण वृद्धि हुई है और वह नरेंद्र मोदी से बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गाँधी के भाषण को बचकाना क़रार देना विपक्ष के नेता का अपमान है। यह ऐसा ही है जैसे कोई सदन में कह दे कि प्रधानमंत्री बुढ़ापे के कारण सठिया गए हैं। बड़ी उम्र की आड़ में दूसरों का मज़ाक़ उड़ाना ज़ुल्म है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष के नेता की हैसियत कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहने का कोई हक़ नहीं है कि राहुल गाँधी अपने पद के योग्य नहीं हैं। यह काँग्रेस पार्टी का हक़ है कि वह किसको इस पद पर आसीन करे। यह हास्यास्पद बात है कि अपनी पार्टी के लोकसभा सदस्यों की बैठक बुलाकर उसमें अपने नेतृत्व की पुष्टि करवाने से डरनेवाला (कि कहीं नितिन गडकरी का नाम न आ जाए) दूसरों की योग्यता पर उंगली उठा रहा है। प्रधानमंत्री को संसद भवन में दस साल गुज़ारने के बाद भी यह नहीं पता चला कि वहाँ शब्द 'झूठ' का इस्तेमाल निषिद्धि है। उन्होंने लगभग चालीस बार इस शब्द को विभिन्न शैलियों में प्रयोग किया, जबकि उनके विरोधी ख़ुद उन्हें झूठों का सरदार कहकर पुकारते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण में से इस ग़ैर-संसदीय शब्द को निकाला जाना चाहिए। मोदी ने अपने भाषण में राहुल गाँधी की बातों को एक तरफ़ तो बचकाना कहा और फिर उनको संजीदगी से लेकर उसपर सख़्त कार्रवाई करने की माँग भी कर दी। वह भूल गए कि परिपक्व लोग बचकाना बातों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

प्रधानमंत्री की उपर्युक्त गीदड़ भभकी को गंभीरता से लेकर अगर कहीं ओम बिड़ला ने राहुल गाँधी से सदस्यता छीन ली तो मोदी को लेने के देने पड़ जाएँगे। वैसे भी सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक़ मोदी की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में 36 प्रतिशत लोग राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जबकि मोदी को इस पद पर देखने के ख़ाहिशमंद सिर्फ़ 32 प्रतिशत रह गए हैं। राहुल पर कार्रवाई उनकी लोकप्रियता को बहुत बढ़ा देगी। मोदी और राहुल के भाषण का मुहूर्त देखें तो प्रधानमंत्री के भाषण से ठीक पहले हाथरस के हादिसे में डेढ़ सौ लोग मृत्यु का ग्रास बन गए और देश भर में शोक की लहर छा गई। इसके विपरीत विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गाँधी के भाषण से पहले 17 साल के बाद भारतीय टीम विश्व पदक जीत गई और आम लोगों के अंदर ख़ुशी की एक लहर चल गई। आज के ज़माने में अपना फ़र्ज़े-मंसबी (पदगत कर्तव्य) अदा करते हुए सच

बोलने की ज़िम्मेदारी निभानेवालों पर यह शेर फ़िट बैठता है—

हमें गवाह बनाया है वक़्त ने अपना
बनाम अज़मते-किरदार आओ सच बोलें

अमेरिका में दक्षिण अफ़्रीक़ा के साथ फ़ाइनल में भारतीय टीम की जीत पर पूरा देश झूम उठा है। प्रधानमंत्री को अगर इसका यक़ीन होता तो मैच देखने पहुँच जाते, मगर पिछले साल के कटु अनुभव ने रोक दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिछले वर्ष भारत और आस्ट्रेलिया का फ़ाइनल देखने के लिए अमित शाह सहित नरेंद्र मोदी मौजूद थे, मगर शिकस्त के बाद 'पनौती' का मच गया। 'पनौती' का मतलब समझने के लिए मोदी के चहेते अक्षय कुमार की सब से ज़्यादा कामयाब फिल्मों में से एक 'हाउसफ़ुल' देख लेना काफ़ी है। इसके चार सीक्वेल बन चुके हैं और पाँचवाँ भी अगले साल रिलीज़ हो जाएगा। इस फ़िल्म का हीरो आरुश एक मनहूस आदमी है, इसलिए 'पनौती' के लक़ब से याद किया जाता है। 2021 में पहली बार वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो स्टेडियम में अक्षय कुमार के साथ अमित शाह का बेटा जयशाह मौजूद था और प्रधानमंत्री भी अपने घर में खेल देखकर तालियाँ बजा रहे थे। पाकिस्तान की जीत के बाद ट्वीटर पर यूज़र्स ने इन तीनों को 'पनौती' कहकर भारत की हार के लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया था।

मोदी 3.0 के साथ 'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा' का मामला हो रहा है। अयोध्या के जिस मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया उसकी छत से पानी टपक गया। अयोध्या जंक्शन का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, उसकी दीवार गिर गई। राजकोट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 को किया तो उसके पिकअप और ड्रॉप एरिया की छत गिर गई। लखनऊ के अडानी एयरपोर्ट पर टर्मिनल-3 में बारिश से छत टपकने की वीडियो प्रसारित करके काँग्रेस ने याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया था। जनता अब एयरपोर्ट पहुँचकर इंक़ायरी काउंटर पर यह पता लगाती है कि इसका उद्घाटन मोदी जी ने तो नहीं किया? राजधानी दिल्ली में बारिश के दौरान इंदिरा गाँधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की छत गिर गई। उसके कारण एक व्यक्ति मर गया और कई लोग ज़ख़्मी हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 27 जून को नवनिर्मित डुमना हवाई अड्डे के ड्रॉप इंडिगो एरिया में छत फट जाने की वजह से पानी का सैलाब आ गया। इससे एक गाड़ी तबाह हो गई, जबकि आयकर विभाग का एक कर्मचारी और उसका ड्राइवर बाल-बाल बच गए। इत्तिफ़ाक़ से ये सारी दुर्घटनाएँ डबल इंजनवाली सरकारों में हुईं । इन दुर्घटनाओं से पहले दो रेल गाड़ियों के टकराव से मोदी जी के नए कार्यकाल का मनहूसियत भरा आरम्भ हुआ।

सदन के पहले अधिवेशन से पहले नीट (NIIT) के पेपर्स भी मंदिर की छत की तरह लीक हो गए। इन प्रतियोगी परीक्षाओं का ताल्लुक़ चूँकि लाखों छात्रों से था इसलिए इसपर संसद भवन में बहस की माँग स्वाभाविक थी, लेकिन मोदी सरकार के लिए उसकी इजाज़त देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। इस भ्रष्टाचार का ताल्लुक़ गोधरा (गुजरात), पटना (बिहार), इलाहाबाद और नोएडा (यूपी), सिवाय माधवपुर (राजस्थान), रोहतक (हरियाणा), नांदेड़ (महाराष्ट्र) और भोपाल (मध्य प्रदेश) जैसे शहरों से जुड़ चुका। इत्तिफ़ाक़ से इन तमाम राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। इसलिए यह सवाल तो बनता ही है कि आख़िर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है?' यह मामला उतना संगीन है कि जब शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शपथ लेने के लिए आए तो संसद भवन 'शेम शेम, नीट नीट' के नारों से गूँज उठा। आगे चलकर जब विपक्ष के नेता राहुल गाँधी ने इस अहम मुद्दे पर ज़ोर दिया तो उनका माइक बंद कर दिया गया। पेपर लीक से मंदिर लीक तक की घटनाएँ सरकार की कमज़ोरी का सुबूत हैं। ऐसा लगता है कि वे दिन दूर नहीं जब मोदी की नई सरकार भी हवा के झोंके से छत, दीवार और छज्जे की तरह धराशायी हो जाएगी।

केन्द्र सरकार के अंदर चारों ओर से रिसाव को छिपाने की ख़ातिर प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन से एमरजेंसी का राग छेड़ दिया। बात दरअसल यह है कि वर्तमान चुनावों में मोदी की तानाशाही और संविधान विरोध इस क़दर खुलकर सामने आ गया कि अब उसका इनकार नामुमकिन है। इसलिए अब प्रधानमंत्री के पास सिर्फ़ यही चारा रह गया है कि वह बताएँ उनसे ज़्यादा संविधान की दुश्मन काँग्रेस है और यह साबित करने की उन्हें 49 साल पुरानी एमरजेंसी का राग अलापना पड़ा। इस कूटनीति के अन्दर यह सन्देश भी छिपा है कि अब काँग्रेस को मुस्लिम-समर्थक या हिंदू-विरोधी कह देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि लोग इस झाँसे में नहीं आते। यही वजह है कि काँग्रेस को संविधान का दुश्मन कहा जा रहा है जो हिंदुत्व के नफ़रती नैरेटिव की हार को स्वीकार करना है। मोदी ने अपने तानाशाही रवैये को बदलने के बजाय काँग्रेस को अपने से बड़ा डिक्टेटर साबित करने की मुहिम में स्पीकर के साथ राष्ट्रपति को भी शामिल करके दोनों की मिट्टी पलीद कर दी।

प्रधानमंत्री के सलाहकारों में लेशमात्र भी बुद्धि होती तो वे उन्हें एमरजेंसी को मुद्दा बनाने का मशवरा नहीं देते। इसकी पहली वजह तो यह है कि ऐसा करने से मोदी की अघोषित एमरजेंसी की इंदिरा गाँधी की घोषित एमरजेंसी से तुलना शुरू हो गई और वह बुरी तरह फँस गए। इसमें कोई शक नहीं कि एमरजेंसी घोषित हो या अघोषित दोनों हालतों में बुरी चीज़ है, मगर घोषित हो तो उसको कुछ सीमाओं का पाबंद होना पड़ता है, जबकि बिना एलान के वह बिलकुल बे-नकेल ऊँट की तरह जहाँ चाहे मुँह मारती फिरती है, यानी दोनों में पालतू और नील गाय का फ़र्क़ है। दोनों के कार्यकाल में भी बहुत बड़ा अन्तर है। इंदिरा गांधी ने 21 महीनों बाद एमरजेंसी उठा ली थी। मोदी तो दस साल बाद भी उठाने का नाम नहीं लेते। इंदिरा गाँधी ने तो चुनावों से पहले एमरजेंसी उठाकर सारे विरोधियों को रिहा कर दिया था, जबकि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले पकड़-धकड़ तेज़ कर दी। झारखंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान जेल में रहे और अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए सरकारी वकील ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया। इसका मतलब है कि इंदिरा गाँधी को चुनाव की हद तक विपक्ष का ख़ौफ़ नहीं था ।

वैसे काँग्रेस ने अपनी ग़लती मानकर क़ौम से माफ़ी माँग ली, लेकिन मोदी जी से यह मुमकिन नहीं है। वह तो न चीन की घुसपैठ को स्वीकार करते हैं और न चुनावी हार को मानते हैं। घमंड में डूबे मोदी का तथ्यों से इनकार करके अपनी ग़लतियों पर आग्रह ही उनकी पहचान है। एमरजेंसी के बारे में लंबी-चौड़ी हाँकनेवाले प्रधानमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके मातृ संगठन आरएसएस ने इंदिरा गाँधी के सामने दया की भीख माँगने के साथ उसकी तारीफ़ भी की थी। सरसंघचालक बाला साहिब देवरस ने कई बार यरवदा जेल से इंदिरा गाँधी को माफ़ीनामा लिखकर जयप्रकाश नारायण से कोई सम्बन्ध न होने की बात करने के साथ कुख्यात 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सहयोग का यक़ीन दिलाया था। इंदिरा गाँधी को जयप्रकाश के साथ आन्दोलन नहीं चलाने का वादा करके अटल जी पैरोल पर बाहर आए तो जेल नहीं लौटे। मोदी ख़ुद भी गिरफ़्तार होने के बजाय अंडर ग्राउंड होने का बहाना बनाकर छिपते फिरे थे।

प्रधानमंत्री और स्पीकर के एमरजेंसी वाले बयानात को सुनकर दुनिया हैरान है कि आख़िर ये लोग किस दुनिया में रहते हैं। उन्हें पचास साल पुरानी एमरजेंसी तो याद है मगर वे 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत भूल गए जिसे देश की सुप्रीमकोर्ट ने भी क़ानून का उल्लंघन क़रार दिया था। अब पाठ्यपुस्तकों में बाबरी मस्जिद को तीन गुम्बद वाली इमारत कहने से वह महापाप छिप नहीं सकता। उनको गोधरा के दंगों की याद भी नहीं आती जिसने दो हज़ार लोगों को मौत के मुँह में ढकेल दिया। भीमाकोरे गाँव के झूठे मुक़द्दमे में गिरफ़्तार बुद्धिजीवियों का ध्यान नहीं आता जिनमें से कई अब भी जेल की सलाख़ों के पीछे हैं। जिनको ज़मानत पर छोड़ा गया वे भी परेशान हैं। बीजेपी को एनआरसी आन्दोलन के दौरान देश भर में छात्रों और महिलाओं पर किए जानेवाले अत्याचारों की याद नहीं आती जिन्हें 'कपड़े' देखकर पहचाना जा रहा था। मोदी को वो सैकड़ों किसानों का ख़याल नहीं आता जो दिल्ली की सरहद पर अपनी जान गँवा बैठे और अभी हाल में मणिपुर के अंदर होनेवाले अत्याचारों की याद भी नहीं आती कि जिसकी ख़ातिर मणिपुर बीजेपी के अध्यक्ष फ़िलहाल गृहमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, मगर महाशय केन्द्र सरकार को बचाने की जोड़-तोड़ में व्यस्त हैं। एमरजेंसी का ज़िक्र छेड़कर मोदी ने जी ख़ुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है।

चुनाव परिणाम: नफरत की राजनीति और सांप्रदायिकता के अन्त का संदेश

प्रो प्रदीप माथुर

क्या 2024 के लोक सभा चुनाव स्वतंत्र भारत के राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगे, क्योंकि इनमें स्पष्ट रूप से विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार करने तथा एकता, न्याय और प्रगति के सिद्धांतों पर आधारित समाज को प्राथमिकता देने का संकेत दिया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय मतदाताओं ने राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णायक योगदान दिया है और गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी जैसे व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। चुनाव परिणामों ने पिछली भाजपा नीत सरकार की नफरत की राजनीति, विपक्ष को दबाने के लिए संवैधानिक एजेंसियों के इस्तेमाल और बड़े व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भेजा है, जो असमान विकास और बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं।

542 सदस्यों वाले सदन में 243 सीटें हासिल करके, INDIA गठबंधन की जीत का श्रेय किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और नागरिक समाज के समर्थन को दिया जाता है। विपक्षी दलों को अपनी नई ताकत का श्रेय जनता के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को जाता है, जिन्होंने सत्ता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका नेतृत्व विपक्ष को करना चाहिए था।

लोगों ने न केवल अपने वोट डाले, बल्कि सरकार के खिलाफ मोर्चा भी संभाला। वोट को प्रभावित करने वाले कारकों में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार और धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिकता शामिल थे। जबकि शहरी मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर अधिक था, ग्रामीण मतदाताओं ने विपक्षी गठबंधन का भारी समर्थन किया।

INDIA गठबंधन की जीत का श्रेय किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और नागरिक समाज के समर्थन को दिया गया। लोगों ने नफ़रत, तानाशाही और सांप्रदायिकता की राजनीति को नकार दिया और इसके बजाय अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को चुना।

चुनाव परिणामों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से निपटने और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व को उजागर किया। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन चुनाव परिणाम जनता की आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्र को आकार देने का एक आशाजनक अवसर प्रदान करते हैं।उत्तर प्रदेश में मतदाताओं ने नफरत की राजनीति को नकार दिया और भगवा पार्टी की मंदिर-मस्जिद राजनीति के महाकेन्द्र अयोध्या में भी भाजपा को चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा। यह नफरत और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को सीधा झटका था।

महाराष्ट्र में यह झटका इसलिए लगा क्योंकि मतदाताओं ने जोड़-तोड़ और दबाव वाली राजनीतिक प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें विपक्षी दलों को तोड़ना और ऐसा करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना भी शामिल था।

परिणामों और उनके निहितार्थों के विश्लेषण से पता चलता है कि लोगों को 'एक पार्टी, एक नेता, एक भाषा, एक धर्म' की अवधारणा अस्वीकार्य लगी है। उन्होंने राजनीति के बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है और पुष्टि की है कि भारत कई धर्मों, संस्कृतियों और विविधताओं का देश है, और देश पर केवल आम सहमति से ही शासन किया जा सकता है।

चुनाव परिणाम मोदी सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद की गई कुछ बड़ी गलतियों के खिलाफ एक स्पष्ट फैसला था। पहली थी नफरत की विभाजनकारी राजनीति, जिसने कुछ समुदायों को अलग-थलग करने और उन्हें कलंकित करने की कोशिश की। इसमें समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर डालना और परेशान करना, ज़हरीले आख्यान फैलाना और सामाजिक बंधनों को तोड़ना शामिल था। विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), चुनाव आयोग और अदालतों जैसी संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करना दूसरी गलती थी। इससे कम नहीं, देश की संपत्ति को चंद लोगों के हाथों में केंद्रित करने वाले क्रोनी पूंजीवाद को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया।

भाजपा के कुशासन के खिलाफ संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पांच प्रमुख राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु - ने निभाई, जिनमें कुल मिलाकर 249 लोकसभा सीटें हैं। इन राज्यों में मतदाताओं ने नफरत की राजनीति को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया, जिससे पार्टी के प्रभुत्व को बड़ा झटका लगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा को भारी झटका लगा है, फिर भी किसी भी तरह की लापरवाही से सावधान रहना होगा क्योंकि विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। विपक्ष को लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने और शांति और सद्भाव का माहौल बनाने के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है।

भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर 2024 के आम चुनावों के परिवर्तनकारी प्रभाव ने देश के मतदाता समुदाय के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया है। चुनाव परिणाम भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से गरीब समुदाय के लिए एक शानदार सफलता रही है।

राजनीति का मतलब राज्य की नीति को प्रभावित करना है, न कि सिर्फ़ सांसदों का चुनाव करना। लोकतांत्रिक समाजों में लोगों की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, जो बदले में शासन और राज्य की नीति निर्माण के लिए सकारात्मक एजेंडा तैयार करता है।

चूंकि हम इस वर्ष चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हैं, इसलिए इन संसदीय चुनाव परिणामों से उत्पन्न गति को बनाए रखने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।

आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने देश को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आकार देने का एक आशाजनक अवसर प्रदान किया है। सभी हितधारकों - सरकार, विपक्षी दल और नागरिक समाज - को मतदाताओं की आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए और एक सच्चे लोकतांत्रिक, समावेशी और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।

बजट: क्या विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा?

प्रो. लल्लन प्रसाद

वित्त मंत्री द्वारा 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में दीर्घकालिक विकास का दृष्टिकोण है - जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर भी, गरीबों, किसानों, असंगठित श्रमिकों, एसएमई, युवाओं और गृहिणियों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। 144 करोड़ लोगों के लिए 48 लाख करोड़ रुपये के बजट की कुछ प्रमुख विशेषताएं राजकोषीय समेकन, पूंजीगत व्यय, कौशल विकास, प्राकृतिक खेती और फसल उत्पादकता, हरित निवेश और अनुसंधान, सभी के लिए आवास और कर व्यवस्था का सरलीकरण हैं।

राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पिछले साल के सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% से घटाकर 4.9% कर दिया गया है। 2026-27 से सरकार का इरादा हर साल घाटे को इस तरह बनाए रखना है कि केंद्र सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घटता रहे। 2024-25 के दौरान सरकार का सकल उधार 14.01 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जो बहुत ज़्यादा है और इसे कम करने की ज़रूरत है। सब्सिडी पर सरकारी खर्च पिछले साल के 413958 करोड़ रुपये के मुकाबले 381175 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी दोनों पर खर्च जो सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसे कम किया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय 11.1 करोड़ रुपये रखा गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। हालांकि, राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण सहित 2024-25 के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय का आंकड़ा 15 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री द्वारा घोषित रोजगार बढ़ाने वाले उपायों में विनिर्माण क्षेत्र की फर्मों के लिए प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा के लिए सस्ते ऋण, युवाओं के लिए कंपनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम और छोटे व्यवसायों को ऋण प्रवाह शामिल हैं। सरकार की योजना 2 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने, 1000 प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने और 10 मिलियन लोगों को 500 शीर्ष फर्मों में इंटर्नशिप प्रदान करने की है, जिसमें एक वर्ष के लिए 5000 रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा। 5 वर्षों में सरकार 41 मिलियन युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बना रही है। सरकार को एहसास है कि उसके बढ़ते कार्यबल के लिए पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां नहीं बनाई गई हैं। जून 2024 में बेरोजगारी दर 9.2% थी। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें एक मॉडल पर कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करना और कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी के अवसर पैदा करना शामिल है। गृहिणियों की मुख्य समस्या खाद्यान्न, सब्जियां, दूध और रसोई की अन्य दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की बढ़ती लागत है, जिसे बजट में प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया गया है। शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए 2024-25 के लिए 822576 करोड़ रुपये और सड़क के लिए 54000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

"2024-25 के केंद्रीय बजट में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। प्रमुख पहलुओं में राजकोषीय समेकन, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, और कृषि अनुसंधान पर ध्यान शामिल हैं। हालांकि, गरीबों, किसानों, और एसएमई की जरूरतें पूरी तरह से संबोधित नहीं की गई हैं।"

2023-24 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट में अनुपात के लिहाज से स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर खर्च बढ़ाया गया है, हालांकि यह 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की तुलना में काफी कम है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों को स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% और शिक्षा पर 6% खर्च करना चाहिए।

कृषि को सरकार की 9 शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। भारतीय किस्मों की उत्पादकता और विकास बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है। सरकार 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में पेश करेगी। पीएम किसान के लिए बजट में 60000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो नकद हस्तांतरण योजना है। सरकार आपूर्ति को बढ़ावा देने और बाजार में अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए बड़े शहरों के आसपास सब्जी फार्मों के समूह स्थापित करने की भी योजना बना रही है। बजट में किसानों के डेटाबेस और कृषि-स्टॉक के साथ डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को जोड़ने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने अधिक रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। बजट में प्राकृतिक खेती के लिए आवंटन 365 करोड़ रुपये है। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है, जो इस क्षेत्र के योगदान को देखते हुए अपर्याप्त है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 5 राज्यों में जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए

जाएंगे। झींगा पालन और कृषि उत्पादों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। हालाँकि, किसान निराश हैं क्योंकि सरकार ने उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके बिना उनकी आय दोगुनी करना एक सपना ही रहेगा।

सरकार छोटे परमाणु रिएक्टरों, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों तथा उन्नत अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित एक विविध ऊर्जा योजना की योजना बना रही है। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।

कृषि के बाद एमएसएमई सबसे बड़े नियोक्ता हैं। बजट में मशीनरी और उपकरण खरीदने में मदद के लिए जमानत-मुक्त ऋण गारंटी योजना को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। पीएसयू बैंकों को इस क्षेत्र की ऋण मांग तक पहुँचने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक नए ऋण मूल्यांकन मॉडल की परिकल्पना की गई है। जीएसटी प्रक्रिया के सरलीकरण और दरों के युक्तिकरण की आवश्यकता है, जिस पर सरकार ने विचार नहीं किया है। एंजल टैक्स को समाप्त करने और गैर-सूचीबद्ध सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में कमी से उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेशकों को लाभ होगा।

बिहार और आंध्र को विकास के लिए विशेष पैकेज दिए गए हैं। बिहार को सड़क संपर्क परियोजनाओं, नए हवाई अड्डे और खेल बुनियादी ढांचे के लिए 26000 करोड़ रुपये और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11500 करोड़ रुपये मिले हैं, जो राज्य की एक प्रमुख मांग रही है। आंध्र को अमरावती में राजधानी विकसित करने के लिए 15000 करोड़ रुपये मिले हैं। गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने और दो प्रमुख औद्योगिक गलियारों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए भी राज्य को धन जारी किया जाएगा। ओडिशा को भी ऐसे पैकेज की जरूरत है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया है।

बजट की प्राथमिकताओं में से एक है कर व्यवस्था का सरलीकरण और पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था को बढ़ावा देना, जिससे बचत को प्रोत्साहन मिले। नई आयकर व्यवस्था में कर की दरें थोड़ी कम की गई हैं, जिसमें निवेश पर कोई कटौती नहीं की गई है। मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इन उपायों से व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा देय कर में कुछ कमी आएगी। हालांकि, पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है और इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि लोग अधिक खर्च करें और कम बचत करें, ताकि वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मांग बढ़े, लेकिन इससे बचत की आदतें प्रभावित हो सकती हैं। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे अंतरिक्ष, रक्षा दूरसंचार, हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। सोने और चांदी के आभूषणों और विनिर्माण के लिए कपड़ा और चमड़े के इनपुट पर सीमा शुल्क में कटौती का स्वागत है।

---

10 विकास स्तंभों पर आधारित सरकार बचाओ बजट

प्रो शिवाजी सरकार

यह एक गठबंधन बजट है जिसमें निगम के माध्यम से रोजगार सृजन का वादा किया गया है, तथा विवादित सहयोगियों को बड़े पैकेज के साथ संतुष्ट करना तथा राज्यों को बहुपक्षीय बैंक वित्तपोषण के लिए खोलना एक कठिन कार्य है, जो एक दुविधा बन सकता है।

राजनीति और गठबंधन के पास 4 जून, 2024 का संदेश है, जो अर्थव्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण में कम से कम एक स्पष्ट बदलाव के लिए बेंचमार्क बन गया है। मुद्रास्फीति नियंत्रण अब एक प्राथमिकता के रूप में उभरा है। सरकार का दावा है कि मुद्रास्फीति कम हुई है, लेकिन RBI का कहना है कि यह 5.1 प्रतिशत या उससे अधिक पर बनी हुई है।

नई आयकर दरों में परिवर्तन स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ ही 30 प्रतिशत की दर से 20 लाख रुपये की आय वाले स्लैब को 15 लाख रुपये पर पहुंचा दिया गया है, जो पहले निचले स्लैब में था।

पूंजीगत लाभ कर में बदलाव से करों में अधिक व्यय होगा क्योंकि 2001 के बाद इंडेक्सेशन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। इससे कई सौदे नकद में हो सकते हैं क्योंकि पुरानी दरों और नई दरों के बीच व्यय अधिक होगा। इसे रोकने के लिए सरकार को इंडेक्सेशन की प्रणाली को जारी रखना चाहिए।

> ***"2024 का केंद्रीय बजट एक गठबंधन सरकार का पहला बजट है, जिसमें रोजगार सृजन और मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। 2 लाख करोड़ रुपये रोजगार योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, और कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। हालांकि, नई कर नीतियां और पूंजीगत लाभ कर में बदलाव से व्यय में वृद्धि हो सकती है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिए गए हैं, लेकिन ओडिशा को नजरअंदाज किया गया है।"***

कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन अपर्याप्त है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम के लिए अलग से 1.64 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि आवंटित की गई है। कृषि की वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत से घटकर 1.4 प्रतिशत रह गई है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो प्रधानमंत्री के मत्स्य संपदा कार्यक्रम की सफलता है।

सोने पर कर 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना शादी से पहले के मौसम में अच्छा है। हालांकि, सोने की कीमत में वृद्धि होगी क्योंकि यह वैश्विक मुद्रा बन रहा है।

बिहार और आंध्र प्रदेश इन राज्यों में निर्माण लॉबी की उदारता और तेजी के लाभार्थी हैं। अमरावती के निर्माण से आंध्र के निर्माण और अन्य उद्योगों को कई लाभ होंगे और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का प्रभाव बढ़ेगा। राज्य में कम से कम दो प्रमुख औद्योगिक गलियारे प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है कि इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के बहुआयामी निर्माण और नालंदा और गया को तीर्थस्थलों से पर्यटन स्थलों में बदलने से पुरानी और शायद प्राचीन संरचनाओं का बहुत विनाश होगा, जैसा कि यूपी के तीर्थस्थलों में हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख गठबंधन सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महत्व देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की।

गया और नालंदा की समीक्षा करें, जहां पिछले कई सालों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, लेकिन सावधानी की जरूरत है ताकि बुनियादी ढांचे में बदलाव न हो। गया में उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। यह पारिस्थितिकी और सौंदर्य की दृष्टि से मेल खाना चाहिए।

चाहे आंध्र प्रदेश हो या बिहार, विकास सिर्फ़ रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यूपी में कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है और शहरों में बिना किसी मुआवज़े या मामूली रकम के आवासों का विनाश देखा गया है। राज्यों में यह आवाज़ उठ रही है कि सभी को विशेष देखभाल की ज़रूरत है, जो आंध्र और बिहार को दी गई है, जो विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। लेकिन एक बहुपक्षीय संस्थागत खिड़की खुल गई है। सीतारमण ने राज्यों को 50 साल के ऋण के प्रावधान की भी घोषणा की जिसे 2073 में चुकाना होगा। यह एक सौगात है जैसा कि कुछ राज्य देख सकते हैं लेकिन यह भविष्य की पीढ़ी पर बोझ भी है।

बजट में कृषि, रोजगार, समावेशी विकास, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नवाचार-अनुसंधान और अगली पीढ़ी के सुधारों के आधार पर विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया है। फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट का आधार यही था। वित्त सचिव सोमनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि बजट का मूल फोकस नहीं बदला है। बजट का मुख्य विषय नौकरियों या रोजगार का गुलदस्ता है, जिसे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था। इस पर कुल 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसका उद्देश्य कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना और लोगों को 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में अप्रेंटिसशिप सहित नौकरियों के लिए तैयार करना है। यह बेरोजगारी की वृद्धि को संबोधित करने के लिए है जो 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने से पहले ही एक समस्या बन गई थी। यह शायद पहली बार है जब बजट रोजगार और युवाओं में रोजगार सृजन पर केंद्रित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने इस मुद्दे को उजागर किया।

सरकार अगले पांच साल या 2029 के चुनावों तक हर साल एक करोड़ नौकरियां पैदा करना चाहती है। इसका मतलब है कि 500 कंपनियों में से प्रत्येक को, जिसमें बिजली संयंत्र, रिफाइनरी और रसायन जैसे महत्वपूर्ण और सुरक्षा संबंधी मुद्दे शामिल हैं, को 6000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रोत्साहन पाने के लिए 4000 लोगों को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करना होगा। कंपनियों को उन्हें 12 महीने तक बनाए रखना होगा। प्रशिक्षुता कार्यक्रम दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी शुरू किया था। इसे सीमित सफलता मिली थी। स्वचालित सॉफ्टवेयर-नियंत्रित संचालन में, कुछ कंपनियों को बड़े कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। खर्च का एक हिस्सा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पूरा किया जाना है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देना कई लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है।

यद्यपि इरादा अच्छा है, परन्तु वास्तविक लाभार्थी बहुत कम हो सकते हैं।

यह भाजपा की ओर से एक सार्थक प्रतिक्रिया है और साथ ही एक कहानी भी गढ़ने का काम करती है। सरकार को हरियाणा के युवाओं की ज़रूरतों के हिसाब से अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करना चाहिए। सशस्त्र बलों में भर्ती पहले की तरह ही जारी रह सकती है।

मुद्रा योजना के तहत ऋण दोगुना करके 20 लाख रुपये कर दिया गया है। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए इसे पर्याप्त नहीं माना जाता है। सीमा-सीमा की आवश्यकताएं अधिक हैं।

कृषि क्षेत्र में बागवानी पर और अधिक जोर दिया गया है और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल 32 किस्मों की 109 किस्मों का विकास किया जा रहा है। बागवानी और सब्जी उत्पादन में 200 लाख टन से अधिक की वृद्धि हुई है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि चावल, गेहूं या सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव न हो जिससे उच्च मुद्रास्फीति हो।

राजकोषीय पक्ष पर, सरकार ने सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाया है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत तक कम हो गया है। इसका मतलब यह भी होगा कि सरकार 11.9 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय सहित अपने खर्चों में सावधानी बरतेगी। बड़े पैमाने पर खर्च करने के बजाय, यह अधिक चयनात्मक होगा जैसा कि उसने रेलवे के लिए किया है, जहां सबसे बड़ा इंफ्रा फंड सुरक्षा और सिग्नलिंग मुद्दों पर खर्च किया जाएगा।

कुल मिलाकर, अंतरिम बजट की निरंतरता के बावजूद, वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो अपने दृष्टिकोण में अलग है, हालांकि इसमें मुद्रास्फीति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और देश के विकास को मजबूत करना है।

कमज़ोर सरकार का मजबूर बजट

डॉ सलीम ख़ान

दस वर्ष शासन करने के बाद एक मजबूर सरकार का कमज़ोर बजट सामने आया। इसी लिए चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह हारने के बावजूद विपक्ष जश्न मना रहा था, उसी तरह बजट को देखकर विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है। यक़ीन न आता हो तो नौ बार बजट पेश करके रिकार्ड बनानेवाले वित्तमंत्री पी चिदम्बरम की टिप्पणी देखें—

"मुझे यह जानकर ख़ुशी हुई कि माननीय वित्तमंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद काँग्रेस के घोषणापत्र (लोकसभा) 2024 को पढ़ा है। मुझे ख़ुशी है कि उन्होंने काँग्रेस के घोषणापत्र के पृष्ठ 30 पर उल्लिखित रोज़गार से सम्बन्धित प्रेरणा को व्यावहारिक रूप से अपना लिया है।" उन्होंने काँग्रेस के घोषणापत्र में दर्ज प्रशिक्षुता योजना (Apprenticeship Scheme) को लागू करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इसी पूर्व वित्तमंत्री चिदम्बरम ने केन्द्र सरकार के 2021-22 के बजट की बाबत कहा था कि "यह अमीरों का, अमीरों के लिए, अमीरों के द्वारा लाया गया बजट है।"

चिदम्बरम ने आरोप लगाया था कि केन्द्र सरकार ने बजट में ग़रीबों, बेरोज़गारों और एमएसएमई सेक्टर को पूरी तरह से नज़र-अंदाज़ कर दिया है। राज्य सभा के अंदर उन्होंने कहा था कि "सबसे हक़दार वर्ग यानी ग़रीब, किसान, परदेसी मज़दूर, एमएसएमई सेक्टर, मध्यम वर्ग और बेरोज़गार को उनकी क़िस्मत पर छोड़ दिया गया है।" इसके साथ देश के 73 प्रतिशत संसाधनों का कंट्रोल करनेवाले एक प्रतिशत लोगों की आलोचना करने बाद ग़रीबों के हाथ में पैसा और मुफ़्त राशन पहुँचाने की माँग की थी, मगर अब कह रहे हैं, "काश, एफ़एम ने काँग्रेस के घोषणापत्र में कुछ और बातें भी नक़्ल की होतीं। मैं जल्द ही रह जानेवाली बातों की सूची दूँगा।" इस तरह बजट के बाद जहां काँग्रेस बग़लें बजा रही है और वहीं मोदी भक्त रो रहे हैं, क्योंकि अगर यही बजट पिछले वर्ष पेश कर दिया जाता तो चुनाव परिणामों के बाद ऐसा बुरा हाल नहीं होता, लेकिन कहावत मशहूर है—

> ***2024 का बजट विपक्ष द्वारा 'मोदी सरकार बचाओ' बजट कहा जा रहा है, जिसमें गरीबों और बेरोज़गारों के लिए ठोस राहत नहीं दिख रही।***

आछे दिन पाछे गए पर से किया न हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत

नरेंद्र मोदी जैसे आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री से यह आशा तो सम्भव ही नहीं है कि वह यह स्वीकार

कर लेंगे कि "जी हाँ, ठोकर लगी तो अक़्ल ठिकाने आई," मगर उन्होंने यह ज़रूर कहा कि "मैं इस महत्वपूर्ण बजट के लिए तमाम देशवासियों को बधाई देता हूँ जो देश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाएगा।" वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देने के बाद मोदी बोले, "यह बजट समाज के हर वर्ग को संबल प्रदान करनेवाला है। यह देहातियों, ग़रीबों और किसानों को ख़ुशहाली की राह पर अग्रसर कर देगा।" उन्होंने दावा किया पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग ग़रीबी से बाहर आए हैं। यह बजट नव-मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले का बजट है। यह एक ऐसा बजट है जो युवकों को अनगिनत अवसर प्रदान करेगा। मोदी ने बजट के द्वारा शिक्षा और हुनरमंदी को नई बुलंदियों पर ले जाने का वादा करके मध्यम वर्ग को नई शक्ति पानेवाला बताया। उनके अनुसार बजट में आदिवासी समाज, दलितों और पिछड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की ठोस योजनाएँ हैं। मोदी ने दावा किया कि बजट से महिलाओं की आर्थिक साझेदारी को यक़ीनी बनाने में मदद मिलेगी।

मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत करनेवाले प्रधानमंत्री अपने चहेते पूँजीपतियों को बिलकुल भूलकर कहने लगे कि यह बजट छोटे व्यापारियों, और मध्यम श्रेणी की व्यापारिक संस्थाओं (एमएसएमई) को विकास का एक नया मार्ग प्रदान करेगा। इस टिप्पणी को पढ़ते वक़्त ऐसा लग रहा था कि राहुल गाँधी की आत्मा उनके अंदर घुसकर के उनसे कहलवा रही है कि "रोज़गार और आत्मनिर्भरता के बेमिसाल अवसर पैदा करना सरकार की शनाख़्त रही है।" यह किस सरकार की पहचान रही है यह कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री के अनुसार इस बजट में दर्ज इम्पलाइमेंट लिंक इनसेंटिव स्कीम (Employment Linked Incentive Scheme) से देश में करोड़ों नई नौकरियाँ पैदा होंगी। इसके तहत सरकार ज़िंदगी में पहली नौकरी पानेवाले नौजवानों को पहला वेतन देगी। क्यों देगी? यह कोई नहीं जानता। निपुणता में बेहतरी और उच्च शिक्षा के लिए सहयोग से एक करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप स्कीम (Internship Scheme) का लाभ मिलेगा। उसके द्वारा देहाती और ग़रीब नौजवानों को बड़ी कंपनियों में काम मिलेगा। प्रधानमंत्री के ये लच्छेदार जुमले 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' लगते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बड़ी क़लाबाज़ी के बावजूद विपक्ष ने आम बजट 2024 को निराशाजनक क़रार दिया। काँग्रेस को शिकायत है कि इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे ग़ायब हैं। शशि थरूर ने देश के अन्य राज्यों को नज़र-अंदाज़ करके बिहार और आंध्र प्रदेश को राजनैतिक कारणों से सन्तुष्ट करने का आरोप लगाया। संयोग से नज़र-अंदाज़ होनेवालों में बीजेपी का गढ़ गुजरात, एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्य भी शामिल हैं, जिनके कारण बीजेपी 240 तक पहुँच सकी। उन वफ़ादारों के साथ बीजेपी ने वही सुलूक किया जो 'इंडिया' गठबंधन की पार्टियाँ मुसलमानों के साथ करती हैं। बजट के हवाले से राहुल गाँधी ने एक्स पर लिखा, "यह कुर्सी बचाओ बजट है, जिसमें गठबन्धन मित्रों को ख़ुश किया गया है। अभिजात वर्ग को लाभ दिए गए हैं, लेकिन आम भारतवासियों के लिए कोई राहत नहीं है। यह बजट काँग्रेस के चुनावी घोषणापत्र और पूर्व बजटों की नक़्ल भर है।"

यह विचित्र संयोग है कि वर्तमान बजट के हवाले से काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर रेवड़ियाँ बाँटने का आरोप लगा दिया। एक ज़माने में मोदी यही एतिराज़ काँग्रेस पर किया करते थे।

खड़गे ने कहा, "मोदी सरकार का बजट अपने गठबन्धन मित्रों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवड़ियाँ बाँट रहा है, ताकि एनडीए बचा रहे। यह देश के विकास का बजट नहीं, बल्कि 'मोदी सरकार बचाओ' बजट है और बीजेपी जनता को धोखा दे रही है।" काँग्रेस अध्यक्ष के अनुसार, "10 वर्ष बाद इन नवयुवकों के लिए सीमित उद्घोषणाएँ की गईं जिन्हें वार्षिक दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया गया था। किसानों के लिए सिर्फ़ सतही बातें हुई हैं, डेढ़ गुना एमएसपी और आमदनी दोगुनी करना चुनावी फ़्राड निकला। इस सरकार का ग्रामीण वेतनों में वृद्धि का कोई इरादा नहीं है।" जय राम रमेश ने ध्यान दिलाया कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं कराई गई। आज़ादी के बाद यह पहला मौक़ा है कि दस वर्ष तक यह अभ्यास नहीं हुआ और इस बजट में भी जनगणना के लिए फ़ंड्ज़ का उल्लेख नहीं है। इसके समय पर न होने से 10-12 करोड़ लोग नेशनल फ़ूड सेक्योरिटी एक्ट के दायरे से बाहर हो जाते हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको ग़रीब विरोधी, जनता का दुश्मन, राजनैतिक रूप से पक्षपातवाला बजट कह दिया। उनके अनुसार बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं देकर राज्य का अपमान किया गया है और लोग उसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बोले, "10 वर्षों में सिर्फ़ बेरोज़गारी बढ़ी है। सरकार ख़ुद को बचाने के लिए सिर्फ़ बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाएँ दे रही है।" शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस बजट का नाम 'पीएम सरकार बचाओ योजना' होना चाहिए, क्योंकि अगले 5 वर्ष तक सरकार बचाने के लिए, दोस्तों को ख़ुश करने के लिए, विशेष हैसियत दिए बिना फ़ंडिंग की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बिहार को 47 हज़ार करोड़ देने के बाद वहीं औद्योगिक कॉरीडोर बने तो उतर प्रदेश और झारखंड के मतदाता बीजेपी को वोट क्यों दें? आंध्र प्रदेश को 15 हज़ार करोड़ मिल जाएँ तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्य स्तरीय चुनावों में बीजेपी कामयाब कैसे हो।

दस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ने 'बहुत हुई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार' का नारा लगाकर कहा था कि हर वर्ष दो करोड़ नौकरियाँ देंगे, मगर जब बहुमत प्राप्त हो गया तो उन्हें 'जुमला' कहकर उड़ा दिया गया। अब बहुमत से महरूमी के बादवाले बजट में एलान किया गया कि महंगाई कंट्रोल में है, हालाँकि यह दावा खोखला है। इस बार ग़रीबों, महिलाओं, युवकों और किसानों पर बजट केन्द्रित करने की कम-से-कम बात तो की गई है। रोज़गार बढ़ाने के लिए 3 बड़ी योजनाओं पर काम करने का वादा किया गया है और इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपये तय किए गए हैं। छात्रों को 7.5 लाख रुपयों का स्किल मॉडल क़र्ज़ देने की बात भी की गई है। कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पीएफ़ के साथ महिलाओं को प्राथमिकता देने पर ज़ोर है। इस वर्ष कृषि और उससे सम्बन्धित विभागों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए हैं, तथा मुफ़्त राशन की व्यवस्था 5 वर्ष तक जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। मगर जल्द ही जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट से जो आशाएँ थीं वे निराशा में बदल गईं । अगले चार महीनों के अंदर राज्य स्तर के चुनावों में बीजेपी को इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे इस बजट में बीजेपी की कमज़ोरी ने 'एनडीए' के 'शेर' को 'इंडिया' की 'बकरी' बना दिया है।

भारत और रूस की मित्रता का विरोधी अमेरिका

डॉ जॉन दयाल

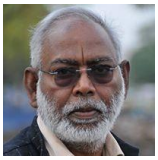

अमेरिका ने पहली बार भारत से स्पष्ट रूप से अपनी विदेश नीति बदलने और अमेरिकी खेमे में शामिल होने का साहसिक अनुरोध किया, न की केवल चीन को नियंत्रित करने तक सीमित रहे।

इस सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया और रूस से लौटे, जहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने संघर्ष रेखाओं के पार नेताओं के साथ मोदी की स्पष्ट निकटता के कारण भारत के शांति निर्माता होने के दावे पर अपने देश की निराशा व्यक्त की।

राजदूत गार्सेटी ने नई दिल्ली में आयोजित अमेरिका-भारत रक्षा समाचार सम्मेलन में कहा: "अब कोई युद्ध दूर नहीं है, और हमें सिर्फ़ शांति के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें ठोस कदम उठाने चाहिए... अमेरिका और भारत को मिलकर यह जानने की ज़रूरत है।"

उन्होंने कहा, "संकट के समय हमें एक-दूसरे को विश्वसनीय मित्र के रूप में जानना होगा। जरूरत पड़ने पर हम एक साथ काम करेंगे, एक-दूसरे के उपकरण, प्रशिक्षण, प्रणालियों और मानवता को समझेंगे।"

यह भारत को रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अमेरिका और नाटो के साथ शामिल होने का निमंत्रण है। भारत, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान, क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा रक्षा) के भाग के रूप में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ था, जिसने भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के विरुद्ध सबसे बड़ी शक्ति का सृजन किया है।

विदेश नीति में बदलाव

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं और चीन के साथ लगातार तनावों के बीच भारत की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर रूस और चीन के साथ संबंधों को लेकर।

हाल के दशकों में भारत अपने पड़ोस में एक दबंग बड़े भाई की तरह रहा है, जो उत्तर में सैन्य रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली, तथा तकनीकी और इसलिए आर्थिक रूप से कहीं अधिक उन्नत पड़ोसी के आगे अनिच्छा से झुकता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है।

पाकिस्तान, जिसके साथ भारत ने 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद से चार बार युद्ध किया है, भारत की विदेश और घरेलू नीतियों में एक अजीब इकाई रहा है। मुस्लिम बहुल पाकिस्तान पर अक्सर भारत में आतंकवादियों को भेजने का आरोप लगाया जाता है, खास तौर पर कश्मीर घाटी में।

चीन ने शायद इसके तुरंत बाद पाकिस्तान को अपना परमाणु बम परीक्षण करने में मदद की। दुनिया के लिए, यह सिर्फ़ एक आधिकारिक प्रदर्शन था कि दो दक्षिण एशियाई देश अब परमाणु शक्ति बन गए हैं - एक ऐसा तथ्य जो उन्हें सालों से पता था।

मोदी शायद इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि चीन और उससे भी अधिक उसके निरंकुश शासक शी जिनपिंग से कैसे निपटा जाए। मोदी द्वारा शी को लुभाने के लिए किए गए अनेक प्रयास - चाहे आतिथ्य, इतिहास या वैश्विक राजनीति के माध्यम से - भारत के साथ 3,360 किलोमीटर (2,100 मील) की सीमा पर चीन के बढ़ते दावे को रोकने में बहुत कम सफल रहे हैं।

यूक्रेन-रूस युद्ध पर मोदी की तटस्थ नीति को यूरोप के राजनीतिक और मानवाधिकार हलकों में अनुचित और अनैतिक माना जा रहा है। इसके बावजूद, मोदी ने पश्चिमी देशों को भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है।

ग्रीष्म ऋतु के चुनावों में कई यूरोपीय देशों में नए नेतृत्व उभरे, लेकिन जनता मानती है कि भारत आदर्शवादी नहीं बल्कि अवसरवादी है।

एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से एक तीव्र गिरावट है, जिन्होंने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाने में मदद की थी।

उन्होंने पांच सिद्धांतों की पुनः पुष्टि में मदद की, जो राष्ट्रों के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करने चाहिए - संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, अहिंसा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

भारत की विदेश नीति मजबूत रही, तथा नेहरू से लेकर भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने तटस्थता और शांति की भावना को बरकरार रखा।

अमेरिका का साहसिक अनुरोध

अमेरिका ने पहली बार भारत से स्पष्ट विदेश नीति बदलने और अमेरिकी खेमे में शामिल होने का साहसिक अनुरोध किया है, जो केवल चीन को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध झेला, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके साथ ही, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया।

वाजपेयी, जिनकी भाजपा पार्टी ने 1992 में 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए निंदा झेली थी, ने बाद में 1998 में प्रधानमंत्री के रूप में पोखरण के उसी परीक्षण मैदान में परमाणु विखंडन उपकरण के परीक्षण का आदेश दिया। यह किसी अन्य नाम से परमाणु बम था। पश्चिमी देश नाराज़ दिखे, लेकिन उन्होंने कोई दंडात्मक कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की।

चीन ने शायद इसके तुरंत बाद पाकिस्तान को अपना परमाणु बम परीक्षण करने में मदद की। दुनिया के लिए, यह सिर्फ़ एक आधिकारिक प्रदर्शन था कि दो दक्षिण एशियाई देश अब परमाणु शक्ति बन गए हैं - एक ऐसा तथ्य जो उन्हें सालों से पता था।

26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर मोदी के आगमन के बाद विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला है, जिसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें प्रधानमंत्री को एकमात्र सर्वव्यापी शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें तथ्य की कमी है।

अब तक मोदी ने 77 विदेश यात्राएं की हैं, जिसमें सभी महाद्वीपों के 67 देशों का दौरा किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा भी शामिल है। वे पांच बार चीन और आठ बार अमेरिका गए

हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देना भी शामिल है।

हाल के दशकों में भारत अपने पड़ोस में एक दबंग बड़े भाई की तरह रहा है, जो उत्तर में सैन्य रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली, तथा तकनीकी और इसलिए आर्थिक रूप से कहीं अधिक उन्नत पड़ोसी के आगे अनिच्छा से झुकता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है।

इसका एक उदाहरण मालदीव है, जो एक संप्रभु देश है, जिसके एटोल ऐसे हैं जो आसपास के अरब सागर की लहरों से बमुश्किल ऊपर उठते हैं। यह इतना नाराज़ हो गया कि इसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारतीय सशस्त्र बलों के समूह को समय सीमा तय करते हुए वहां से चले जाने का आदेश दे दिया।

यद्यपि संबंध थोड़े बेहतर हुए हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे, लेकिन भविष्य में दुनिया में क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

विडंबना यह है कि एकमात्र क्षेत्र जहां चीन ने भारत के सामने घुटने टेके हैं, वह है जनसंख्या। एक सदी तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में राज करने के बाद, चीन अब दूसरे नंबर पर है, एक-बच्चा नीति के कारण इसकी जनसंख्या घट रही है।

पाकिस्तान, जिसके साथ भारत ने 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद से चार बार युद्ध किया है, भारत की विदेश और घरेलू नीतियों में एक अजीब इकाई रहा है।

मुस्लिम बहुल पाकिस्तान पर अक्सर भारत में आतंकवादियों को भेजने का आरोप लगाया जाता है, खास तौर पर कश्मीर घाटी में। इस्लामिक बांग्लादेश से आए लोगों को "सफेद चींटियों" के रूप में चित्रित किया जाता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। पश्चिम और पूर्व के दो देशों के साथ भारत के जल-बंटवारे के मुद्दे भविष्य में कटुता का कारण बने हुए हैं।

बांग्लादेश की नेता शेख हसीना भारत आने वाली कोई असामान्य बात नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान के नेता भी ऐसा ही करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 2014 में मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, लेकिन इस साल जुलाई में हुए तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया।

2015 में क्रिसमस के दिन मोदी ने शरीफ और उनके परिवार से मिलने के लिए एक पोते की शादी में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने पारंपरिक सम्मान दिखाते हुए शरीफ की मां के पैर छुए, जिसकी तस्वीर दुनिया भर में फैली।

सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक विमर्श में पाकिस्तान सबसे अधिक निंदित पड़ोसी बना हुआ है, क्योंकि वह अपने बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक को इस्लामोफोबिया और विदेशी आतंकवाद के मिश्रण पर पोषित करता है, भले ही वह आक्रामकता न हो।

मोदी शायद इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि चीन और उससे भी अधिक उसके निरंकुश शासक शी जिनपिंग से कैसे निपटा जाए।

जैसा कि प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संबंध पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने एक लेख में बताया है, मोदी ने 2014 में अपने गृह राज्य गुजरात में शी के स्वागत में लाल कालीन बिछाया था, ताकि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सकें और हिमालय में दोनों देशों के बीच जटिल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आधारशिला रखी जा सके।

"लेकिन जब वे ... कार्यकर्ता महात्मा गांधी के आश्रम के बरामदे में बातचीत कर रहे थे, तो भारतीय मीडिया लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र में एक नए चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट कर रहा था। सैकड़ों चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को घूर रहे थे और भारतीय प्रशासित क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने पर जोर दे रहे थे।

पांच साल बाद, अक्टूबर 2019 में, मोदी ने शी को दक्षिण भारत के मामल्लापुरम में सातवीं सदी के मंदिरों का दौरा कराया। आठ महीने बाद, चीनी सैनिकों ने लद्दाख के गलवान में प्रवेश किया और 20 भारतीय सैनिकों को कील लगे डंडों से मार डाला। इस घटना में चार चीनी मारे गए।

नवंबर में, गलवान झड़पों के बाद पहली बार, मोदी और शी इंडोनेशिया के बाली में मिले, जब भारत ने जी-20 की अध्यक्षता संभाली और मोदी ने उन्हें एक नए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का नाममात्र का प्रमुख घोषित कर दिया। भारत को मोदी की जी-20 अध्यक्षता के 12 महीनों के जश्न में अरबों रुपये खर्च करने थे।

लेकिन बाली बैठक के कुछ सप्ताह के भीतर ही चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक पर्वतीय चौकी पर कब्जा कर लिया, जिस पर चीन अपना दावा करता है।

मोदी द्वारा शी को लुभाने के लिए किए गए अनेक प्रयास - चाहे आतिथ्य, इतिहास या वैश्विक राजनीति के माध्यम से - भारत के साथ 3,360 किलोमीटर (2,100 मील) की सीमा पर चीन के बढ़ते दावे को रोकने में बहुत कम सफल रहे हैं।

विदेश नीति ने कहा, "द्विपक्षीय संबंधों में यह गिरावट मोदी के लिए एक राजनीतिक समस्या है, जिन्होंने खुद को भारतीय जनता के सामने एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया, जो क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर नरम रुख रखते हैं। फिर भी उन्होंने चीनियों को अपने जवानों और कथित तौर पर जमीन का नुकसान पहुंचाया है।"

जहां मोदी भारत को एक कोने में धकेल रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के नए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का दावा है कि मोदी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को मनमाने ढंग से संभालते हैं, और बिना किसी सुसंगत रणनीति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते रहते हैं।

विपक्षी दलों का कहना है कि अतीत में, राजनीतिक ध्रुवीकरण के बावजूद, भारत की विदेश नीति पर व्यापक सहमति थी, विशेष रूप से चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में।

मोदी के पास सत्ता में पाँच साल हैं। यह उनकी सरकार और उनकी राजनीतिक पार्टी के लिए सुधार करने के लिए एक लंबा समय है। लेकिन अल्पावधि में, उनके लिए पड़ोस में दिए गए घावों और विदेशों में पैदा की गई शर्मिंदगी को भरना आसान नहीं होगा।

मोदी की मॉस्को यात्रा से अमेरिकी आयुध लॉबी नाराज

गोपाल मिश्रा

क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जिन्होंने कभी भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को समाप्त करने का गंभीरता से प्रयास नहीं किया, अपने राजनीतिक आधार को सुरक्षित रखने के लिए अपने देश के युद्ध उद्योग की सेवा कर रहे थे?

यह प्रश्न इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि नई दिल्ली में राजनयिक हलकों और दुनिया भर के अन्य शांतिप्रिय लोग इस महीने की शुरुआत में मास्को में मोदी-पुतिन बैठक की अमेरिका द्वारा की गई तीखी आलोचना के तर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यूक्रेन के एक वर्ग को गोल्डन वीजा देने के हालिया फैसले के संदर्भ में, जो यह संकेत देता है कि युद्ध से कुछ लोगों के लिए अभूतपूर्व समृद्धि आई है।

हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित ओबामा की प्रतिक्रिया ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ आरोप-प्रत्यारोप का खेल उजागर कर दिया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके गर्मजोशी भरे गले मिलने से शांति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मोदी के खिलाफ़ एक और कारण यह हो सकता है कि उन्होंने मॉस्को की अपनी हालिया यात्रा के दौरान भारत की शांति की अपील को दोहराया था।

शायद, उन्होंने ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी युद्ध उद्योग के साथ-साथ यूक्रेन के समकालीन शासकों सहित अमेरिका के राजनेताओं के एक वर्ग को नाराज़ कर दिया।

इसलिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन-रूस युद्ध के थमने की आशंका से न केवल हथियार और विस्फोटक बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, बल्कि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी में इन कंपनियों के हितों की सेवा करने वाले राजनीतिक चेहरों के हितों पर भी असर पड़ सकता है। इस संदर्भ में, बिडेन प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा शांति के लिए भारतीय प्रयासों की आलोचना करना स्वाभाविक था।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संघर्ष के भड़कने के बाद से ही अमेरिकी युद्ध उद्योग भारी मुनाफा कमा रहा है। फरवरी 2022 में जब पूर्वी यूरोप में युद्ध छिड़ा था, तब से उनके शेयरों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है।

मोदी की हाल की मास्को यात्रा की आलोचना का कारण अमेरिका में युद्धोन्मादी लोगों की अंतर्निहित भावना है, जिसमें राजनीतिक, सैन्य और कॉर्पोरेट नेता शामिल हैं, साथ ही यूक्रेन में सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग भी शामिल है, जो शांति प्रयासों को विफल करके अभूतपूर्व वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहा है, और इस प्रकार वे वर्तमान यूक्रेन-रूस युद्ध से प्राप्त होने वाले भारी धन का लाभ उठा रहे हैं।

मोदी की यात्रा की आलोचना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी की है, जो हास्य कलाकार से राजनेता बने हैं। नई दिल्ली या वाशिंगटन में ज़ेलेंस्की की टिप्पणियों को बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, लेकिन नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी के हालिया बयान ने भारत को आगाह किया है कि उसे अमेरिकी समर्थन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिसने नई दिल्ली में रणनीतिक मामलों के विद्वानों को खुश कर दिया है। कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और यहां तक कि उनके अराजनयिक, या असभ्य, बयान पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया।

इन बयानों के अलावा मोदी की यात्रा के खिलाफ व्हाइट हाउस के अधिकारियों की टिप्पणियां भी काफी आलोचनात्मक हैं। हालांकि, ये टिप्पणियां अब अप्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि बाइडेन का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है।

कहा जा रहा है कि मोदी की रूस यात्रा के दौरान, 30 सदस्यीय नाटो सैन्य गठबंधन के नेता वाशिंगटन में रूस के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेन को भारी सैन्य सहायता देने पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने की मीडिया कवरेज ने वाशिंगटन में युद्ध-प्रेमियों को नाराज़ कर दिया है क्योंकि उनके लिए मोदी ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता को वैध बना दिया है।

यूक्रेन-रूस युद्ध और अमेरिकी हितों का टकराव

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की शांति प्रयासों से दूरी, यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करने की बजाय अपने देश के युद्ध उद्योग को बढ़ावा देने के आरोपों के घेरे में है। मोदी की मॉस्को यात्रा पर आलोचना से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध से कुछ वर्गों को वित्तीय लाभ हो रहा है, खासकर अमेरिका के राजनीतिक, सैन्य और कॉर्पोरेट समूहों को।

बांग्लादेश के जनविद्रोह से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता

डॉ. सतीश मिश्रा

वर्ष 2009, 2014, 2019 और 2024 में चार चुनाव जीतने के बाद, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अचानक और अप्रत्याशित रूप से भाग जाना उन सभी लोगों के लिए एक गंभीर झटका है जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जीवन शैली को महत्व देते हैं।

बांग्लादेश के 50 वर्षों के अस्तित्व की नवीनतम घटना से कई सबक सीखने और भूलने की आवश्यकता है। जबकि भ्रष्टाचार, उच्च बेरोजगारी, बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों में कमी के साथ तीव्र आर्थिक विकास, कुछ हाथों में धन का संकेन्द्रण और भाई-भतीजावाद पड़ोसी देश में उथल-पुथल के प्रमुख कारण हैं, शेख हसीना इसकी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने एक विरासत को बर्बाद कर दिया जो उनकी मुख्य संपत्ति थी।

उनकी सत्तावादी सरकार असहमति की आवाजों को दबाने पर अड़ी हुई थी और नेतृत्व की उनकी तानाशाही शैली, जिसने विपक्ष को हर उचित और अनुचित तरीके से नियंत्रित रखा, उन सभी बातों के बिल्कुल विपरीत थी जिनके लिए उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान खड़े हुए और 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के लिए लड़े।

2009 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के माध्यम से सत्ता में आने के बाद, उन्होंने बाद में तीन मौकों - 2014, 2018 और 2024 में बड़े पैमाने पर गैर-सहभागी और विवादास्पद चुनावों की अध्यक्षता की। वह लगभग अजेय लग रही थीं, सत्ता पर उनकी पकड़ पूरी थी।

स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत नौकरी कोटा बहाल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शन उस समय चरम पर पहुंच गए जब कई वर्षों से उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। अशांति ने आम जनता में भय पैदा कर दिया, जो कि ज्यादातर बेरोजगार है। शेख हसीना द्वारा अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए छात्रों की मांगों को पूरा करने से इनकार करने से संकट और बढ़ गया।

शेख हसीना की सबसे बड़ी गलतियों में से एक उनकी टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने नौकरी कोटा का विरोध करने वालों को 'रजाकार' (बांग्लादेश में एक अपमानजनक शब्द) या बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने वालों को कहा था। यह हजारों छात्रों को विरोध करने के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित करने वाला था।

विपक्ष ने लगातार तीन बार चुनाव जीतने वाली हसीना पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को विफल करने का आरोप लगाया था। यह भी प्रचलित धारणा थी कि 'विकास' केवल हसीना की अवामी लीग के करीबियों की मदद कर रहा था।

जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन ने गति पकड़ी, उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन मिला, जिसमें माता-पिता, शिक्षक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता शामिल थे। आंदोलन अपनी शुरुआती मांगों से आगे निकल गया और 15 साल के भय और उत्पीड़न के खिलाफ निराशा की सामूहिक अभिव्यक्ति बन गया। छात्रों द्वारा अपनी मांगें पूरी होने तक प्रधानमंत्री से बातचीत करने से इनकार करना गहरे अविश्वास और आक्रोश को दर्शाता है।

सोशल मीडिया पर खुलेआम चर्चा हुई जिसमें शीर्ष अधिकारियों, चाहे वे सेवारत हों या सेवानिवृत्त, पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। हसीना ने भ्रष्टाचार को एक समस्या के रूप में स्वीकार किया था और कार्रवाई करने का वादा किया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

2009 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के माध्यम से सत्ता में आने के बाद, उन्होंने बाद में तीन मौकों - 2014, 2018 और 2024 में बड़े पैमाने पर गैर-सहभागी और विवादास्पद चुनावों की अध्यक्षता की। वह लगभग अजेय लग रही थीं, सत्ता पर उनकी पकड़ पूरी थी।

बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वह न केवल एक कठोर चेतावनी है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सबक भी है, जो समाज के बड़े वर्गों के बीच इसके वितरण की चिंता किए बिना आर्थिक विकास पर जोर देते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षरण के सामने अकेले आर्थिक प्रगति किसी नेता की लोकप्रियता को कायम नहीं रख सकती।

निस्संदेह, हसीना का कार्यकाल उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धियों से भरा रहा। उनके नेतृत्व में, बांग्लादेश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक से क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया, यहाँ तक कि अपने बड़े पड़ोसी भारत से भी आगे निकल गया।

देश की प्रति व्यक्ति आय एक दशक में तीन गुनी हो गई, और विश्व बैंक का अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में 25 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। हसीना की सरकार ने घरेलू निधियों, ऋणों और विकास सहायता के संयोजन का उपयोग करके गंगा पर $2.9 बिलियन के पद्मा ब्रिज जैसी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू किया।

हालांकि, ये आर्थिक लाभ काफी कीमत पर आए। 2014, 2018 और 2024 के संसदीय चुनाव कम मतदान, हिंसा और विपक्षी दलों के बहिष्कार से प्रभावित हुए। हसीना की सरकार ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए कठोर शक्ति पर अधिक से अधिक भरोसा किया, जिससे भय और दमन का माहौल बना। 2018 में लागू किया गया डिजिटल सुरक्षा अधिनियम सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आलोचकों को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विशेष रूप से ऑनलाइन, को दबाने का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा और नागरिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से दबाया गया क्योंकि हसीना ने सत्ता के एकमात्र केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ-साथ अमीर और गरीब के बीच असमानता भी बढ़ी। बैंक घोटाले बढ़े और ऋण न चुकाने वालों की सूची में भारी वृद्धि हुई। सीएलसी पावर, वेस्टर्न मरीन शिपयार्ड और रेमेक्स फुटवियर जैसी कंपनियाँ 965 करोड़ से लेकर 1,649 करोड़ बांग्लादेशी टका तक के खराब ऋणों के साथ डिफॉल्टरों की सूची में सबसे ऊपर हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने समग्र आर्थिक प्रगति के बावजूद लोगों में असंतोष को बढ़ावा दिया।

170 मिलियन की आबादी वाले बांग्लादेश में लगभग 18 मिलियन युवा बेरोजगार हैं। बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश वैश्विक बाज़ार में लगभग 40 बिलियन डॉलर के कपड़े निर्यात करता है। खुदरा क्षेत्र में महिलाओं सहित 4 मिलियन से ज़्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन इस वृद्धि का मतलब शिक्षित युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है

जबकि हसीना की आर्थिक उपलब्धियाँ सराहनीय थीं, उनके द्वारा कठोर शक्ति का प्रयोग और लोकतांत्रिक मानदंडों की अवहेलना अंततः उनके पतन का कारण बनी। जैसे-जैसे बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, उसे अपनी आर्थिक गति को पुनः प्राप्त करने, अपने लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास बहाल करने और हाल के वर्षों में उभरी असमानताओं को दूर करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

बांग्लादेश में घटित घटनाएं आर्थिक प्रगति को लोकतांत्रिक शासन के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करती हैं, जिसके अभाव में बहुतों की कीमत पर केवल कुछ ही लोगों को लाभ मिलता है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जैसे कि अलोकप्रिय सेना प्रमुख एचएम इरशाद जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वे देश छोड़कर भागे नहीं। देश छोड़कर वे उन पाकिस्तानी शासकों की जमात में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के बजाय सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पसंद किया।

शेख हसीना का पतन उन नेताओं के लिए चेतावनी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता की कीमत पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

क्या यह कहानी बांग्लादेश के किसी अन्य पड़ोसी देश से मिलती-जुलती है या जानी-पहचानी लगती है? मैं इसे अपने पाठकों की कल्पना पर छोड़ना पसंद करूंगा।

यह कुर्सी है बदलने में जरा सी देर लगती है

मीडिया मैप लखनऊ ब्यूरो

इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि प्रजा पर थोपे गए तुगलकी फरमान सत्तधारी ही नहीं बल्कि सत्ता की नीव को भी हिला देते हैं। ऐसे ही कुछ फरमान इन दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी गले ही हड्डी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रर्दशन काफी खराब रहा, तब से पार्टी की हार की समीक्षा हो रही है। इस समीक्षा में बुलडोजर नीती से लेकर अकबर नगर में मकानों को जमीदोज किए जाने को भी हार की वजह माना जा रहा है। तमाम लोग इसके पीछे यूपी सरकार की नीतियों को दोष दे रहे हैं। यहां तक सहयोगी दलों के नेता भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इन समीक्षा बैठकों के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी के भविष्य को लेकर आशंकाएं सामने आने लगी हैं। इन सब कारणों के बीच योगी बनाम केशव के उस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है जिसकी शुरुआत साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पहले शुरू हुई थी। क्या होंगे इस रस्साकसी के नतीजे? यह तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल योगी सरकार का 'नेम प्लेट' वाला फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला कोर्ट तक पहुंचा न्यायालय ने 22 जुलाई को नेमप्लेट वाले आदेश को खारिज करते हुए फैसला दिया कि खाने की पहचान बतानी होगी ना कि दुकानदार की पहचान लिखी जाए।

कावंड़ यात्रा के मार्ग में पढ़ने वाली खाद्य समाग्री की दुकानों पर, ठेलों पर उसके मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य होगा, यानी हर दुकान, खाने के होटल और ठेलों पर नेमप्लेट लगाना जरूरी होगा। उदाहरण के तौर पर सिर्फ यह लिखा होना कि 'मुन्ना का होटल' काफी नहीं होगा बल्कि लिखना होगा कि रहीम खान इस होटल के मालिक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद से प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया। पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के नए बोर्ड तैयार करने शुरू कर दिए, लेकिन दिलों में यही सवाल थे कि यह वही कावंड़ यात्रा है जो सालों से हो रही है? इन्हीं रास्तों से गुजरी है? हमेशा शिव के इन भक्तों पर मुसलमानों ने कहीं फूलों की बारिश की है तो कहीं उन्हें बिठा कर सेवा की है। उन्हें पानी पिलाया है तो पैर भी दबाए हैं। अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस पवित्र यात्रा में मुस्लिम लोगों की सहभागिता से सब अपवित्र हो जाएगा? सुप्रीमकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं खाना मासाहारी है या शाकाहारी इस बात की जानकारी देनी हो
गी।

कांवड़ यात्रा की शुरूआत से जारी हुआ यह आदेश सिर्फ धर्म की राजनीति करने वालों का एक हथियार है। वरना आम आदमी तो इस पवित्र यात्रा को सिर्फ आस्था के रास्ते पर चलकर पार करता है। कांवड़ लिए शिव के भक्तों को ना किसी के नाम से परहेज है और ना ही उनकी सेवा से। यूपी में कई ऐसे मुस्लिम कारीगर हैं, जो कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द का रंग भर रहे हैं। वर्षों से यह शिवभक्तों की पोशाक तैयार करते आ रहे हैं। यही नहीं शिवभक्त जिन कांवड़ में गंगाजल

"बीजेपी की हार के बाद 'बुलडोजर नीति' और कांवड़ यात्रा के विवादित आदेश पर आलोचना बढ़ी। मुख्यमंत्री ने मकानों को ढहाने के आदेश रोके।"

भर कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उन्हें मुस्लिम कारीगर पूरी मेहनत और लगन से तैयार करते हैं। सहारनपुर के मोहल्ला गोटेशाह में व्यापारी हसीब की होजरी फैक्टरी है। इनके यहां कई कारीगर और उनके बेटे तौफीक व शाहिद अपने हाथों से होजरी के कपड़े तैयार करते हैं। हर वर्ष श्रावण शुरू होने से पहले कांवड़ियों की महाकाल लिखी, भोले बाबा की और शिवलिंग की तस्वीर लगी पोशाक बनाते हैं। हरिद्वार में कांवड़ कारीगरों के काम में भाईचारे और एकता का एक दिल को छू लेने वाला प्रदर्शन देखने को मिलता है । कुंभनगरी हरिद्वार से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा हिंदू-मुस्लिम सद्भाव की मिसाल है। हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्त गंगा का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि ये भक्त अपने कंधों पर जो कांवड़ उठाते हैं, उन्हें हरिद्वार जिले के मुस्लिम परिवार बड़ी सावधानी से तैयार करते हैं।

लखनऊ में अकबरनगर में अवैध निर्माणों को ढहाने के बाद कुकरैल नदी के किनारे बसे अबरार नगर ,पंतनगर ,रहीम नगर ,इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सिंचाई विभाग के सर्वे के बाद मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए। लाल निशान मतलब यही मकान जमीदोज किए जाएंगे। लेकिन यहां हुए सर्वे के खिलाफ बनी संघर्ष समिति जमीन बचाओ सत्याग्रह आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। इन इलाकों में लोगों ने पोस्टर लगा दिए जिनमें लिखा था कि अगर हमारे मकान अवैध है तो हमारा वोटर आईडी भी अवैध है और हमारे द्वारा दिया गया वोट भी अवैध है। इसलिए हमारे क्षेत्र के पार्षद, हमारे विधायक, हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद और हमारे द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री जी भी अवैध हैं। इलेक्शन कमिशन इस मामले को संज्ञान में ले और इन सभी की सदस्यता खत्म करके फिर से चुनाव करवाए। अवाम के इन बदले तेवरों का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री जी आगे की कार्यवाई को रोक दिया है। शायद अब सरकार को भी यह पता चल रहा है कि विध्वंसक कार्रवाइयां ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आश्वासन दिया निजी जमीनों पर बने घर नहीं गिराए जाएंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. चूंकि बड़ी संख्या में गिराए जा रहे घरों के मामले में यह बड़ा सवाल भी आया कि आखिर सालों से ये घर बनते कैसे चले गए? मुख्यमंत्री के रुख में आए इस बदलाव को भी चुनावी नतीजों से ही जोड़कर देखा जा रहा है।

राज्य सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 'बुलडोजर नीति' को हार का प्रमुख कारण बताया। संजय निषाद की बात में इसलिए दम हैं क्योंकि बुलडोजर के इस्तेमाल पर जो तालियां बजाया करते थे वह भी धीरे-धीरे इसकी चपेट में आने लगे। पहले कई मामलों में ज्यादातर बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों के मामलों में हुई तो इसे राजनीतिक तुष्टीकरण से देखा गया लेकिन धीरे-धीरे इसका विस्तार होता गया। किसी अपराध में नाम आ जाने पर भी कथित अवैध निर्माण के नाम पर घर ढहा दिए गए। यहां तक कि अदालत की टिप्पणियों के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी रहा। बीजेपी समर्थक बुलडोजर को सरकार की ताकत के प्रतीक के तौर पर प्रचारित करते रहे लेकिन चुनावी हार और खराब प्रदर्शन के बाद अब इसे भी हार के प्रमुख कारणों में गिना जा रहा है।

महाराष्ट्र चुनाव और मोदी सरकार का भविष्य

मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क

गठबंधन सरकार भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिये कोई नयी बात नहीं है। वर्ष 1967 के बाद देश के तमाम राज्यों और केंद्र मे लम्बे समय तक गठबंधन सरकारे बनी और चली है पर प्रधानमंत्री मोदी की अधिआयाक्रादी मानसिकता और राजनैतिक शैली के कारण यह प्रश्न उठ रहा है कि उनकी वर्तमान सरकार कितने दिन तक चलेगी।

दो क्षेत्रीय दलो --जनता दल (यू) और तेलगू देशम पार्टी-- के समर्थन के चलते भाजपा बहुमत का दावा करके सरकार बनाने में समक्ष हुई है। अब इन दोनों दलों के शीर्ष नेता-- नितीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू -- केंद्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गये है और वह आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएंगे । पर लगता है कि दिल्ली से बहुत दूर महाराष्ट्र में विधानसभा के आने वाले चुनाव मोदी सरकार के भविष्य के लिए ज्यादा महत्तपूर्ण है।

महाराष्ट्र की गिनती देश के पांच - छह बड़े राज्यों में होती है। यह राज्य राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर कहा जाता है की जो मुंबई पर राज करता है उसके हाथ में दिल्ली की राजनीति की चाभी होती है। उत्तर प्रदेश के 80 बाद सबसे अधिक 48 लोकसभा सांसद महाराष्ट्र से चुनकर आते है। देश की लोकतांत्रिक राजनीति चलाने के लिये राजनैतिक दलों का अधिकांश चन्दा आज भी मुंबई से आता है। इसके अतिरिक्त न सिर्फ आर एस एस का मुख्य कार्यलय नागपुर में है बल्कि महाराष्ट्र उस हिंदुत्व राजनीति की जन्मस्थली है जिसको आधार बना कर नरेंद्र मोदी सत्ता में आये और अब तक बने हुए है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर की कर्मभूमि भी रही जिनके कारण हम आज उदार और समावेशी लोकतांत्रिक राजनीति की बात करते है।

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों से पहले कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज़्यादा 48 सदस्य लोकसभा यहाँ से ही आते है और इसलिए बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए यह बहुत अहम है। महाराष्ट्र ने निश्चित रूप से बीजेपी को पूर्ण बहुमत से वंचित करने और मोदी-शाह लॉबी के अहंकार को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब निगाहे कुछ महीनों बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर है और उसके के लिए चुनावी संग्राम की रेखाएँ खींची जा रही हैं। लगता है कि महाराष्ट्र गुजरात लॉबी तथा विपक्ष के बीच निर्णायक युद्ध का अखाड़ा बन गया है। अगर मोदी-शाह शैली की राजनीतिक चालें महाराष्ट्र में सफल नहीं होती हैं, तो आगामी चुनावों में भाजपा का कर्चस्व कम होता जायेगा।

पिछले वर्षों में मोदी-शाह की भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को, जो स्थापित पार्टियां हैं और जिनके नेता बेहद लोकप्रिय हैं, उनको विभाजित करने में सफलता प्राप्त की और उनकी गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। स्वाभाविक है कि केंद्र में कमजोर मोदी सरकार को हटाने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों का गठबंधन महाराष्ट्र को युद्ध के मैदान के रूप में देख रहा है,

सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार का समर्थन प्राप्त एकनाथ शिन्दे और अजित पवार जैसे नेताओ के महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन को अपने समर्थकों की बड़ी संख्या के चले जाने से कमजोर हो गए शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे पुराने नेता सफलतापूर्वक चुनौती दे पाएंगे, या फिर - शिंदे और अजित पवार - अपने पुराने आकाओं को हराने और उन दो पार्टियों पर कब्ज़ा करने में सफल होंगे जिन्होंने उन्हें पाला-पोसा और उन्हें वह राजनीतिक दर्जा दिया जिसका वे आज आनंद ले रहे हैं? जबकि विधायकों का बहुमत, केंद्र से मजबूत समर्थन, एक दोस्ताना चुनाव आयोग और एक उदार मीडिया-उनके पक्ष में हैं, यह संदिग्ध है कि शिंदे और अजित पवार सफल होंगे। इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि अपनी पार्टियों को विभाजित करने और पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के उनके कदम को आम जनता की सहमति नहीं मिल रही है।

क्या यह उनके काम का नैतिक पहलू है जो शिंदे और अजित पवार को राजनीतिक दलदल में फंसाता है? हालांकि हममें से ज़्यादातर लोग यही कहना चाहेंगे और मानते हैं पर यह सच नहीं है। न्यायिक अयोग्यता या भाजपा द्वारा धोखा दिए जाने का डर भी वह कारण नहीं है जो उन्हें अस्थिर बनाता है। और भाजपा शासित गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे उन पर लगे आरोप निश्चित रूप से धुल गए हैं।

शिन्दे और अजीत पवार की समस्या का मूल कारण एक औसत भारतीय की मूल मानसिकता को न समझना है जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी व्यक्ति को सत्ता में लाने के लिए वोट करता है। हम जानते हैं कि एक औसत भारतीय, हिंदू या किसी अन्य धर्म का व्यक्ति रूढ़िवादी, धार्मिक और ईश्वर से डरने वाला होता है और ये गुण काफी हद तक उसके मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। लेकिन यह सब भारतीय मतदाता की मानसिकता के बारे में सब कुछ नहीं है।

तथ्य यह है कि भारत में हमने संसदीय लोकतंत्र को एक सामंती समाज पर थोप दिया है, जो सदियों से निरंकुश उत्पीड़न के अधीन था और लोकतांत्रिक स्वभाव से अपरिचित था।

सामंती मनोवृति दमनकारी जरूरी है लेकिन संरक्षण देने वाली भी होती है। एक सामंती स्वामी शासक अपने लोगों का शोषण कर सकता है लेकिन वह उन्हें बाहरी आक्रमण से भी बचाता है। और इसी कारण से, एक सामंती स्वामी अपनी जागीर में रहने वाले लोगों के लिए देवता स्वरूप बन जाता है। पिछले कुछ दशकों में विधायी निकायों में निर्वाचित होकर भारत के सामंती स्वामी लोकतांत्रिक बन गए हैं। और जो लोग सामंती पृष्ठभूमि से नहीं आए थे, उन्होंने भी उनकी नकल की, जिसका नतीजा यह हुआ कि न तो चुने गए नेताओं और न ही मतदाताओं की मानसिकता बदली। राजा और प्रजा की परम्परा वाला मनोविज्ञान अभी भी हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का चरित्र बना हुआ हैं। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद (वंशवादी शासन) का बोलबाला है।

चूँकि आप जिस देव की पूजा करते हैं, उसके गुण-दोषों का निर्णय नहीं करते, इसलिए भारतीय मतदाता अपने चुने हुए नेताओं के अच्छे या बुरे कामों के बावजूद उनके प्रति अपनी वफादारी नहीं बदलते। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के सिद्ध आरोपों, अक्षमता, और शारीरिक विकलांगता के बावजूद लालू प्रसाद, शिब्बू सोरेन, नवीन पटनायक और मायावती जैसे नेताओं ने अपना समर्थन बरकरार रखा है।

मतदाताओं के सामन्ती मनोवृति के इसी चरित्र के कारण चरण सिंह, बाल ठाकरे, जगजीवन राम, करुणानिधि, जयललिता, मुलायम सिंह यादव और कई अन्य नेताओं ने जीवन के अंतिम दिन तक अपना जनाधार बनाए रखा, जबकि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी। यही कारण है कि 83 वर्षीय और बीमार शरद पवार कहते हैं कि वे अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे और जनता कहती है कि हम आपके साथ हैं।

हमारे देश में राजनीतिक नेता अक्सर अपनी पार्टियाँ बदलते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता कभी भी उस पार्टी के स्थापित नेता को चुनौती देने में सफल नहीं हो पाया, जिसे उसने छोड़ा था और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना। पार्टी के कार्यकर्ता और अनुयायी हमेशा शीर्ष नेता के प्रति ही वफादार रहे हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिन्दे और अजीत पवार जैसे बागी नेता न तो अपनी पुरानी पार्टी को अपने पाले में कर पाएंगे और न ही शरद पवार या उद्धव ठाकरे को पछाड़ पाएंगे। वे भले ही विधायकों का बड़ा हिस्सा लेकर चले गए हों, लेकिन वे जनता को अपने साथ नहीं ले जा पाए। जनता अपनी पार्टी के मुखिया और उनके परिवार के प्रति वफादार रही है और इसके बहुत स्पष्ट और स्पष्ट संकेत हैं।

अगर एकनाथ शिन्दे और अजित पवार अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो इन के पास एक ही रास्ता है कि या तो वे भाजपा में शामिल हो जाएं या अपनी अलग पार्टी बना लें। वह कुछ भी करे पर वह भाजपा गठबंधन को आगामी विधानसभा के विजयी नहीं बना पायेंगे। महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस, शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी और शिव सेना की उदव ठाकरे की महाविकास अगाडी पार्टी के साथ ही है। अगर भाजपा नेतृत वाला गठबंधन विधानसभा वाला चुनाव हारता है तो भाजपा सरकार का केंद्र में बने रहना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

जगन्नाथपुरी का भव्य मेला जहाँ लाखो श्रद्धालु आते है

जगदीश गौतम

हमारे देश में धार्मिक स्थान क्षेत्र के अनुसार चार धामों में विभक्त किये गये है। इन धामों में से "जगन्नाथ धाम" उड़ीसा प्रान्त के पुरी नामक स्थान में है जो भुवनेश्वर से लगभग 35 किमी दूर है जहां विश्व के कोने-कोने से दर्शक और तीर्थयात्री आते है।

जगन्नाथपुरी धाम में प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह रथयात्रा महोत्सव भगवान कृष्ण की गोकुल से मथुरा तक की यात्रा की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। इसी रथयात्रा के कारण यहां करोड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री आते है। गेल लगाग एक माह तक चलता है। जगन्नाथ मंदिर के कारण ही पुरे विश्व में प्रसिद्ध है।

भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के आयोजन के लिए 14 मीटर ऊँचाई तथा ग्यारह मीटर चौड़ाई वाले लकड़ी के रथ मन्दिर का निर्माण किया जाता है जिसे लगभग हजारो की संख्या में लोग दितीया के दिन बड़े उत्साह के साथ खींचते है। इस रथ में श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बैठाई जाती है। यह रथयात्रा जगन्नाथ उद्यान से शुरू होकर गुंडी चाबारी तक जाती है जो लगभग दो किमी की दूरी पर स्थित है। फिर भी इस यात्रा में चौबीस घंटे का समय लग जाता है। इसी गुंडी चावारी में सात दिन तक विश्राम करने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने धाम वापिस आते है। रथयात्रा के उपलक्ष्य में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है।अपनी सुन्दरता तथा अनुपम छटा के लिये जगन्नाथ धाम अनूठा है। इस मन्दिर की रचना अलौकिक एवं अत्तीम कसीदाकारी युक्त है। मन्दिर काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यह मन्दिर पुरी नगर के बीचों बीच स्थित है। इस मन्दिर में बैंगवान जगन्नाथ की मूर्ति प्रतिष्ठत है। इस मूर्ति में हीरा जड़ा हुआ है जो काले पत्थर के बीच अपनी अनोखी छटा निखारता है। इसी मन्दिर में भगवान जगन्धाथ के भाई तथा बहन वलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित है जो चंदन की लकड़ी ते बनाई गयी है। इन मूर्तियों को बहुमूल्य हीरो, जवाहरत, रत्नों एवं रेशमी योटों से सजाया जाता है।

मंदिर देखने में बहुत सुन्दर आकर्षक लगता है। यह दो परकोटों के बीच स्थित है जो शिल्पकला की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस मन्दिर के चारों तरफ प्रवेश द्वार है। इनमें पहला प्रवेश द्वार अत्यन्त सुन्दर है। इसके सामने दोनों ओर दो शेरों की मूर्तियां बनी हुई है। इन्ही सिंह मूर्तियों के कारण इते सिंह द्वार कहा जाता है।

सिंहद्वार के तामने ही काले रंग का सुन्दर अरुण स्तम्भ जिस पर सूर्य तारथी अरुण की प्रतिमा बनी हुई है। यह स्तम्भ कोणार्क के सूर्य मन्दिर से लोकर यहां स्थापित किया गया है।

मन्दिर के पश्चिमी भाग में व्याध द्वार तथा उत्तर में गज हस्तिहूँ द्वार, एवं दक्षिण की ओर अश्व द्वार है। इन द्वारों का नाम उनके पास बने जानवरों के चित्रो के कारण रखा गया है। यह मन्दिर लगभग 60 मीटर ऊंचा है। परकोटे के मुख्य मंदिर में जाने पर दूसरे दृश्य देखने को मिलते है। इस मन्दिर में पश्चिम में एक रत्न वेदी पर सुदर्शन चक्र बना है। इस मन्दिर के भी चार भाग है।

"उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जहां 14 मीटर ऊंचा लकड़ी का रथ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ खींचा जाता है। यह यात्रा आषाढ़ मास की द्वितीया को होती है और यहां लाखों तीर्थयात्री आते हैं।"

पहला भाग प्रसाद मण्डप कहलाता है। दूसरा भाग जगमोहन मण्डल, तीसरा भाग मुख्य मण्डल तथा चौथा भाग जगन्नाथ मण्डल कहलाता है। यह मण्डप एक दूसरे से मिले हुए है। लेकिन उनका उपयोग अलग अलग है। इस मन्दिर में तीन दिन तक दर्शनाथियों- तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन मिलता है। जो प्रसाद मण्डप में वितरित किया जाता है। समुद्र में स्नान करने के बाद जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किये जाते है। यहां से पीपल का बर्तन खरीद कर ले जाना धार्मिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। मंदिर की व्यवस्था में सैकड़ो लोग लगे हुए है। जो देखने में स्वयं तेवी पण्डे प्रतीत होते है। इस स्थान मन्दिर की आर्थिक व्यवस्था में धनी वर्ग के लोग अपना सहयोग देते है।

मंदिरों के इतिहास से पता चलता है कि यह मन्दिर 12वीं शताब्दी के लगभग बनवाया गया है। पुरी का नाम प्राचीन काल में पुरुषोत्तम स्थल तथा लक्ष्मी स्थल भी बताया जाता है। इस मन्दिर का निर्माण कलिंग प्रान्त के राजा चोड़गंग ने करवाया था। जिसमें जगन्नाथ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठत की गयी। तभी से यह स्थान जगन्नाथ पुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ दूसरे मत के अनुसार पहले यहां बौद्ध मठ बने हुए थे। बाद मैं यहां जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया।

महात्मा गांधी जी की यादों को सहेजने के लिए बन रहा एक स्मारक

हेमलता म्हस्के

पुणे का डेढ़ सौ से भी अधिक साल पुराना डेविड ससुन अस्पताल महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है। ऐतिहासिक भी हैं। इससे देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। पुणे नगर और उसके आसपास के इलाकों में काफी प्रतिष्ठित है। इन दिनों यह अस्पताल चर्चा में है क्योंकि आज से सौ साल पहले इसी अस्पताल में 1924 में महात्मा गांधी का आपातकालीन अपेंडिक्स ऑपरेशन किया गया था। जिस वार्ड में गांधी जी का ऑपरेशन हुआ था उसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि गांधी का कभी किसी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। लेकिन सौ साल पहले 12 जनवरी 1924 में पुणे के डेविड सुसन अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ था और उसकी स्मृति इस अस्पताल में सहेज कर रखी जा रही है। अब इस अस्पताल में आने वाले ज्यादातर बीमार और उनके तीमारदार सभी को पता चल रहा है कि कभी यहां गांधी जी का भी ऑपरेशन हुआ था। इस अस्पताल में गांधी जी के अलावा कर्मवीर भाऊ राव पाटिल और प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी का भी इलाज हुआ था।

यह अस्पताल इसलिए भी खास है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इस अस्पताल का निर्माण भी उदारवादी लोगों के दान से हुआ लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

12 जनवरी 1924 का दिन बहुत ही तूफानी था, जब महात्मा गांधी को पेट दर्द की शिकायत के बाद सेंट्रल येरवडा जेल से पुणे के अस्पताल में लाया गया

हालांकि पिछले कुछ सालों में अपेंडिक्स को निकालने की प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन उस समय यह एक अलग प्रक्रिया थी, खासकर इसलिए क्योंकि भयंकर तूफान के कारण अस्पताल की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। गांधी को तब तूफान लैंप के नीचे ऑपरेशन करना पड़ा था।

डॉ. मुरलीधर तांबे के मुताबिक "कई मेडिकल परीक्षण किए गए और डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि गांधीजी को तीव्र अपेंडिसाइटिस हो गया था। उस समय उनकी आयु 50 वर्ष थी।"

महात्मा गांधी ने उनके ऑपरेशन के लिए डॉ. दलाल और डॉ. जीवराज के नाम सुझाए थे और ब्रिटिश सरकार मुंबई से भारतीय डॉक्टरों के आने का इंतजार करने को तैयार थी।

हालांकि, आधी रात से ठीक पहले ब्रिटिश सर्जन डॉ. कर्नल मैडॉक ने गांधी को सूचित किया कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख वीएस श्रीनिवास शास्त्री और अपने करीबी दोस्त डॉ. फाटक को बुलाया।

उन्होंने एक पत्र का मसौदा तैयार करने में मदद की, जिसमें कहा गया था कि गांधीजी ऑपरेशन के लिए सहमत हो गए हैं,। इसी के साथ यह भी कहा गया था कि डॉक्टरों ने उनका अच्छा इलाज किया है और यदि कुछ गलत हो जाता है तो कोई सरकार विरोधी आंदोलन नहीं होना चाहिए - यह पत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना से पूरे देश में अराजकता फैल सकती थी।

गांधी को आधी रात के बाद ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया और यह प्रक्रिया 40 मिनट तक जारी रही। ऑपरेशन के दौरान आंधी-तूफान के कारण अस्पताल की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी।

फिर ऑपरेशन के बाकी हिस्से को पूरा करने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह जल्दी ही बंद हो गई। अंत में, ऑपरेशन को हरिकेन लैंप की रोशनी में पूरा किया गया।

ऑपरेशन पूरी तरह सफल होने के बाद गांधी ने मैडॉक को बहुत धन्यवाद दिया। इसके तुरंत बाद गांधी की छह साल की जेल की सज़ा कम कर दी गई और उन्हें 5 फरवरी, 1924 को रिहा कर दिया गया।

गांधी, जो उस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थे, को एक साल बाद फिर से ससून अस्पताल लाया गया, जब उनकी तबीयत खराब हो गई। इस बार, गांधी ने संतरे के जूस से अपना उपवास तोड़ने पर जोर दिया, जो उन्हें कर्नल मैडॉक ने दिया था, जो उनके करीबी दोस्त बन गए थे।

ससून अस्पताल में 400 वर्ग फुट का ऑपरेशन थियेटर, जिसे उस दिन के कारण एक स्मारक में बदल दिया गया है, में अभी भी वे उपकरण रखे हुए हैं जो गांधी की सर्जरी के लिए इस्तेमाल किए गए थे और वहां एक दुर्लभ पेंटिंग भी रखी गई है जिसमें तूफान लैंप के नीचे चमत्कारी ऑपरेशन को दर्शाया गया है।

इस अस्पताल के स्थापित होने की कहानी भी प्रेरणादायक है।

1867 में भारत आने वाले सबसे प्रभावशाली व्यापारियों और परोपकारी लोगों में से एक डेविड सैसून के उदार दान से इस अस्पताल का निर्माण संभव हो सका। बगदादी यहूदी सैसून ने भारत में एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया और आयात-निर्यात व्यापार पर अपना दबदबा कायम किया।

उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक

पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर, ससून रोड पर स्थित यह अस्पताल बेसाल्ट और ग्रे ट्रैप स्टोन से बनी दो मंजिला विक्टोरियन गोथिक इमारत है। इसे बनाने में कुल 3,10,060 रुपये की लागत आई थी, जिसमें से ससून ने 1,88,000 रुपये का योगदान दिया था। इमारत का डिज़ाइन हेनरी सेंट क्लेयर विल्किंस (1828-1896) ने तैयार किया था, जो ब्रिटिश सेना के अधिकारी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक वास्तुकार थे। उन्होंने डेक्कन कॉलेज और ओहेल डेविड सिनेगॉग जैसी कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिज़ाइन किया था। संरचना पर लोहे का काम एमजे हिगिंस द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिन्होंने सेंट पॉल चर्च के लिए लोहे का काम भी डिज़ाइन किया था।

इमारत परिसर के दक्षिण-पश्चिम कोने में एक बड़ा चिनाई वाला घंटाघर है, जो 120 फीट ऊंचा है। इस टॉवर में अस्पताल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का टैंक भी था। मुख्य इमारत का माप 227' x 50' है। दोनों मंजिलों पर स्थित वार्ड बरामदे के आर्केड पर खुलते हैं। भूतल के उत्तर में दो 'मूल महिला' वार्ड स्थित थे, और दक्षिणी तरफ दो 'मूल पुरुष' वार्ड थे। पहली मंजिल पर यूरोपीय लोगों के लिए वार्ड पाए गए।

आज, भूतल को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित किया गया है और इसमें दो पुरुष वार्ड, दो महिला वार्ड और सिविल सर्जन और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय कक्ष शामिल हैं। पहली मंजिल पर महिला और बच्चों के वार्ड हैं। इमारत में एक ऑपरेशन थियेटर और एक एक्स-रे विभाग भी है। इमारत में कई नवीनीकरण किए गए हैं, जिसमें एक अत्याधुनिक रसोई का निर्माण भी शामिल है, जो श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट द्वारा 1,50,00,000 रुपये से अधिक के उदार दान के माध्यम से संभव हुआ।

राजीव गाँधी जो भितरघात के शिकार हुए

प्रो प्रदीप माथुर

राजीव गाँधी के विरुद्ध बोफर्स षड्यंत्र की यह कथा बहादुरशाह जफ़र मार्ग पर स्थित इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस में लिखी गयी। नयी दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के कमरे में एक प्रतिष्ठित पत्रकार को स्वीडन को राजधानी भेजने का प्लान बना जिससे बोफर्स कार्यलय जाकर राजीव गाँधी के विरुद्ध कुछ मसाला मिल सके। षड्यंत्र कारियो को आशा के विपरीत इन पत्रकार महोदय ने बताया की हथियारो की खरीद पर कमीशन देना - लेना इस व्यापर की सामान्य सी रित है पर राजीव गाँधी को न कुछ दिया गया और न उन्होंने कुछ लिया।

इसके बाद इन पत्रकार महोदय को इस षड्यंत्र की आगे की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया।

अमिताभ बच्चन का नाम इस षड्यंत्र में दो कारणों से लिया गया। एक था इलाहबाद में उनके कारण राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का घटना प्रभाव। फिर अमिताभ बच्चन की अपार फैन फॉलोइंग राजीव गाँधी की बहुत बड़ी शक्ति थी। बिना अमिताभ बच्चन को अलग किये हुऐ राजीव गाँधी की स्थित को कमजोर करना असम्भव था। **व**र्ष 1984-85 में अप्रत्याशित जनसमर्थन प्राप्त कर भारत का प्रधानमंत्री बन कर राजीव गांधी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर बहुत तेजी से उभरे थे। जितनी तेजी से राजीव गांधी का उदय हुआ उतनी ही तेजी से तीन वर्षों के अंदर उनका पतन भी होना प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या हुई। पर उनकी राजनैतिक हत्या का प्रयास तो वर्ष 1987 में बोफोर्स घोटाले के खुलासे के साथ ही किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या वर्ष 1987 में उनकी राजनैतिक हत्या और फिर 1991 में उनकी शारीरिक हत्या स्वाभाविक थी या उसके पीछे कोई राजनैतिक षड़यंत्र था।

यह सही है कि दिसम्बर 1984 के चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की अभूतपूर्व सफलता उस सहानुभूति लहर का परिणाम थी, जो सुरक्षा सैनिकों द्वारा उनकी मां प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की निर्मम हत्या के कारण सारे देश में उपजी थी। यह भी सही है कि राजनीति में कोई रुचि न रखने वाले राजीव गांधी को अपने भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद इन्दिरा गांधी को सहारा देने के लिये राजनीति में आना पड़ा और परिस्थितियों ने ही राजनैतिक दृष्टि से अनुभवहीन और अपरिपक्व इस युवा को देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। पर जो बात समझ में नहीं आती है वह यह है कि राजीव गांधी में ऐसा क्या था जिसके कारण उनका प्रारम्भ में अभूतपूर्व महिमामण्डन हुआ और फिर थोडे समय बाद ही उनकी कटु आलोचना का दौर आया।

सच तो यह है कि राजीव गांधी के छोटे लेकिन घटना प्रधान राजनैतिक जीवन (1981-91) का निष्पक्ष व वैज्ञानिक मूल्यांनक कभी किया ही नहीं गया है। इस कारण तत्कालिक इतिहास में उनके स्थान को सुनिश्चित करना वास्तव में एक समस्या है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के समाजवादी शासन के बाद भारत के पूंजीवादी वर्ग को अपने निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिये राजीव गांधी में अपार संभावनाएं दिखीं। शायद इसी कारण राजीव गांधी का भारत के बुर्जुआ वर्ग ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राजीव गांधी ने न सिर्फ सूचना क्रान्ति के द्वार खोले बल्कि आधुनिक सोच और आर्थिक सुधारों पर भी विमर्श को बढ़ावा दिया। उनकी साफ सुथरी छवि, सज्जनता और सौम्य स्वभाव ने उन्हें प्रसिद्धी के शिखर पर बैठा दिया। एक समाचार पत्र ने उन्हें 'मिस्टर क्लीन' की - उपाधि दे डाली। पर थोड़े ही समय बाद हवा उल्टी बहने लगी। यह बोफोर्स से - पहले ही शुरू हो गया था। बोफोर्स काण्ड - ने उसे नये आयाम दिये। यदि राजीव गांधी अनुभवहीन, अपरिपक्व व राजनैतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं थे तो यह तो उस दिन भी पता था जब वह प्रधानमंत्री बने। फिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री की पारी शुरू होने पर उन्हें अपार प्रशंसा और व्यापक समर्थन मिला और थोड़े ही समय बाद उनका विरोध आरम्भ हो गया।

किसी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है, किसी व्यक्ति को सत्ता में बैठाना, सत्ता में जमाना और सत्ता से उखाड़ना, तीन अलग- अलग काम है जिन्हें अलग अलग वर्ग के लोग अंजाम देते हैं। राजीव गांधी को सत्ता में तो व्यापक जनसमर्थन ने बैठाया। पर लगता है कि उनके सत्ता में बैठने के कुछ समय बाद ही निहित स्वार्थियों को लगा कि वह उनके हित साधन के लिये उपयुक्त नहीं है तो उन्हें उखाड़ने का प्रयास शुरू हो गया, जिसे समझने में उन्होंने बहुत देर की।

शायद राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित मंत्री बनाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। राजा साहब ने पूंजीपति और उद्योग जगत के बड़े संगठनों पर कर चोरी के लिये छापे डलवाने शुरू किये। इससे हड़कंप मचा और राजीव सरकार का विरोध प्रारम्भ हुआ। कारपोरेट जगत का

इशारा पाते ही संघ परिवार और नेहरू परिवार के पेशेवर विरोधियों ने उनके विरुद्ध भ्रामक प्रचार शुरू कर दिया। कहा गया कि उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है और उनका नाम रार्बट गांधी है। उनकी पत्नी सोनिया गांधी के विरुद्ध भी भीषण प्रचार शुरू किया गया।

सरकार में भी विश्वनाथ प्रताप सिंह और अरूण नेहरू ने राजीव गांधी के विरुद्ध षड़यंत्र शुरू किया। विश्वनाथ प्रताप की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की थी तथा अरूण नेहरू कारपोरेट जगत तथा हिन्दुत्ववादी शक्तियों के ऐजेन्ट थे और उनकी प्रधानमंत्री के सचिव और वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी गोपी अरोड़ा के साथ साठगांठ थी।

राजीव गांधी विरोधियों की शायद समस्या यह थी कि उनका जनाधार लगातार बढ़ रहा था। बड़े परिवार से आये, विदेश में पढ़े तथा वायुसेवा की नौकरी करने वाले राजीव गांधी ने भारत के गरीब आदमी के जीवन की वास्तविकता नहीं देखी थी। जब प्रधानमत्री के रूप में इस वास्तविकता से उनका साक्षात्कार हुआ तो उनका संवेदनशील व्यक्तित्व आम आदमी के जीवन के लिये बहुत कुछ करने को प्रेरित हुआ। मणीशंकर अय्यर जैसे सहायक अफसरों के कहने पर राजीव गांधी ने भारत के पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के बहुत दौरे किये और इनसे बहुत कुछ सीखा।

अपनी अनुभवहीनता के चलते राजीव गांधी ने दो और बड़ी भूलें की। एक था तमिल विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष करती श्रीलंका की सेना की सहायता के लिये भारतीय सेना की टुकड़ियां भेजना और इससे भी बड़ी भूल थी बोफोर्स रिश्वत काण्ड पर लोकसभा में बहस के दौरान खड़े होकर यह कहना कि मैंने रिश्वत नहीं ली है। सच बात यह थी कि राजीव गांधी ने बोफोर्स काण्ड में कोई पैसा नहीं लिया था। लेकिन लोकसभा में उनके बचकाने बयान से विरोधियों को उनके ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप लगाने का अच्छा बहाना मिल गया।

आम जनता के बीच राजीव गांधी के बढ़ते जनाधार का एक कारण अमिताभ बच्चन का उनको समर्थन था। अमिताभ राजीव के सबसे करीबी मित्र थे और राजीव शासन में उनका बहुत दबदबा था। अमिताभ बच्चन की राजीव से करीबी वी.पी.सिंह और अरूण नेहरू को फूटी आंखों न सुहाती थी। इसलिये अमिताभ बच्चन भी राजीव विरोधियों के षड़यंत्र का शिकार हुऐ। बिना किसी कारण के बोफोर्स काण्ड में उनको भी घसीटा गया। 28 वर्ष बाद जब राजीव गांधी, वी.पी. सिंह और अरूण नेहरू इस संसार से विदा ले चुके थे, अधिकारिक रूप से कहा गया कि बोफोर्स काण्ड में अमिताभ बच्चन का कोई लेना देना नहीं था।

वर्ष 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हुई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। पर वह एक वर्ष भी सरकार नहीं चला पाये। फिर लगातार तीन प्रधानमंत्रियों के बाद 1991 वर्ष के चुनावों में फिर कांग्रेस सत्ता में आयी। पर चुनाव प्रचार के दौरान 21 मई को श्री पैरम्बूर (तमिलनाडु) में राजीव की हत्या कर दी गयी।

"1984-85 में राजीव गांधी ने अचानक जनसमर्थन प्राप्त कर प्रधानमंत्री पद संभाला। कांग्रेस की सफलता के बावजूद, 1987 के बोफोर्स घोटाले के बाद उनका पतन शुरू हुआ। क्या यह केवल संयोग था या इसके पीछे कोई षड़यंत्र था? उनकी साफ छवि और नई सोच के बावजूद, अनुभवहीनता और राजनीतिक गलतियों ने उन्हें विरोधियों का निशाना बना दिया। उनके जीवन के इन रहस्यमय पहलुओं की सही समझ जरूरी है।"

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी राजीव गांधी निहित स्वार्थो की शत्रुता का केन्द्र बन रहे थे। पांच बड़े विकासशील राष्ट्रों के दक्षिण अमेरिकी सम्मेलन में पारित यह प्रस्ताव कि विकासशील राष्ट्र विश्व बैंक तथा आईएमएफ का कर्जा न चुकाने के विकल्प के अधिकारी हैं। अमेरिका तथा पूंजीवादी देशों की नींद उड़ा दी। अब राजीव गांधी अमेरिका के आर्थिक-सामरिक तंत्र के सबसे बड़े शत्रु के रूप में पहचान बना चुके थे। अपनी अंतिम यात्रा पर जब वह श्री पैरम्बूर के लिये जा रहे थे, तब उनको छोड़ने दिल्ली हवाई अड्डे पर कांग्रेस सचिव अनिल शास्त्री भी थे। अनिल शास्त्री ने उनसे कहा कि बधाई स्वीकार कीजिये। अब हम लोग चुनाव जीतने वाले ही है और आप प्रधानमंत्री बनेंगे। राजीव गांधी ने कहा वह तो ठीक है पर अमेरिका वाले कुछ काम करने दे तब तो। अनिल शास्त्री का कहना है कि वह राजीव गांधी की प्रतिक्रिया से सकते में आ गये। उनकी कुछ भी समझ मैं न आया कि राजीव ऐसा क्यों कह रहे थे।

अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, भारतीय कारपोरेट सेक्टर, सांप्रदायिक हिन्दुत्व, अन्तर्राष्ट्रीय खालसा मूवमेन्ट तथा तमिल उग्रवाद में निहित स्वार्थ राजीव गांधी के विरोधी थे। साथ ही कांग्रेस पार्टी में वीपी सिंह, अरूण नेहरू, वेंकटरमन, तारिक अनवर आदि भीतरघात के लिये उपयुक्त समय की तलाश कर रहे थे। नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, शरद पवार तथा नरसिम्हा राव जैसे नेता विरोधी तो नहीं थे लेकिन राजीव गांधी को लेकर बहुत उत्साहित भी न थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने कभी कहा था कि इन्दिरा गांधी कहेंगी तो मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, राजीव गांधी के कट्टर विरोधी थे। उन्हें लगता था कि अब नयी पीढ़ी सत्ता में आने वाली है और कभी भी उनकी छुट्टी हो सकती है। दल बदल निषेध बिल लेकर राजीव गांधी अपनी स्थिति को मजबूत समझ रहे थे। पर उन्हें पार्टी के अन्दर षड्यत्र के जाल का कोई अन्दाज़ न था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके कुछ विश्वासपात्र नौकरशाह उनके विरोधियों के साथ मिलते हैं।

राजीव गांधी को शायद यह भी अन्दाजा नहीं था कि उनके राजनैतिक मित्र कौन है। जब राष्ट्रपति जैल सिंह जोर शोर से उनकी सरकार को अध्यादेश के सहारे बर्खास्त करने का मन बना रहे थे और सेना अध्यक्षों से बात करना चाह रहे थे कुछ विपक्षी नेताओं, जैसे चन्द्रशेखर, हेमवती नन्दन बहुगुणा, मधु दण्डवते, आरके हेगड़े, ज्योति बसु, इन्द्रजीत गुप्ता आदि ने राष्ट्रपति जैल सिंह को कहा कि ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक होगा और यदि राष्ट्रपति ने ऐसा किया तो उन पर महाभियोग लगाकर पदच्युत करने के लिये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जायेगा। इससे जैल सिंह के बढ़ते कदम रूक गये।

राजीव गांधी के राजनैतिक जीवन की किताब के और भी तमाम अधखुले पन्ने है। आवश्यकता है कि उनको खोला और समझा जाये।

हमारीबढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास

राजीव माथुर

भारत की जीडीपी प्रति वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था से रणनीतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिश्रित मध्यम आय विकासशील सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। यह नाममात्र जीडीपी के हिसाब से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है; भारत की जीडीपी का लगभग 70% घरेलू खपत से संचालित होता है; देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बना हुआ है। निजी खपत के अलावा, भारत की जीडीपी सरकारी खर्च, निवेश और निर्यात से भी प्रेरित होती है।

सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना हुआ है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में अधिकांश श्रम शक्ति कार्यरत है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्माता है, जो वैश्विक विनिर्माण उत्पादन का 2.6% प्रतिनिधित्व करता है। भारत की लगभग 65% आबादी ग्रामीण है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देती है।

भारत की जीडीपी 8% से अधिक की दर से बढ़ रही है, जो इसे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। शहरीकरण की तेज़ रफ्तार के चलते 2036 तक शहरी क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70% योगदान होने की संभावना है। बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ, 2047 तक भारत एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है।

शहरीकरण

भारत में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। 2036 तक, इसके कस्बों और शहरों में 600 मिलियन लोग या कुल आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा होगा, जो 2011 में 31 प्रतिशत था, और शहरी क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70 प्रतिशत योगदान होगा।

इस शहरी परिवर्तन को अच्छी तरह से प्रबंधित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाए, जो हमारी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा। आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण रहने योग्य, जलवायु-लचीले और समावेशी शहरों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे।

चूंकि 2047 तक आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे का लगभग 70 प्रतिशत अभी तक नियोजित और निर्मित नहीं हुआ है, इसलिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि 2036 तक भारत को बुनियादी ढांचे में $840 बिलियन का निवेश करना होगा - औसतन $55 बिलियन या प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत।

भारत की ऊर्जा जरूरतें

भारत वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति है। ऊर्जा आवश्यकताओं में प्रति वर्ष 8 या उससे अधिक प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

वर्ष 2000 के बाद से ऊर्जा की खपत दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है, जो बढ़ती आबादी - जो अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है - और तेज़ आर्थिक विकास के दौर की वजह से बढ़ी है। वर्ष 2019 में लगभग सभी घरों में बिजली की पहुँच हो गई, जिसका मतलब है कि दो दशकों से भी कम समय में 900 मिलियन से ज़्यादा नागरिकों को बिजली का कनेक्शन मिल गया है।

ऊर्जा आवश्यकताओं और स्वच्छ ऊर्जा की ओर रुख

भारत की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। कोयला, तेल और बायोमास के साथ, सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों का बढ़ता उपयोग भारत के ऊर्जा भविष्य को स्थिरता की ओर ले जा रहा है।

भारत का निरंतर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण इसके ऊर्जा क्षेत्र और इसके नीति निर्माताओं पर भारी मांगें रखेगा। प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग वैश्विक औसत से आधे से भी कम है, और राज्यों और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच ऊर्जा के उपयोग और सेवा की गुणवत्ता में व्यापक अंतर हैं। ऊर्जा आपूर्ति की सामर्थ्य और विश्वसनीयता भारत के उपभोक्ताओं के लिए मुख्य चिंता का विषय है।

जबकि, भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है, आईईए (भारत ऊर्जा आउटलुक 2021) के अनुसार, प्राथमिक ऊर्जा की मांग लगभग दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन तेल के बराबर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2040 तक बढ़कर 8.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।

आज भारत की 80% से ज़्यादा ऊर्जा ज़रूरतें तीन ईंधनों से पूरी होती हैं: कोयला, तेल और ठोस बायोमास। कोयले ने बिजली उत्पादन और उद्योग के विस्तार को आधार बनाया है और ऊर्जा मिश्रण में सबसे बड़ा एकल ईंधन बना हुआ है। वाहन स्वामित्व और सड़क परिवहन के बढ़ते उपयोग के कारण तेल की खपत और आयात में तेज़ी से वृद्धि हुई है। बायोमास, मुख्य रूप से ईंधन की लकड़ी, ऊर्जा मिश्रण का घटता हुआ

हिस्सा बनाती है लेकिन अभी भी खाना पकाने के ईंधन के रूप में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के कवरेज का विस्तार करने की हाल की पहलों के बावजूद, 660 मिलियन से ज़्यादा भारतीय आधुनिक, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन या तकनीकों पर पूरी तरह से स्विच नहीं कर पाए हैं।
प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन कम होने के बावजूद भारत CO2 का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक है। विशेष रूप से इसके बिजली क्षेत्र की कार्बन तीव्रता वैश्विक औसत से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है, जो भारत के सबसे संवेदनशील सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों में से एक के रूप में उभरा है: 2019 में, जिसके लिए डेटा उपलब्ध है, परिवेश और घरेलू वायु प्रदूषण से संबंधित दस लाख से अधिक अकाल मौतें हुईं।

जल्द ही स्वच्छ ईंधन का अधिक से अधिक उपयोग अनिवार्य हो जाएगा। प्राकृतिक गैस और ऊर्जा के अन्य आधुनिक नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर, पवन, हाइड्रोजन आदि जैसे स्वच्छ हाइड्रोकार्बन अब लोकप्रिय होने लगे हैं। प्राकृतिक गैस की खपत 2021 में 174 MMSCMD से बढ़कर 2030 तक 12.2% की CAGR से बढ़कर 550 MMSCMD होने का अनुमान है।

साथ ही, भारतीय तेल रिफाइनरियां 2028 तक 56 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) जोड़कर घरेलू क्षमता को 310 एमटीपीए तक बढ़ा देंगी। भारत 2030 तक अपनी तेल रिफाइनिंग क्षमता को दोगुना करके 450-500 मिलियन टन करने की योजना बना रहा है।

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में, सौर पी.वी. का उदय शानदार रहा है; संसाधन क्षमता बहुत बड़ी है, महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं, तथा नीतिगत समर्थन और प्रौद्योगिकी लागत में कमी ने इसे नई ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे सस्ता विकल्प बना दिया है।

भविष्य में, निरंतर मजबूत आर्थिक विकास के कारण भारत की ऊर्जा मांग वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा मांग की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा, वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत में देश की हिस्सेदारी 2035 तक दो गुना बढ़ने का अनुमान है।

आर्थिक विकास और स्थिरता

भारत के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन चुनौतीपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संसाधन है, और कोयले की खपत वर्षों तक बढ़ती रहेगी। हालाँकि, हाल के दिनों में नवीकरणीय निवेश भी बढ़ा है, खासकर पीवी पक्ष में। देश का लक्ष्य भविष्य में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना भी है।

दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है और भारत पहले से ही अभूतपूर्व गर्मी और बाढ़ का सामना कर रहा है।

यद्यपि भारत उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में विश्व के प्रयासों का हिस्सा है और अपना योगदान दे रहा है, तथापि, आने वाले वर्षों में वैश्विक उत्सर्जन को सीमित करने में इसके योगदान को काफी बढ़ाना होगा।

भारत सरकार ने हाल ही में कुछ परिमाणात्मक नीतियों की घोषणा की है, जो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कुल मिलाकर, आने वाले वर्षों में भारत कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के लिए एक बड़ा बाजार है। बड़ी और योग्य जनशक्ति और उच्च तकनीक उद्योगों द्वारा पोषित, यह उम्मीद की जाती है कि यह तेजी से बढ़ती हुई मात्रा में एफडीआई को आकर्षित करेगा। भारत के लिए एक विशाल हरित केंद्र बनने की संभावना बहुत अधिक है और विकास के कई अवसर प्रदान करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों के बावजूद भारत अभी भी ऊर्जा संक्रमण के शुरुआती चरण में है। परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण और उद्योगों की कार्बन तीव्रता में तेजी से गिरावट देश के डीकार्बोनाइजेशन के प्रमुख उत्प्रेरक होंगे।

भारत को, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, जलवायु परिवर्तन को प्रबंधित करने की आवश्यकता और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को तेजी से अपनाने की देश की इच्छा और क्षमता के साथ अपने विकास को संतुलित करना होगा। हालांकि, आने वाले वर्षों में जो बात स्पष्ट दिखाई देती है, वह यह है कि भारत में ऊर्जा के मोर्चे पर अवसर अद्वितीय और विशाल हैं।

----------**लेखक के बारे में :**

पेशे से इंजीनियर राजीव माथुर सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गेल के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने ऊर्जा विशेषज्ञ, वे अब सलाहकार हैं।

जिनका शिल्प पूरी तरह समझा-परखा नहीं गया

आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और कथाकार, अपने जनवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध, साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित बाबा नागार्जुन (मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, जन्म :30 जून 1911 - मधुबनी, बिहार और निधन :5 नवंबर 1998 , दरभंगा, बिहार का आज जन्मदिवस है | उन्हें उनकी ही कुछ कविताओं के साथ स्मरण करते हैं

बाबा के के कथ्य पर तो बहुत बात हुई लेकिन उनके शिल्प पूरी शिद्दत से समझा-परखा नहीं गया। बाबा की प्रसिद्ध अधिकतर कविताएँ किसी छंद विशेष में हैं। : शासन की बन्दूक पूरी की पूरी कविता दोहा छंद में लिखी गई कविता है। पूरी कविता में छन्दगत कोई भी त्रुटि नज़र नहीं आती। मात्रा, लय, समान्त एकदम सही।जैसा कि बाबा ने खुद कहा है कि जब उन्हें छंद का ज्ञान हुआ तो लोगों को चिढ़ाने के लिए कविता करना शुरू किया। अतः छंद को साधने के बाद ही बाबा ने कविताई शुरू की। उनकी कुछ चुनिंदा कविताएं:

1.शासन की बन्दूक

खड़ी हो गई चाँपकर कंकालों की हूक नभ में
विपुल विराट-सी शासन की बंदूक

उस हिटलरी गुमान पर सभी रहें है थूकजिसमें
कानी हो गई शासन की बंदूक

बढ़ी बधिरता दस गुनी, बने विनोबा मूकधन्य-
धन्य वह, धन्य वह, शासन की बंदूक

सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूकजहाँ-
तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक

जली ठूँठ पर बैठकर गई कोकिला कूकबाल न
बाँका कर सकी शासन की बंदूक

2.अकाल और उसके बाद

कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद
धुआँ उठा आँगन से ऊपर कई दिनों के बाद
चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद
कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद।

क्या महिला आरक्षण काफ़ी है?

अमिताभ श्रीवास्तव

"मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए"

पिछली सरकार ने अपनी संख्या बल के आधार पर ज़ोर ज़बरदस्ती बहुत सारे बिल बिना विरोधी दलों की राय लिए पास करवा दिए।

इनको लेकर विपक्ष सरकार से इन क़ानूनों को दोबारा से डिबेट और बातचीत करने के लिए शोर मचा रहा है।लेकिन इस मारामरी में एक बिल जिसका किसी दल में विरोध करने की हिम्मत या इच्छा नहीं है वो है महिला आरक्षण बिल जिसे दोनों सदनों ने पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया।

ये बिल जो पहली बार १९९६ में लोक सभा में यूपीए द्वारा पेश किया गया था बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव के भारी विरोध के कारण पारित नहीं हो पाया।

स्थिति इतनी दयनीय थी कि एक बार, शायद २००८ में, उस समय क़ानून मंत्री एच आर भारद्वाज को बिल पेश करने वाले दिन कांग्रेस की महिला सांसदों के बीच बैठना पड़ा था क्योंकि यूपीए के समर्थक दलों राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी दलों के सदस्य उनके हाथ से बिल छीनने की कोशिश कर रहे थे।

एक बार तो कांग्रेस की दबंग नेता और मंत्री रेणुका चौधरी ने समाजवादी पार्टी के एक नेता को धक्का देकर भारद्वाज की रक्षा की थी।

उसके बाद से इस बिल को १९९८,१९९९ और २००८ में पेश करने की कोशिश हुई।वर्तमान में स्थिति ये है की बिल राज्य सभा से पारित है लेकिन लोक सभा में आने से पहले लोक सभा भंग हो गयी। लेकिन समय बदला और नौजवान नेताओं के विचार बदले।सपा के नेता आज अखिलेश यादव हैं,राजद में तेजश्वी यादव हैं और जनता दल (यू) के नए नेताब्रजवासी रंजन ,और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने संसद में इस बिल को पारित करने की माँग रखी थी।

भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव में महिलाओं के लिए इससे अच्छी कोई सौग़ात हो सकती जहाँ एक पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं का सम्मान और आदर नारों तक ही सीमित रह गया है।

यद्यपि पिछली लोक सभा में महिलाओं की संख्या आज़ादी के बाद सबसे अधिक(१४.३ %) थी लेकिन अगर विश्व के अन्य देशों से तुलना की जाए तो ये संख्या औसत २२ % से बहुत कम है।

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार महिलाओं के संसद में प्रतिनिधित्व के हिसाब से १९३ देशों की सूची में भारत का स्थान १४८ है।पिछले चुनावों में प्रियंका गांधी ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बड़े ज़ोर शोर से अभियान चलाया और 'लड़की हूँ लड़ सकती हूँ' का नारा प्रचलित किया लेकिन इसका फ़ायदा चुनाव परिणामों कांग्रेस को नहीं मिला।

ऐसा नहीं है की भारत में महिला आरक्षण का केवल विरोध ही हो रहा है।स्थानीय निकायों (पंचायतों) में उनको ३३ % आरक्षण है और कुछ राज्यों में तो उन्हें ५० % तक आरक्षण दिया चुका है।

मुद्दे की बात ये है कि क्या महिलाएँ अपनी संख्या बल के साथ न्याय कर पायी हैं? ऐसे में प्रयास की इग्ज़ेक्युटिव निदेशक इन्दु रानी सिंह का कहना सही है की अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो ये तो देखना होगा वो इसके लायक बनें।

मीडिया मैप से बात करते हुए इन्दु सिंह ने कहा,"महिला आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक तो गांधी जी थे।उन्होंने तब कहा था कि अगर भारत की आधी आबादी को घर में बैठा दिया जाएगा तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा"।

"लेकिन में इसके ये जोड़ना चाहूँगी कि सिर्फ़ संख्या बल की काफ़ी नहीं है हमें ये भी देखना है कि उनका ज्ञान का स्तर कैसा है तभी वो वो सही मुद्दों पर अपने विचार रख पाएँगी।इसके लिए ज़रूरी है की शिक्षण संस्थाओं और उच्च संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश की व्यवस्था हो।तभी महिला आरक्षण का पूरा लाभ मिल पाएगा" उन्होंने कहा।

मेरा इस विषय में एक व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं अधिक से अधिक शेयर करता हूँ।आज से लगभग पाँच वर्ष पहले प्रयास संस्था की ओर से हमें राजस्थान के कुछ इलाक़ों में महिला सरपंचों को उनकी ताक़त और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए भेजा गया था।

कहा गया था कि केवल महिला पंचायत की मुखियाओं को मिलना था और खाने की व्यवस्था भी केवल महिलाओं के लिए थी।लेकिन वहाँ सब मुखिया (लम्बे घूँघटों में) पंचों के साथ उनके पति या घर के बुज़ुर्ग साथ आए।उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ी क्योंकि उनका कहना था कि वो दूर दराज़ गावों से बिना ट्रैक्टर के नहीं पहुँच सकती थीं।हमारा ट्रेनिंग कैम्प तीन दिन चला और तीन दिनों तक उनके पति रोज़ आते और उसी कमरे में बैठते।मना करने पर लठ चलने की आशंका थी।

ख़ैर, लेकिन अच्छी बात ये हुई इस प्रकार से सशक्तिकरण देने के बाद भी कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ीं जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है।

हमने महिलाओं और पुरूषों दोनों को अलग अलग फ़ॉर्म दिए और उनसे बहुत से सवालों के साथ ये भी पूछा कि अगर उनको कुछ एकमुश्त धनराशि जनता के कामों के लिया दी जाए तो वो उसका कैसे उपयोग करेंगे।

पुरुषों ने लिखा कि वो गाँव में अखाड़े,बैंक्वेट हॉल या खेल स्टेडीयम खुलवाएँगे।वहीं लगभग सभी महिलाओं ने बताया कि वो उस पैसे से गाँव में प्रसूति केंद्र,अस्पताल या लड़कियों के स्कूल खुलवाएँगी जहाँ उनके लिए शौचालय की व्यवस्था होगी।

संसद में महिलाओं की अधिक संख्या होने का ज़िक्र एक संयुक्त राष्ट्र की रिसर्च में भी आया है जहाँ कहा गया कि जिन देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है वहाँ साफ़ पानी,पेन्शन,बच्चों के जन्म के समय पति की छुट्टी की व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाये जाते हैं।

लेकिन क्या ये काफ़ी है? जहाँ तक हमने देखा है कम से कम भारत में चुनी हुई महिलाएँ इन सार्वजनिक विषयों पर तो कभी कभी मुखर हो भी जाती हैं लेकिन जब बात आती है महिलाओं और बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार की तो वो पार्टी से अलग अपना कोई स्टैंड नहीं लेतीं।

अभी पिचकी सरकार के समय महिला पहलवालों के शारीरिक शोषण के ख़िलाफ़ धरने प्रदर्शन के प्रति जिस तरह महिला सांसदों ने अपनी उदासीनता दिखाई वह लोकतंत्र के लिए बेहद ख़तरनाक है।

ये अकेला मामला नहीं है।बिलक़िस बानो केस में बलात्कार और हत्या के आरोपियों के छोड़े जाने की बात हो,या थानों में महिलाओं की शिकायत लिखने के बजाय उन्ही के साथ बलात्कार की दुखद घटनाओं की हो महिला सांसदों की 'चुप' अप्रत्याशित है।

इसी कड़ी में वैवाहिक बलात्कार (marital rape) की बात करने की ज़रूरत है।आज से ठीक दस वर्ष पहले दिल्ली में ज्योति सिंह 'निर्भया' के साथ हुई बर्बरता ने दुनिया भर में भारत की राजधानी को 'रेप कैपिटल' का टाइटल दिला दिया था।

निर्भया की क़ुर्बानी का देश को ये फ़ायदा हुआ की भारत में बलात्कार की क़ानूनी परिभाषा को पूरी तरह आधुनिक बनाया गया और उसमें सज़ाओं का प्रविधान भी बढ़ा दिया गया।

जस्टिस वर्मा कमिटी के अन्य सुझावों में वैवाहिक बलात्कार को भी अपराध घोषित करने की सिफ़ारिश थी लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया है।उम्मीद थी कि पिछली लोक सभा में महिलाओं की अधिकतम संख्या होने से यह प्रस्ताव पारित हो जायेगा लेकिन अफ़सोस कि मामला उच्चतम न्यायालय तक जाने के बाद भी ना तो सरकार ने ना चुनी हुई महिला सांसदों ने इस विषय पर कोई स्टैंड लिया।

ज़रूरी नहीं की महिलाओं के बारे में केवल महिलाएँ ही सोचें।अच्छी सोच तो किसी की भी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की किरण नेगी के २०१२ की हत्या के आरोपियों की उच्चतम न्यायालय से रिहाई को लेकर पूर्व क़ानून मंत्री किरेन जिज़िजू से मिलना हुआ।

उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए वो दृढ़ संकल्प हैं और वे इसके लिए विशेष अदालतों के गठन की तैयारी कर रहे हैं जो तीन महीनों में फ़ैसला सुना देंगी।लेकिन उनके इस फ़ैसले से पहले उन्ही का तबादला हो गया।

मुहर्रम पर ताज़िया क्यों निकाला जाता है ।

डा. मुजफ्फर हुसैन गजाली

अरबी साल की शुरूआत मोहर्रम के महीने से होती है। इस्लामी इतिहास में इस माह का बहुत महत्व है। मुहर्रम की दसवीं तारीख यानि आशुरा का यहूदी और इसाई भी बहुत सम्मान करते हैं। वैसे तो दसवीं मुहर्रम के साथ कई घटनाऐं जुडी हैं लेकिन हज़रत ए हुसैन और उनके परिवार के बलिदान की वजह से इस दिन को याद किया जाता है। हज़रत हुसैन पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद के नवासे और हज़रत अली रज़ि के पुत्र थे।

इस्लाम में शासन प्रमुख को समाज के ज़िम्मेदार और बुद्धिजीवी मिल कर चुनते थे। शासन प्रमुख को खलीफा कहा जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ि का चुनाव इसी आधार पर हुआ था। हज़रत अली के बाद हज़रत अमीर माविया खलीफा बने। उन्होंने अपने बेटे यज़ीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अमीर माविया की मृत्यु के बाद यज़ीद ने अपने खलीफा होने की घोषणा कर दी। यह इस्लामी परम्परा के विरुद्ध था। सामुदायिक नेताओं और बुद्धिजीवीयो ने इस का विरोध किया। कूफ़ा (दमिश्क - आज का इराक) के बहुत से ज़िम्मेदारों ने हज़रत हुसैन को पत्र लिखे कि वह यहाँ आ जाएँ। हम उन्हें अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। पत्र मिलने पर हज़रत हुसैन ने हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील को वहां का जायज़ा लेने के लिए भेजा। कूफ़े के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही यज़ीद के डर से यातनाएं दे कर उनकी हत्या कर दी।

हज़रत मुस्लिम ने कूफ़े वालों की मेहमान नवाज़ी देख कर हज़रत हुसैन को यहाँ आने के लिए पत्र लिख दिया। हज़रत हुसैन कूफ़े के लिए रवाना हो गए लेकिन रास्ते में ही उन्हें कूफ़े के लोगों की वादाखिलाफी और हज़रत मुस्लिम के क़त्ल की सूचना मिली। वह वापस होना चाहते थे लेकिन हज़रत मुस्लिम के बेटों की ज़िद और खिलाफत को बादशाहत में बदलने से रोकने की प्रतिबद्धता ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह चाहते थे कि इस्लामी मूल्यों को बदलने से यज़ीद को रोकें। इसके लिए भले ही उन्हें कोई भी क़ीमत चुकानी पड़े। वह यज़ीद तक पहुंचें इस से पहले ही हज़रत हुसैन को यजीद की फौजों ने फरात नदी के किनारे कर्बला के स्थान पर रोक लिया। हज़रत हुसैन ने कूफ़े के गवर्नर इब्न जियाद को सन्देश भेजा की मुझे यज़ीद के पास तक जाने दिया जाये या मुझे मक्का वापस जाने दो या फिर न मालूम दिशा की ओर इस्लामी खिलाफत से दूर जाने दें। उनकी एक नहीं सुनी यज़ीद की फौज ने हज़रत हुसैन के काफिले को घेर लिया। उनके काफिले में कुल ७२ सदस्य थे। हज़रत हुसैन का खाना पानी बंद कर दिया गया। घर के सारे मर्द एक एक कर शहीद कर दिए गए। शहीद होने वालों में ६ माह का बच्चा अली असग़र भी शामिल था। हज़रत हुसैन के केवल एक बेटे ज़ैनुल आबेदीन बाक़ी बचे। वे उस समय बहुत बीमार थे उठ बैठ भी नहीं सकते थे। हर वर्ष सत्य, अहिंसा और इस्लामी मूल्यों की सुरक्षा के लिए बलिदान देने के लिए मुहर्रम पर हज़रत हुसैन को याद किया जाता है।

भारत में भी हज़रत हुसैन के परिवार की शहादत को याद किया जाता है। मुहर्रम पर ताज़िये निकाले जाते हैं मर्सिये पढ़े जाते हैं। कहा जाता है कि भारत में ताज़िये कि परम्परा तैमूर के ज़माने में शुरू हुई। तैमूर को हज़रत हुसैन और अहले बैत में आस्था थी। वह हर वर्ष मुहर्रम पर हज़रत हुसैन के रोज़े कि ज़्यारत को जाया करता था और दस दिन वहीँ गुज़रता था। एक वर्ष वह बहुत बीमार पड़ा जाने कि हालत में नहीं था। वह बीमारी में भी जाने के लिए बेचैन था। उसकी यह हालत देख कर दरबारियों ने हज़रत हुसैन के रोज़े (मक़बरे) का मॉडल तैयार कराया। तैमूर उसे देख कर खुश हुआ और उसने ज़्यारत के लिए जाने का इरादा तर्क कर दिया। मुग़ल काल में न केवल ताज़ियादरी में बढ़ोतरी हुई बल्कि साहित्य में मर्सिये की नई शैली का भी आरंभ हुआ।

क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है।
इस्लाम ज़िंदा होता है हर कर्बला के बाद।

अवध के नवाबों का मोहर्रम में खास योगदान रहा है। खासकर लखनऊ में आज भी मोहर्रम का शाही अंदाज इन्हीं नवाबों की देन है। जिसमें आसिफी इमामबाड़े से मोहर्रम की 1 तारीख को उठने वाली शाही मोम की जरी (करीब एक कुंतल मोम से बना ताजिया) का जुलूस हो या फिर 7 मोहर्रम को निकलने वाले शाही मेहंदी का जुलूस। मातमी धुन बजाते हुए बैंड, घोड़े, हाथी, फलों, मेवों से सजे हुए शाही थाल और साथ में मातम करते हुए मातमदार। सदियों से मोहर्रम की खास तारीखों पर निकलने वाले इन शाही जुलूसों को देखने के लिए हर मजहब के लोग जमा होते हैं।

लखनऊ से रिश्ता रखने वाली, चार साल की उम्र से शासत्रीय संगीत की शिक्षा लेने वाली सुनीता झिंगरन पूरे हिंदुस्तान में हुसैनी ब्रह्मण के नाम से जानी जाती हैं। इमाम हुसैन और उनके परिवार से उनकी मोहब्बत उनकी अवाज में दर्द बनकर बयां होती है। सुनीता कहती हैं कि, मैं पिछले 27 साल से मिर्सिया और सलाम पढ़ रही हूं। मैंने स्वर्गीय क़ारी हैदर हुसैन से बकायदा इसकी तालीम ली है। कई बार मुझसे भी सवाल होता है कि हिंदु ब्राह्मण होते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार से मोहब्बत क्यों? तब मैं उन्हें यह शेर सुना देती हूं कि

आंख में उनकी जगह दिल में मकां शब्बीर का
यह जमीं शब्बीर की यह आसमां शब्बीर का
जब आने को कहा था कर्बला से हिंद में
उसी रोज से हो गया हिंदोस्तां शब्बीर का।
(इमाम हुसैन को शब्बीर भी कहते हैं)

सुनीता कहती हैं कि इमाम हुसैन किसी एक क़ौम के नहीं बल्कि हर क़ौम के हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि

इंसान को बेदार तो हो लेने दो
हर क़ौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।

लेखक पत्रकार एवं स्तंभकार तथा यू एन एन के संपादक है।

मोहब्बत और मौसिकी की जुगलबंदी को खय्याम कहते हैं

ज़ेबा हसन

"**खु**द को खुशनसीब मानता हूं कि मैं हिन्दी सिनेमा का एक ऐसा वरक (पेज) हूं जो, जब भी फिल्मों के सुनहरे दौर की बात होगी पलटा जरुर जाऊंगा। बदले हुए इस दौर से मुझे मायूसी ज्यादा मिली है मगर यह बदलाव भी मेरे इस फिल्मी सफर का हिस्सा है।" वाकई खय्याम की कही यह बात उतनी ही प्रासंगिग है जितना उनका संगीत। खय्याम साहब जैसी हस्ती से मिलना भी किसी खुशनसीबी से कम नहीं था। साल 2009 में वह लखनऊ के एक सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे और उसी दौरान हुई मुलाकात में उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ दिलचस्प यादों को साझा किया था। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके गीतों की तरह उनकी उनकी यादें भी फूलों जैसी महकती हैं। आने वाली 19 अगस्त को खय्याम साहब की पुण्यतिथि है। इस लेख में उनकी कही बातों के जरिए हम उन्हें श्रधांजलि दे रहे हैं।

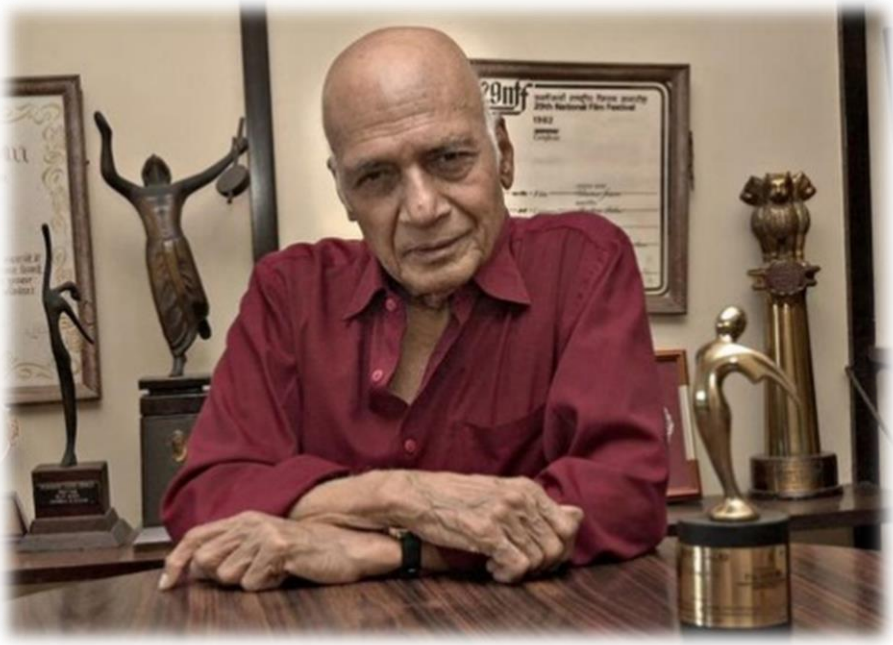

खय्याम का पूरा नाम है मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जालंधर जिले के नवाब शहर में जन्में खय्याम ने संगीत की इबादत की तो अपनी महबूबा और गायिका पत्नी जगजीत कौर के साथ ऐसी मोहब्बत की जिसकी मिसाल जल्दी नहीं मिलती। जब उनसे उनकी इस मोहब्बत के बारे में बात हुई तो उन्होंने अपनी कहानी को रोमांचित होकर सुनाया था। खय्याम कहते हैं कि वक्त आगे निकलता है, दौर बदलता है, लेकिन प्यार नहीं बदलता। वो तो आज भी उतनी ही सादगी से मुस्कुराती हैं, वहीं शहाना अंदाज है और यह उन्हीं का जहूरा है कि खय्याम आज खय्याम है। खय्याम साहब ने अपनी प्रेमिका और पत्नी जगजीत कौर की पहली झलक को याद करते हुए बताया कि वह पचास का दशक था, मैं स्ट्रगलर था। दादर का वो पुल जो ईस्ट से वेस्ट को ले जाता था, एक शाम उधर से गुजर रहा था और उसी राह से वह भी गुजर रही थीं। खद्दर का लिबास, बिना किसी सुर्खी, लाली के उस सादगी भरे हुस्न को बस देखता ही रहा। जैसे हर नौजवान के तसव्वुर में हमसफर की एक तस्वीर होती है, उस पल मुझे अहसास हुआ कि शायद यही वह तस्वीर है जो मेरी जिंदगी के खाली फ्रेम को पूरा कर सकती है।

स्टूडियो में हो गई मुलाकात

उन्हें देखने के बाद दिल की धड़कने तेज और मेरे पैरों की रफ्तार धीमी हो गई थी। मैं मुड़ मुड़ कर उन्हें जाता हुआ देख रहा था तभी वह हुआ जिसका मुझे गुमां भी नहीं था। वह एक दम से मुड़ीं और उनकी नजरे मेरी नजरों पर ठहरी तो जैसे वक्त मेरे लिए ठहर गया था। मुझे किसी की कही बात पर यकीन हो गया था कि अगर किसी को सच्चे दिल से देखो तो वो पलट कर देखता है। उस हसीन इत्तेफाक के बाद में अपने काम में मसरूफ हो गया लेकिन दिल में एक चिंगारी तो लग ही गई थी। एक दिन मैं रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में बैठा था। मुझसे किसी ने आकर बताया कि पंजाब की एक गायिका आईं हुई हैं, बहुत ही अच्छी आवाज है तुम उन्हें सुन लो। और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे सामने वही दिलकश शख्सियत बैठी है जिसकी एक झलक ने मेरे दिल के साज छेड़ दिए थे। वो हमारी पहली मुलाकात थी। बस यहीं से शुरू हो गया था बातों मुलाकातों का सिलसिला।

मुझे गर्व है अपनी पत्नी पर

वो इतने बड़े घर की बेटी और मैं स्ट्रगलर, लेकिन शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था और आखिर हमारी शादी हो गई। वो बड़ी बड़ी कोठियां, गाडियां सब कुछ छोड़ कर मेरी जिन्दगी में आईं थीं, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। उन्होंने खुद को मेरे रंग में ढाल लिया। प्यार करने वाले एक दूसरे को तोहफे देते हैं, लेकिन मैं एक स्ट्रगलर था उन्हें क्या तोहफा देता। लेकिन जब मुझे ऊपर वाले ने नवाजा मैंने अपनी मोहब्बत के लिए सारे एशोअराम मुहाइया किये। मुझे याद है मैंने जब उन्हें कार बतौर सरप्राइज गिफ्ट में दी थी, उस पल उनकी एक मुस्कुराहट ने सब कुछ बयां कर दिया था। मैं अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करता हूं। आज तक मैनें उन्हें कभी जगजीत जी के अलवा किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारा। देख लो आज हमको जी भर के...काहे को ब्याहे बिदेस...तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी...जैसे गीतों को गाने वाली अपनी पत्नी की आवाज का मैं आज भी दीवाना हूं।

मैं तो दूसरा के एल सहगल बनने आया था

जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के...फिल्म इंस्डस्ट्री में फैज साहब के इस कलाम से मैंने फिल्मी संगीत की दुनिया में कदम रखा था। जोहराबाई अम्बाले वाली जैसी बेहतरीन आवाज की मलिका के साथ गाने का मौका मिला था। नरगिस आर्ट कम्पनी की फिल्म थी और फिल्म का नाम था रोमियो जूलियट। इस इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए आया था वह भी केएल सहगल जैसा। मुझे दूसरा केएल सहगल बनना था लेकिन ऐक्टर तो मैं नहीं बन पाया। हां कुछ फिल्मों में काम जरूर किया था। ऐक्टर बनने के जुनून में संगीत का शौक कब मेरे लिए इबादत बन गया मुझे खुद पता नहीं चला। जिस दौर में मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया वो बेमिसाल और लाजवाब दौर था। हमसे

पहले काम करके जा चुके हमारे सीनियर्स ने भी जो काम किया था वो बेमिसाल था। फिर हमारा दौर आया हमारे कुलीग या फिर हमारे दोस्त, सबके लिए उनका काम इबादत हुआ करता था। मौसीकार, गुलूकार, डायरेक्टर सभी अपना काम पूजा की तरह किया करते थे। 66 साल हो गये मुझे इस इंडस्ट्री में। कितने दौर आए और मेरे सामने चले गये, लेकिन आज भी जब गोल्डन इरा को याद किया जाता है तो उसी दौर का जिक्र होता है जब हिंदी सिनेमा को खय्याम, राज कपूर, नौशाद, रफी जैसे फंकारों ने अपने हुनर से सजाया था।
अब तो गानों को हिट कराने के लिए लाखों का बजट होता है

आज के दौर की अगर बात करता हूं तो एक लाइन में यही कह सकता हूं कि गाने हो या फिल्में हर चीज बस एक शोर सी लगती है।सौ में 10 परसेंट ही काम हो रहा है। परदे पर औरतों की एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है जिसे देखकर कहने पर मजबूर हो जाता हूं कि ऐसा तो नहीं है हमारा हिन्दुस्तान। आज एक गाने की प्रमोशनल एक्टिविटी में करोड़ों रुपया लगाते हैं तब वो जाकर हिट होता है। हर फिल्म के आने से पहले शहर शहर घूम कर उनकी पब्लिसिटी की जाती है। करोड़ों का बजट तैयार किया जाता है सिर्फ प्रचार-प्रसार के लिए. जबकि हमारे दौर में गाने अपनी स्ट्रेंथ, अपने शब्दों और संगीत पर चलते थे। वह गीत हिट होते थे आज भी जब अच्छे गीतों की बात आती है तो लोगों की जुबान पर वही नगमे आते हैं। इंटरटेंमेंट के नाम पर कुछ भी परोस देना अच्छा नहीं है। इंटरटेंमेंट तो तब भी होता है जब परदे पर कलाकार रोता है और कहता है कि यह तो खुशी के आंसू हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बदलाव तो अच्छी बात है। टेकनिकली हम बहुत आगे जा चुके हैं। आज हम हॉलीवुड की फिल्मों से टक्कर ले रहे हैं। तरक्की का मतलब हमेशा अच्छा होना चाहिए, प्रोग्रेस का नाम हमेशा अच्छा पन होना चाहिए न कि ओछापन। फिल्में सोसायटी को क्या दे रही हैं? आज हर दूसरे दिन कभी किसी आयटम गीत की अशलीलता को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो कभी किसी फिल्म के नाम पर। कितना वक्त गुजार दिया इस इंडस्ट्री में लगता है अभी कल की ही बात है। हीर रांझा, फुटपाथ, मोहब्बत इसको कहते हैं, लाला रुख, शगुन, शोला शबनम, आखिरी खत, फिर सुबह होगी और उमराव जैसी शायराना फिल्में मैंने की हैं।

1927 में जन्में ख़य्याम 10 साल की उम्र में घर छोड़कर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में 5 साल रहते हुए उन्होंने संगीत सीखा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए थे। खय्याम ने 1947 से काम शुरू किया, पर तब पांच साल तक वो खय्याम नहीं, बल्कि शर्माजी के नाम से काम करते थे। तभी उन्हें पंजाब फिल्म प्रोडक्शन की 'हीर रांझा' में काम करने का मौका मिला। 1958 में रिलीज हुई फिल्म 'फिर सुबह होगी' से ख्य्याम को पहचान मिली।60 के दशक में खय्याम ने कई फिल्मों में हिट म्यूजिक दिया, जिनमें 'शोला और शबनम', 'फुटपाथ' और 'आखिरी खत' शामिल थीं। 70 के दशक में खय्याम की सबसे यादगार कंपोजिशन आई यश चोपड़ा के साथ, जिनकी शुरुआत हुई 1976 में 'कभी-कभी' से। इस फिल्म में खय्याम ने अपनी काबलियत साबित कर दी। 80 के दशक में खय्याम ने कुछ सबसे यादगार कंपोज़िशंस तैयार किए।1980 में आई फिल्म 'थोड़ी सी बेवफाई' इसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन खय्याम का सबसे मशहूर संगीत सामने आया मुजफ्फर अली की फिल्म 'उमराव जान' में। इस साउंडट्रैक के लिए उन्हें 1981 में नेशनल अवार्ड भी मिला। उमराव जान के लिए ख्य्याम को 1982 में उनका दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड मिला और ये सिलसिला फिल्म 'बाजार' के यादगार गानों के साथ आगे बढ़ता गया। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमे साल 2007 में खय्याम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार और हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार-प्राप्त हुआ। कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए खय्याम को वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पदम् भूषण प्रदान किया गया था। उनका एक बेटा था, प्रदीप, जिसकी 2012 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मदद करने की प्रकृति से प्रेरित होकर, उन्होंने कलाकारों और तकनीशियनों की ज़रूरत में मदद करने के लिए "खय्याम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट" ट्रस्ट शुरू किया था और इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले करीब दस करोड़ की सम्पत्ति दान कर दी थी। अपने अंतिम दिनों में, खय्याम विभिन्न आयु संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। 28 जुलाई 2019 को खय्याम को फेफड़ों में संक्रमण के कारण जुहू, मुंबई के सुजय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 19 अगस्त 2019 को 92 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। अगले दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

लेखक ने जागरण आईनेक्स्ट और अमर उजाला में पत्रकार के रूप में कार्य किया और एन बीटी में विशेष संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दीं। 2020 के बाद से वह फ्रीलांस पत्रकार रिता कर रही हैं।

संगीत के प्रति समर्पण:

ख़य्याम साहब का संगीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी जिंदगी की कहानी सुनते ही महसूस होता है कि संगीत उनके लिए इबादत थी। उन्होंने बॉलीवुड को अपने यादगार गानों से सजाया, जिनमें "कभी-कभी", "उमराव जान" और "फिर सुबह होगी" जैसे बेहतरीन संगीत शामिल हैं। उनकी संगीत यात्रा ने उन्हें भारतीय सिनेमा का अद्वितीय चेहरा बना दिया, जो हमेशा सुनहरे दौर की याद दिलाएगा।

अमर प्रेम कहानी:

खय्याम और उनकी पत्नी जगजीत कौर की मोहब्बत की कहानी आज भी प्रेरणादायक है। सादगी और सच्चाई से भरे उनके रिश्ते ने हर किसी को छू लिया। खय्याम साहब ने अपने जीवन साथी को कभी किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारा और उनकी प्रेम कहानी सच्चे प्यार की मिसाल बनी। उनका प्यार उनके संगीत की तरह अमर है, जो आज भी दिलों में बसता है।

चमकते सितारे जो हमें हँसा और रुला कर न जाने कहाँ चले गये।

प्रशांत गौतम

हिंदी सिनेमा के महान कलाकार अमजद खान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हम उनके जीवन और करियर के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। अमजद खान, जिन्हें उनकी अविस्मरणीय भूमिका 'गब्बर सिंह' के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं।

अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हुआ था। उनके पिता जयंत भी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, इसलिए अभिनय का हुनर उन्हें विरासत में मिला था। अमजद खान ने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की थी और जल्दी ही उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। 1975 में आई फिल्म 'शोले' में अमजद खान ने 'गब्बर सिंह' की भूमिका निभाई, जो भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित खलनायक भूमिकाओं में से एक बन गई। उनका डायलॉग "कितने आदमी थे?" आज भी लोगों की जुबान पर है। गब्बर सिंह की भूमिका ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया और उन्हें बॉलीवुड का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया।

अमजद खान ने केवल खलनायक की भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। 'लावारिस', 'परवरिश', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'कुर्बानी' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने यह साबित किया कि वे एक बहुमुखी अभिनेता थे। हर भूमिका में उन्होंने अपने अभिनय का जादू बिखेरा और दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई।

अमजद खान का निजी जीवन भी उतना ही दिलचस्प था जितना कि उनका फिल्मी करियर। उनकी शादी शीला खान से हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं – शादाब खान, अहलम खान, और सीमा खान। अमजद खान अपने परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उनके बच्चों के साथ उनका विशेष संबंध था।

अमजद खान का जीवन अचानक तब थम गया जब 27 जुलाई 1992 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु ने पूरे फिल्म उद्योग को स्तब्ध कर दिया और उनके प्रशंसकों के दिलों में गहरा शोक भर दिया।

अमजद खान की मृत्यु के बाद भी उनकी फिल्मों और उनके द्वारा निभाए गए किरदारों ने उन्हें अमर बना दिया है। आज भी 'शोले' और 'गब्बर सिंह' की यादें ताजा हैं। उनकी अनूठी आवाज़, बेहतरीन संवाद अदायगी और उनकी व्यक्तित्व की छाप आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।

अमजद खान की पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं और उनकी महान अभिनय यात्रा को याद करते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को जो योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जैसे कलाकार विरले ही होते हैं, जिन्होंने न केवल अपनी कला से बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी लोगों को प्रभावित किया।

अमजद खान, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। अमजद खान की हर भूमिका, हर संवाद और हर फिल्म हमें याद दिलाती रहेगी। अमजद खान की पुण्यतिथि पर हम अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। आप जहां भी हों, खुश हों।

कुश्ती के मैदान से फिल्मों तक, संघर्ष और जीत की कहानी

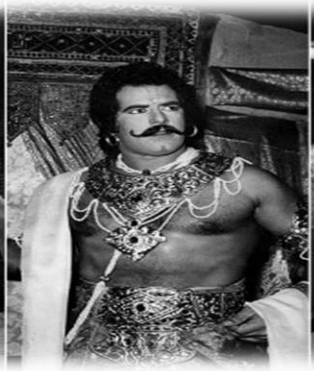

दारा सिंह, भारत के महान पहलवान और फिल्म अभिनेता, की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और सम्मान की एक मिसाल है। 12 जुलाई 2012 को इस महान व्यक्तित्व ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई यादें आज भी हमारे दिलों में जीवित है।

दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर जिले के धरमूचक गाँव में हुआ था। उनका असली नाम देनदार सिंह रंधावा था। बचपन से ही उन्हें कुश्ती का शौक था और उन्होंने इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का संकल्प लिया। वह मात्र 19 साल की उम्र में सिंगापुर चले गए जहाँ उन्होंने पेशेवर कुश्ती की शुरुआत की। उन्होंने दुनिया भर में कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

1959 में दारा सिंह ने 'कॉमनवेल्थ वर्ल्ड चैम्पियनशिप' जीती। इस जीत ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और वह भारत के पहले 'रस्टम-ए-हिंद' बने। उन्होंने अपने करियर में 500 से अधिक मुकाबले लड़े और

सभी में विजय प्राप्त की। दारा सिंह का फिल्मों की दुनिया में कदम रखना भी उनके कुश्ती करियर की तरह ही अद्वितीय था। 1952 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म 'संगदिल' थी। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में 'किंग कॉन्ग', 'फौलाद', 'सिकंदर-ए-आजम', 'रामायण' और 'महाभारत' शामिल हैं।

रामानंद सागर की 'रामायण' में हनुमान का किरदार निभाकर दारा सिंह ने एक अमर छवि बनाई। उनका यह किरदार इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें आज भी हनुमान के रूप में याद करते हैं।

दारा सिंह का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक था जितना उनका पेशेवर जीवन। वह एक सच्चे पारिवारिक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुरजीत कौर के साथ उनका विवाह 1961 में हुआ। उनके पांच बच्चे हैं - तीन पुत्र और दो पुत्रियाँ।

दारा सिंह सिर्फ एक पहलवान और अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि समाज सेवा में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2003 में राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया।

12 जुलाई 2012 को दारा सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। उनके निधन के बाद, उनके सम्मान में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनकी याद में कई संस्थाएँ स्थापित की गईं।

दारा सिंह का जीवन संघर्ष और सफलता की अनोखी कहानी है। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से कुश्ती और फिल्मों दोनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और समर्पण से हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनकी यादों को संजोते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं।

जीवन की चुनौतियों को हंसी में बदलने वाले कलाकार महमूद

जुलाई 23 भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में अगर किसी कलाकार ने हास्य को एक नई पहचान दी है, तो वह हैं महमूद अली, जिन्हें दुनिया महमूद के नाम से जानती है। 23 जुलाई 2004 को महमूद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें आज भी जीवंत हैं। महमूद की पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी को याद करते हैं।

महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज़ अली भी एक अभिनेता थे, लेकिन महमूद ने अपने करियर की शुरुआत बतौर ड्राइवर की थी। फिल्मों में छोटे-मोटे रोल करते हुए उन्होंने अपने हुनर को तराशा और धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। महमूद का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया।महमूद ने अपने करियर की शुरुआत 1950 के दशक में की। उन्होंने छोटे-छोटे किरदारों से शुरुआत की, लेकिन उनकी प्रतिभा ने जल्द ही दर्शकों का ध्यान खींचा। उनकी पहली बड़ी सफलता 1961 में आई फिल्म "छोटी बहन" से मिली, जहां उन्होंने एक हास्य किरदार निभाया। इसके बाद महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी।

महमूद ने हास्य को एक नया आयाम दिया। उनकी फिल्मों में हास्य केवल हंसी-मजाक तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके किरदारों में सामाजिक संदेश भी छिपे होते थे। "पड़ोसन", "भूत बंगला", "बॉम्बे टू गोवा" जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने लोगों को गुदगुदाया और सोचने पर मजबूर किया। महमूद की कॉमेडी में एक खास तरह की मासूमियत और गहराई थी, जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी।

महमूद ने अपने करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया और कई अवॉर्ड्स जीते। उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार में 25 बार नामांकित किया गया और उन्होंने 4 बार यह पुरस्कार जीता। महमूद की सफलता केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई।

महमूद का व्यक्तिगत जीवन भी काफी दिलचस्प था। उन्होंने दो शादियां की और उनके 8 बच्चे थे। उनके बेटे लकी अली भी एक जाने-माने गायक और अभिनेता हैं। महमूद का परिवार हमेशा उनके समर्थन में रहा और उनकी सफलता में उनका बड़ा योगदान रहा।

महमूद ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी लोगों को हंसाने का काम नहीं छोड़ा। वह अक्सर कहा करते थे कि वह लोगों के चेहरे पर हंसी देखना चाहते हैं। 23 जुलाई 2004 को महमूद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें और उनका काम आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।

महमूद की विरासत आज भी बॉलीवुड में जीवित है। उनकी फिल्मों और उनके किरदारों को आज भी याद किया जाता है। उनकी कॉमेडी ने जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाई, वह हमेशा याद रखी जाएगी। महमूद ने जिस तरह से अपने जीवन को संघर्षों के बाद सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वह आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है।

महमूद का जीवन और करियर एक मिसाल है कि अगर आपके पास प्रतिभा और मेहनत है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दी गई हंसी और खुशियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। महमूद हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, उनके किरदारों के माध्यम से, उनकी फिल्मों के माध्यम से और उनकी हंसी के माध्यम स

लेखक मीडिया मैप वेबसाइट (mediamap.co.in) के सह-संपादक है

पेरिस ओलंपिक्स में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन

प्रभजोत सिंह

प्रधानमंत्री के राज में दिन रात भारत के विश्व गुरु होने का दम भर जाता है। ना जाने मोदी का भारत किस क्षेत्र में विश्व गुरु है पर जहां तक पेरिस ओलिंपिक का सवाल है वह किसी मोहल्ले के गुरु का फिस्सडी विद्यार्थी ही लगा। 1.4 अरब लोगों का एक राष्ट्र, जो स्वयं को विश्व आर्थिक शक्ति होने का दावा करता है, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना अभियान खेलों में विश्व चैंपियन बनने के करीब भी नहीं पहुंच पाया।

हम खेलों में विश्व विजेता क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यह एक लाख रुपये का सवाल है जिसका जवाब देने में देश या तो अनिच्छुक है या फिर इनकार कर रहा है।

भारत के छह पदक - एक रजत और पांच कांस्य पदक - 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश द्वारा हासिल किए गए पदकों की बराबरी भी नहीं कर पाए। पिछले चार वर्षों में, हमने एकमात्र विश्व चैंपियन खिताब - भाला फेंक में नीरज चोपड़ा - खो दिया।

भारत ने इसे अपने पड़ोसी के हाथों खो दिया जो संघर्ष से त्रस्त है, जिसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।

भारत द्वारा भेजी गई 117 सदस्यीय टीम की तुलना में पाकिस्तान के दल में केवल सात लोग शामिल थे, जिनमें से केवल दो - भाला फेंक में नए ओलंपिक चैंपियन नदीम अशरफ और उनके कोच - को पाकिस्तान खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन है जो कई देशों से बड़े राज्यों में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य में लगभग 200 मिलियन लोग रहते हैं। पाकिस्तान बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी 230 मिलियन से अधिक लोगों के साथ दुनिया का पाँचवाँ सबसे अधिक आबादी वाला देश है।

भौगोलिक दृष्टि से भारत पाकिस्तान से लगभग चार गुना बड़ा है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने पांच बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें आखिरी बार 1980 में मास्को में कमजोर मैदान पर जीता गया स्वर्ण भी शामिल है, जबकि पाकिस्तान ने तीन बार जीत हासिल की है।

भारत ने ओलंपिक खेलों में केवल दो व्यक्तिगत स्व र्ण पदक जीते हैं। इनमें से पहला 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने जीता था और दूसरा टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता था।

कई अन्य एशियाई देश भारत से बहुत आगे हैं। चीन ने 40 स्वर्ण पदकों के साथ संयुक्त रूप से अमेरिका के साथ शीर्ष स्थान साझा किया। जापान और कोरिया खेल में अन्य एशियाई महाशक्तियाँ हैं। वे दुनिया के शीर्ष आठ खेल देशों में शामिल हैं।

इनके अलावा, इस्लामी गणराज्य ईरान, चीनी ताइपे, हांगकांग चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने हाल ही में संपन्न ओलंपिक खेलों में दो-दो स्वर्ण पदक जीते। इज़राइल, थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी एक-एक स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में स्थान बनाया।

हालांकि, भारत को इस बात से राहत मिली है कि पेरिस गए उसके 117 खिलाड़ियों में से 21 पदक जीतकर लौटे। इनमें से 16 पदक (कांस्य) हॉकी से और तीन निशानेबाजी से आए। भारत को कुश्ती में कांस्य पदक मिला।

भारत को सांत्वना पदकों से ही संतोष करना पड़ता है, आम तौर पर कांस्य और कभी-कभी रजत से, और शायद स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा या क्षमता की कमी है। एक सच्चे खेल राष्ट्र के रूप में, हम दूसरों के लिए स्वर्ण रखते हैं और रजत और कांस्य से ही संतोष करते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार प्रभजोत पॉल सिंह को मिला पेरिस ओलंपिक में सम्मान

प्रशांत गौतम

पेरिस लंदन के बाद तीसरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करने वाला दूसरा शहर बन गया। यह खेल पत्रकारों के वैश्विक निकाय AIPS के शताब्दी समारोह का स्थल भी था। शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में, AIPS ने अपने जर्नलिस्ट्स ऑन द पोडियम कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ खेल पत्रकारिता में 18 या उससे अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले अनुभवी खेल पत्रकारों और शीतकालीन ओलंपिक खेलों सहित 10 या उससे अधिक ओलंपिक खेलों को कवर करने वाले लोगों का सम्मान किया गया।

इस सम्मान में शामिल वरिष्ठ पत्रकार और खेल संपादक प्रभजोत पॉल सिंह, जो नियमित रूप से मीडियामैप के लिए लिखते हैं, 2024 ओलंपिक खेलों को कवर करने के लिए पेरिस गए। वह 23 जुलाई से 13 अगस्त तक पेरिस में रहें। सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कवर करने एवं वह भारतीय प्रवासियों, हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, टेनिस, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और भारतीय मूल के खिलाड़ियों के अलावा अन्य खेलों पर भी ध्यान केंद्रित करा ।

प्रभजोत पॉल सिंह, जिन्हें प्रभजोत सिंह के नाम से जाना जाता है, एक अनुभवी हरफनमौला पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काम करने का 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे अधिक प्रसारित अंग्रेजी दैनिक द ट्रिब्यून के साथ 37 साल का अनुभव भी शामिल है। उन्होंने 8 वर्षों से अधिक समय तक दुनिया के सबसे बड़े पंजाबी टीवी नेटवर्क पीटीसी न्यूज़ के कार्यकारी संपादक के रूप में भी काम किया था।

वरिष्ठ पत्रकार प्रभजोत पॉल सिंह का नाम आज न केवल भारतीय पत्रकारिता में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गर्व से लिया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उनकी विशेष भागीदारी और असाधारण योगदान के लिए उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान न केवल उनकी पत्रकारिता के प्रति समर्पण का प्रमाण है बल्कि भारतीय मीडिया की प्रतिष्ठा को भी वैश्विक स्तर पर ऊँचा उठाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रभजोत पॉल सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, लगन और पत्रकारिता के प्रति गहरी निष्ठा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत छोटे समाचार पत्रों से की, लेकिन अपनी लेखनी की ताकत और सत्यता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें जल्दी ही मुख्यधारा की पत्रकारिता में एक प्रमुख स्थान दिलाया।

उनका लेखन हमेशा से समाज के उपेक्षित वर्गों की आवाज को बुलंद करता रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिनमें सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, और देशभक्ति की भावना प्रमुख रहे हैं।

पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रभजोत पॉल सिंह ने भारतीय मीडिया का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग को अंतरराष्ट्रीय मीडिया जगत ने अत्यधिक सराहा। ओलंपिक के खेलों में उन्होंने न केवल खिलाड़ियों की उपलब्धियों को उजागर किया, बल्कि भारतीय खेल संस्कृति और युवा खिलाड़ियों की संघर्षपूर्ण यात्रा को भी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया।

उनकी रिपोर्टिंग का खास पहलू यह था कि उन्होंने खेल की तकनीकीताओं के साथ-साथ खिलाड़ियों की मानसिकता, उनकी व्यक्तिगत संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को भी प्रमुखता से दिखाया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियों में भावनात्मक गहराई और प्रेरणा का अनूठा मिश्रण था, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया।

प्रभजोत पॉल सिंह को पेरिस ओलंपिक में जो सम्मान मिला, वह न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, ब

लकि यह भारतीय पत्रकारिता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि भारतीय पत्रकारिता न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है।

यह सम्मान उन सभी युवा पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जो इस पेशे में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। प्रभजोत पॉल सिंह ने यह साबित किया है कि यदि आपके पास सच्चाई के प्रति समर्पण और समाज की सेवा का भाव है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

प्रभजोत पॉल सिंह के इस सम्मान के बाद, भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में और भी बड़े अवसरों की संभावना है। इस सम्मान ने यह भी दर्शाया है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय पत्रकारों के लिए बहुत सी नई दिशाएं खुली हैं।

उनका जीवन और उनकी उपलब्धियाँ उन सभी के लिए प्रेरणा हैं, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभजोत पॉल सिंह ने अपने समर्पण, कड़ी मेहनत, और उत्कृष्ट पत्रकारिता से यह साबित किया है कि यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो दुनिया का कोई भी मंच आपके लिए छोटा नहीं है।

वरिष्ठ पत्रकार प्रभजोत पॉल सिंह को पेरिस ओलंपिक 2024 में मिला सम्मान न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, बल्कि यह भारतीय पत्रकारिता के लिए भी एक गर्व का क्षण है। उनकी यह उपलब्धि युवा पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगी और उन्हें भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की दिशा में प्रोत्साहित करेगी। भारतीय मीडिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सफलता आने वाले समय में और भी नई ऊँचाइयों को छूने की उम्मीद जगाती है।

प्रभजोत पॉल सिंह का पेरिस ओलंपिक में विशेष सम्मान

वरिष्ठ पत्रकार प्रभजोत पॉल सिंह को पेरिस ओलंपिक 2024 में खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए विशेष सम्मान से नवाज़ा गया। 40 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ, उन्होंने भारतीय खेल संस्कृति और खिलाड़ियों की संघर्षपूर्ण यात्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे भारतीय मीडिया की प्रतिष्ठा को ऊँचाई मिली।

धूमधाम से मनाया गया इस वर्ष का अट्टहास सम्मान समारोह

रामकिशोर उपाध्याय

शनिवार, 13 जुलाई 2024 को हिन्दी भवन (निकट आईटीओ), विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली में माध्यम साहित्यिक संस्थान, लखनऊ एवं युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच, दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में बहु प्रतीक्षित 33 वाँ अट्टहास सम्मान समारोह सम्पन्न हो गया | कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर कप्तान सिंह ने की | मंचस्थ अतिथियों के स्वागत एवं उनके द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के बाद माध्यम साहित्यिक संस्थान के अध्यक्ष कप्तान सिंह ने संस्था की ओर से सभी आमंत्रित अतिथियों, सदस्यों एवं सम्मानित होने वाले साहित्यकारों का इस कार्यक्रम में स्वागत /अभिनन्दन किया|

माध्यम साहित्यिक संस्थान के अध्यक्ष कप्तान सिंह अध्यक्षता एवं माध्यम के महासचिव अनूप श्रीवास्तव के सानिध्य में देश के कोने -कोने से आये साहित्यकारों ,साहित्य प्रेमियों और व्यंग्य पाठकों से खचाखच भरे सभागार में जाने माने हास्य कवि पद्म श्री अशोक चक्रधर मुख्य अतिथि तथा ख्यात व्यंग्यकार डॉ हरि जोशी, ख्यात लेखक/उपन्यासकार/कथाकार बलराम ,सुभाष चंदर के अतिरिक्त वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉ.आलोक पुराणिक व के कर कमलों से देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार सुरेश कांत को शाल/माला तथा इक्कीस हज़ार की पुरस्कार राशि प्रदान कर 'अट्टहास शिखर सम्मान ' से सम्मानित किया गया | तत्पश्चात लखनऊ के व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी को शाल/माला तथा पांच हज़ार की पुरस्कार राशि प्रदान कर 'अट्टहास युवा रचनाकार सम्मान' से सम्मानित किया गया | सम्मानों की इस श्रंखला में वरिष्ठ व्यंग्यकार रामकिशोर उपाध्याय को शाल/माला तथा ग्यारह हज़ार की पुरस्कार राशि प्रदान कर हरिशंकर परसाई सम्मान' से सम्मानित किया गया | तत्पश्चात ख्यात कवयित्री -डॉ कीर्ति काले को सुश्री प्रमिला भारती की ओर से 'वाणी वाग्धारा सम्मान' एक पौशाक तथा ग्यारह हज़ार की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया | राजगोपाल सिंह वर्मा को डॉ हरिवंश राय बच्चन सम्मान (पुरस्कार राशि इक्कीस सौ रूपये),केवल कुमार'केवल' को डॉ शिव मंगल सिंह सुमन सम्मान (पुरस्कार राशि इक्कीस सौ रूपये), अरुण अर्णव खरे (कर्नाटक) डॉ प्रमिला भारती (दिल्ली) डॉ आभा सिंह (महाराष्ट्र),मधु श्रीवास्तव (उप्र) अभिलाषा (उप्र), सागर कुमार (छत्तीसगढ़), राजेश कुमार सिंह (उप्र) ओम प्रकाश शुक्ल (दिल्ली) संजय कुमार गिरी (दिल्ली) को उनकी साहित्य सेवाओं के लिए 'वाग्धारा सम्मान' से अलंकृत किया गया | श्री अश्वनी कुमार (पत्रकार,उप्र) एवं प्रो प्रदीप माथुर (पत्रकार,उप्र)को उनकी सुदीर्घ साहित्यिक /पत्रकारिता सेवाओं के लिए 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' प्रदान किया गया|

इस अवसर पर माध्यम के महासचिव अनूप श्रीवास्तव को विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा कवयित्री पूनम झा (दिल्ली) ने शाल और उपहार देकर सम्मानित किया |

13 जुलाई 2024 को हिन्दी भवन, नई दिल्ली में 33 वें अट्टहास सम्मान समारोह में साहित्यिक हस्तियों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष कप्तान सिंह की अध्यक्षता में, अशोक चक्रधर और डॉ हरि जोशी को 'अट्टहास शिखर सम्मान' मिला।

अट्टहास के प्रबंध संपादक अनूप श्रीवास्तव ,संपादिका शिल्पा श्रीवास्तव एवं कार्यकारी संपादक रामकिशोर उपाध्याय की गरिमामयी उपस्थिति में मासिक व्यंग्य पत्रिका 'अट्टहास' के पच्चीसवें वर्ष के पहले अंक, रामकिशोर उपाध्याय के व्यंग्य संग्रह 'दस हाथ वाला आदमी' , अलंकार रस्तोगी के व्यंग्य संग्रह – घातक कथाएं , डॉ आभा सिंह के व्यंग्य संग्रह – 'टूटी टांग' तथा केवल कुमार 'केवल' के व्यंग्य कविता संग्रह – 'पूँछ' का भव्य लोकार्पण हुआ | इस अवसर पर रायपुर,छत्तीसगढ़ से पधारे कार्टूनिस्ट सागर कुमार ने अनूप श्रीवास्तव, कप्तान सिंह,डॉ हरि जोशी, अशोक चक्रधर, रामकिशोर उपाध्याय,डॉ कीर्ति काले, अलोक पुराणिक,सुभाष चंदर,भारती पाठक तथा अश्विनी कुमार के शानदार कैरीकेचर भेंट किये | डॉ कीर्ति काले ने शानदार काव्य पाठ किया|

अट्टहास शिखर सम्मान प्राप्त करने के बाद अत्यंत भावुक सुरेश कान्त ने कुछ अधिक न बोलते हुए अट्टहास पत्रिका एवं चयन कर्ताओं का आभार व्यक्त कर अपना स्थान ग्रहण कर लिया | अलंकार रस्तोगी ने कहा

कि यह सम्मान प्राप्त करके उन्हें बहुत ख़ुशी हो रही है | यह उनका चौदह वर्ष पुराना सपना था जो आज साकार हो गया है | सम्मान की सार्थकता तभी है जब लेखक लेखन के प्रति अपने दायित्व को समझे |
रामकिशोर उपाध्याय ने कहा कि आज मुझे हरिशंकर परसाई सम्मान ग्रहण करते हुए आनंद के साथ गर्व की अनुभूति हो रही है कि पुरस्कार के लिए मेरा नाम हिंदी व्यंग्य के पुरोधा और व्यंग्य लेखन की प्रेरणा स्रोत हरिशंकर परसाई के साथ जुड़ गया है | मैं इसके लिये अनूप श्रीवास्तव एवं समस्त चयनकर्ताओं का हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ | व्यंग्य लेखन के विषय में हरिशंकर परसाई के कथन "जो क़ौमें भूखे मारे जाने पर सिनेमा में जाकर बैठ जाए,वह अपने दिन कैसे बदलेगी " को रेखांकित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि क्या हम हरिशंकर परसाई जैसा ऐसा लिख रहे है ? उन्होंने अट्टहास पत्रिका के समक्ष आर्थिक चुनौतियों का भी जिक्र कर सभी से इसके निरंतर प्रकाशन हेतु सहयोग की अपील भी की |
मुख्य अतिथि अशोक चक्रधर ने अपने चिर परिचित हंसोड़ संबोधन में कहा कि सर्वप्रथम मंच संचालकों का नाम लेना चाहिए जो इतना बढ़िया सञ्चालन कर रहे हैं

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति और विचार:

समारोह में मुख्य अतिथि अशोक चक्रधर और विशिष्ट अतिथि डॉ हरि जोशी ने अपने विचार साझा किए। चक्रधर ने पुरस्कार वितरण की निष्पक्षता की सराहना की और कहा कि 'अट्टहास सम्मान' की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है। डॉ जोशी ने व्यंग्यकारों को अपने लेखन में साहस और जोखिम उठाने की सलाह दी, और उपस्थित लेखकों को उनके श्रम के लिए बधाई दी।

| अट्टहास सम्मान एवं अन्य सम्मान प्राप्त करने वाले लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि माध्यम साहित्यिक संस्थान सम्मान देने में साहित्यकारों के साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है | सभी पुरस्कार-ग्रहीताओं को एक प्रकार का शाल और अन्य सामग्री प्रदान की गई ,यह इस बात का परिचायक है | उत्कृष्ट लेखन के लिए सम्मानित लेखकों को बंद लिफाफे की गई सम्मान की धन राशि के विषय में उन्होंने कहा कि न तो संस्था दरिद्र है और न ही हमारी भाषा हिंदी दरिद्र है | यदि पुरस्कार की राशि कम हो भी जाए तब भी अट्टहास सम्मान के स्तर में कोई कमी नहीं आएगी | यही अट्टहास सम्मान की विशेषता है जो अनूप श्रीवास्तव की असंदिग्ध लगन और तप का परिणाम है | उन्होंने सम्मान के लिए जो मानक तय किए हैं उनसे लेखक ही सम्मानित नहीं होते हैं बल्कि पुरस्कार प्रदाता भी सम्मानित होते हैं | लोकार्पित पुस्तकों के विषय में भी उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनायें प्रदान की |

विशिष्ट अतिथि डॉ हरि जोशी ने अंगेजी साहित्यकार बायरन की निम्नांकित पक्तियों --I should write, I would publish right or wrong /But culprit are ...., Satire are my song.का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यंग्यकार को अपने लेखन में 'कल्प्रिट' को ढूँढना चाहिए | उसके लिए यदि व्यंग्य लेखक को जोखिम भी उठाना पड़े तो वह भी उठाना चाहिए | इतने वर्षों तक इन लेखकों ने श्रम किया तब आज पुरस्कार मिला | निश्चित ही ये सभी लेखक बधाई के पात्र है | उन्होंने सम्मानित होने वाले लेखकों के प्रति भी आभार व्यक्त किया | वे अपना करीकेचर बनाने वाले कार्टूनिस्ट सागर कुमार का धन्यवाद करना भी नहीं भूले |

अट्टहास सम्मान प्राप्त करने पर सुरेश कान्त ,अलंकार रस्तोगी को बधाई देते हुए प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक सुभाष चंदर ने कहा कि 'ब से बैंक' उपन्यास से लेकर सुरेश कान्त ने व्यंग्य में बहुत काम किया है | कई अख़बारों और पत्रिकाओं में आपके लेख छप चुके हैं | अलंकार रस्तोगी के विषय में उन्होंने कहा कि उन्हें मॉडलिंग में जाना चाहिए था,लेकिन पत्नी ने नहीं जाने दिया | यदि वहां चले भी जाते तो व्यंग्य लेखन जितना बढिया कार्य ही करते | दस /बारह वर्ष पूर्व जब उनकी पहली पुस्तक का विमोचन करने गया था तब उन्हें एक सलाह दी थी कि खूब पढ़े तब लिखे | यही सलाह आज के युवा लेखकों को देना नहीं भूलता हूँ | उन्होंने ही निश्चित ही सलाह पर अमल किया है तभी उन्हें अट्टहास का यह अति महत्वपूर्ण सम्मान मिला |

वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉ आलोक पुराणिक ने सभी पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को बधाई देते हुए बताया कि गत दिनों वह एक सम्मान समारोह में गए थे जहाँ 178 लोगों को सम्मानित किया गया | आयोजकों ने बताया कि यहाँ उपस्थित सभी 176 साहित्यकारों के अतिरिक्त एक चाय वाला और एक समोसे वाले को भी सम्मानित किया है | आयोजकों ने यह भी कहा – ' आप कहो तो आपको भी सम्मानित किया जा सकता है,' कहकर उन्होंने इस तरह के सम्मान आयोजन पर

गंभीर चुटकी लीं |लेकिन अट्टहास सम्मान की बात बिलकुल अलग है | 'अट्टहास सम्मान वास्तव ISI मार्क सरीखे खरे हैं,' कहकर अपनी बात समाप्त की |

संस्था के महासचिव अनूप श्रीवास्तव ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब वह अस्सी वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त कर चुके हैं | अतः इस पत्रिका को संभालने के लिए लोग आगे आये ताकि यह निरंतर चलती रहे |

माध्यम साहित्यिक संस्थान और इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे कप्तान सिंह ने कहा -'जिन विद्वानों को आज पुरस्कृत किया गया है उन्हें मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने उत्कृष्ट सृजन किया है जिसके लिए हमारी इस संस्था ने आज उन्हें सम्मानित किया है | मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ | साहित्यकार की समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है | जब-जब समाज में विकृति आती है तब-तब साहित्यकार उसे बताने का कार्य करता है | साहित्यकार को जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए | व्यंग्य जीवन में चेतना लाता है | मैंने देश में काफी भ्रमण किया है लेकिन देश में स्थिति आज भी ठीक नहीं है | व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप जैसे विद्वान लिखेंगे तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा |' अंत में सभी आमंत्रित अतिथियों और अन्य सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों का आभार व्यक्त किया |

इस अवसर पर युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के कोषाध्यक्ष हीरा लाल का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया | चार घंटे तक चले इस सम्मान समारोह का मंच -संचालन माध्यम साहित्यिक संस्थान के उपाध्यक्ष आलोक शुक्ल और युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया

समारोह की रंगत और युवा साहित्यकारों की पहचान:

समारोह में युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के कोषाध्यक्ष हीरा लाल का जन्मदिन भी मनाया गया। चार घंटे तक चले इस भव्य आयोजन में मंच संचालन का कार्य आलोक शुक्ल और रामकिशोर उपाध्याय ने मिलकर किया। यह अवसर साहित्य प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय उत्सव था, जो साहित्यिक योगदान और सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहा।

आपस मे लड़ती नहीं,पूजा और नमाज़

सरयू की पीर आई गोमती के तीर पड़ी
भक्त पर भीर अब मुक्ति बीज बोना है
राजनीति में है नीति ,नीति में राजनीति
दृढ़ हुई धर्म नीति, वक्त नही खोना है.

नाहक हुए अधीर, बात बात में नज़ीर,
बहती है गंगा ,हाथ बहुतों को धोना है.
लक्ष्मणपुरी में तभी मिलाप हुआ,
फैसला भी गोमती के तीर होना है.

कृष्ण हुए थे जेल में,
फिर बंदी के राम,
भाग्य बड़ा भगवान से,हुए विधाता राम.
मुल्ला और महंत ही, झगड़े की आवाज़,
आपस मे लड़ती नहीं, पूजा और नमाज़.

-अनूप श्रीवास्तव

मीडिया मैप वेबसाइट पर

आखिर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की हो गयी

के. विक्रम राव

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा सत्र की वैधता को लेकर सवाल उठाना सही नहीं है। राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लंबित बिल पर फैसला लेना चाहिए। राज्यपाल पुरोहित राजनीति में पत्रकारिता से आए हैं। पहले वे इंदिरा-कांग्रेस के सदस्य थे, फिर भाजपा में प्रवेश किए। उनका आरोप था कि तमिलनाडु के राज्यपाल रहे तो चालीस से पचास करोड़ की रिश्वत लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपति नामित किए जा रहे हैं।

Porsche car case: How media should not report

Amod K Kanth

The Porsche car case in Pune has sparked controversy and debate. A 17-year-old boy, driving his father's luxury car, hit and killed two engineers on a bike. The boy was granted bail and ordered to write an essay on safe driving and perform community service.

आटा चक्की से डिजिटल साहित्यिक चक्की तक का

अनूप श्रीवास्तव

मेरे दोस्त को मुगालता है कि वे हर वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नही कर सकता क्योंकि उन्हें काम निपटाना आता हैं। उनकी आटा चक्की है जिसमे हर चीज पिस जाती है। सुबह सुबह चक्की के बाहर अपना सिर पकड़े बैठे थे। मैने पूछा,क्या हआ आज चक्की नही खोली।

U.S. Behind Her Ouster, Says Hasina

Syed Khalique Ahmed

Former Bangladesh President Sheikh Hasina Wajed has claimed that the US was involved in her ouster, alleging that she was asked to transfer St. Martin Island to the US.

Cat women and having children

Suranya Aiyar

As a woman who chose to leave her career to care for her children, I've faced criticism and derision from feminists who deem my decision as "boring" and "cowardly." Despite their claims of empowerment, many feminists have shown little understanding or solidarity towards women like me who prioritize family over career.

डिकोड हुई सिंधु सभ्यता लिपि - उठा रहस्य से पर्दा

शरद कुमार पांचाल

मेरे दोस्त को मुगालता है कि वे हर वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नही कर सकता क्योंकि उन्हें काम निपटाना आता हैं। उनकी आटा चक्की है जिसमे हर चीज पिस जाती है। सुबह सुबह चक्की के बाहर अपना सिर पकड़े बैठे थे। मैने पूछा,क्या हआ आज चक्की नही खोली।

Visit Our bilingual Website: www.mediamap.co.in

Subscribe Our Youtube Channel: Media Map Network

RNI No. : UPHIN/2016/68336

Scholars` Destination

A Holiday Home With A Difference

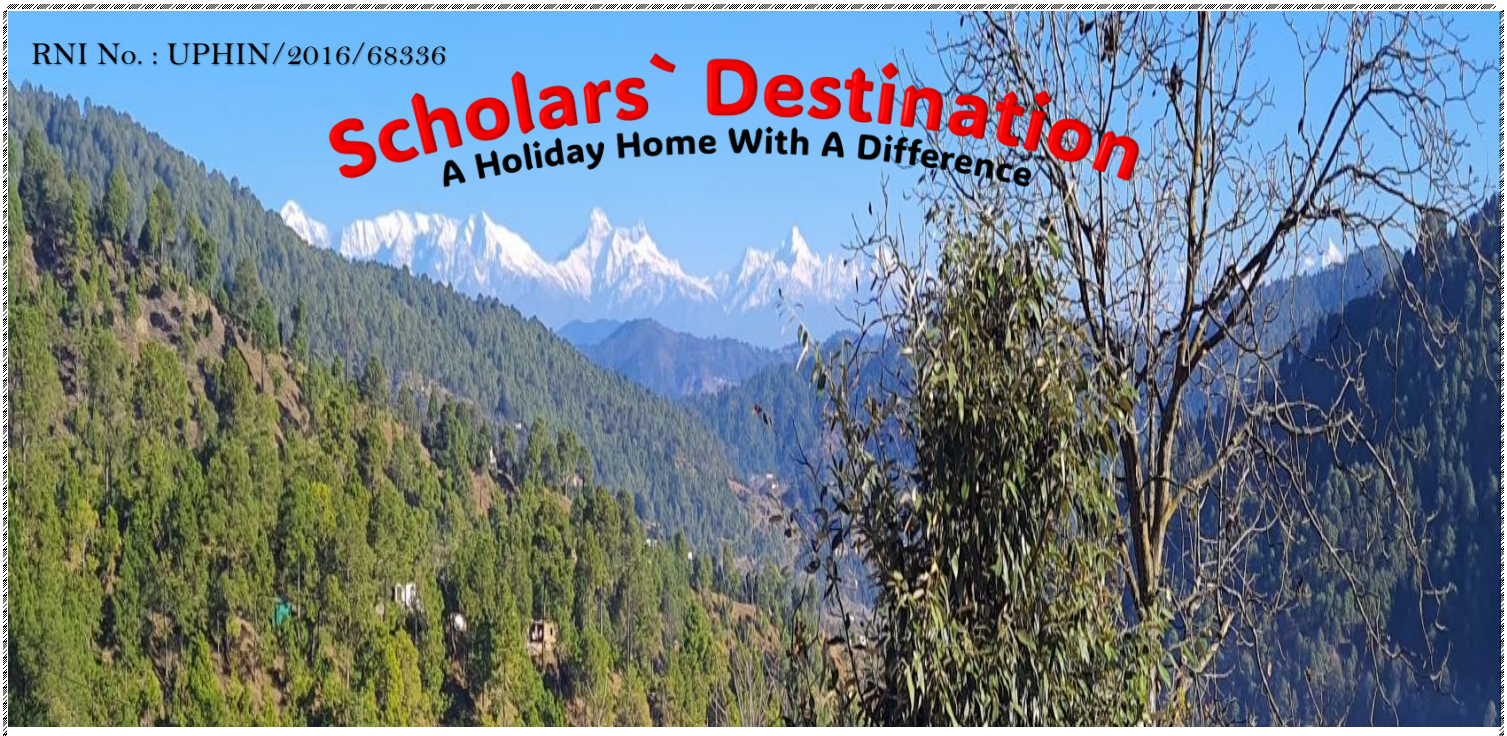

GEHNA, MUKTESHWAR DHAM, NAINITAL